राष्ट्रीय संस्करण

उच विदेश मंत्री से मिले राजनाथ, रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर >>3

वर्ष 9 अंक 190

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

दुर्गम स्थलों पर सैनिकों का सहयोगी बनेगा हनुमंता

सोनीपत : आइआइटी दिल्ली ने एक ऐसा उपकरण बनाया है, जिससे सैनिकों की पीठ पर लदे बैग का वजन 80 प्रतिशत तक कम महसूस होगा। • पेज-7

संपादकीय

चीन की दुखती रग दबाने का समय : चीनी आक्रामकता और धमकियों का सही जवाब यही होगा कि भारत सरकार तिब्बत पर चीन के अनैतिक कब्जे को चुनौती दे। **विजय क्रांति** का आलेख।

राहुल की सीमाएं, प्रियंका की संभावनाएं : वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान प्रियंका ने दिखाया कि वह राहुल गांधी की तुलना में अधिक प्रभावी वक्ता हैं। **राज कुमार सिंह** का दृष्टिकोण। • पेज 8

विमर्श

समावेशी विकास की ओर कदम : विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक ग्रामीण रोजगार नीति को एक नए सोच के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है। **डा. सुशील कुमार सिंह** का विश्लेषण।

गोवा स्वतंत्रता संग्राम की अनदेखी : गोवा को आजाद हुए छह दशक से अधिक समय बीत चुका है, किंतु यह मुक्ति पर्व आज भी मुख्यत: गोवा तक ही सीमित रह गया है। **अभिषेक रंजन सिंह** का आलेख। • पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

मनोरंजन की दुनिया का

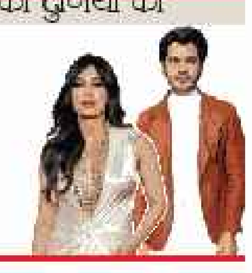

मन का काम कर सकें यही है असल ताकत

विवादों से बेअसर धुरंधर

• पेज-13

ओमान के साथ व्यापार समझौता, कृषि व रोजगारपरक सेक्टर का बढ़ेगा निर्यात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- किसानों व एमएसएमई को समझौते से होगा काफी फायदा, रोजगार में बढ़ोतरी होगी
- सर्विस सेक्टर का भी बढ़ेगा निर्यात, ओमान जाकर सेवा देने का मिलेगा अवसर
- आयुष मेडिसिन के लिए भी खुला दरवाजा, आयुर्वेद को पैर पसारने का मौका मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में गुरुवार को खाड़ी देश ओमान के साथ भारत ने कंप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) पर हस्ताक्षर किए। सीपा के अमल में आते ही ओमान निर्यात होने वाले 99 प्रतिशत आइटम पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। अभी ओमान निर्यात होने वाले आइटम पर कम से कम पांच प्रतिशत का शुल्क लगता है। अगले तीन माह के भीतर सीपा पर अमल शुरू होने की संभावना है और इसके लागू होने के पहले दो साल में ओमान में होने वाले निर्यात में दो अरब डालर का इजाफा हो सकता है।

भारत-ओमान के बीच गत वित्त वर्ष 2024-25 में 10.61 अरब डालर का कारोबार किया गया था। इनमें भारतीय निर्यात की हिस्सेदारी 4.6 अरब डालर की रही। भारत ने ओमान से 6.5 अरब डालर का आयात किया। मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल आइटम का आयात करने से ओमान के साथ हमारा व्यापार घाटे में है। सीपा के तहत भारत ने ओमान के लिए मुख्य रूप से पेट्रो केमिकल्स उत्पाद, प्रोलिपोपलिन, प्रोलिएथनिल, मार्बल, धूप और खजूर जैसे आइटम पर शुल्क में राहत दी है। इस कारण ये वस्तुएं भारत में सस्ती हो जाएंगी। भारत ने कृषि, डेयरी, चाय, काफी, रबर, सोना-चांदी, ज्वैलरी, टेक्सटाइल जैसे आइटम के आयात के लिए अपने द्वार नहीं खोले हैं। खजूर आयात के लिए भी कोटा तय किया गया है।

सीपा से मुख्य रूप से ओमान में कृषि व प्रोसेस्ड खाद्य वस्तुओं के साथ इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर आइटम, टेक्सटाइल, जेम्स व ज्वैलरी, केमिकल्स, प्लास्टिक जैसे रोजगारपरक सेक्टर के निर्यात में वृद्धि होगी। इससे भारतीय किसान व एमएसएमई सेक्टर को काफी लाभ मिलेगा क्योंकि रोजगारपरक सेक्टर के निर्यात में एमएसएमई सेक्टर की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। सीपा में सर्विस सेक्टर व प्रोफेशनल्स को आसानी से सेवा देने का मौका भी शामिल किया गया है जिससे इन दोनों सेक्टर में भी भारत को लाभ मिलेगा। पहली बार किसी देश ने व्यापार समझौते के तहत आयुष इलाज व मेडिसिन के लिए अपना दरवाजा खोला है। इससे ओमान में आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा को पैर पसारने का मौका मिलेगा।

मस्कट में ओमान के प्रधानमंत्री सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष गुरुवार को व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करते वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ। आइएएनएस

समझौते से इन कृषि आइटमों के निर्यात को मिलेगा लाभ

बटर, चीज, घी, दही, चावल, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज, काजू, केला, सेब, आम, संतरा, अनार, टमाटर, प्याज, लहसुन, गोभी, भिंडी, कद्दू, आलू, शहद, सोयाबीन और अन्य खाद्य तेल।

ओमान ने भी मोदी को दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान

ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द फर्स्ट क्लास आफ द आर्डर आफ ओमान' प्रदान किया। (पेज-11)

प्रोफेशनल्स को अधिक मौकों से ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित होगी

प्रोफेशनल्स को अधिक मौका मिलने से ओमान से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी। अभी ओमान में सात लाख भारतीय हैं और सालाना दो अरब डालर की विदेशी मुद्रा वतन भेजते हैं। ओमान सालाना 38-40 अरब डालर का वस्तु आयात करता है और अब जीरो शुल्क होने पर भारत को अपना निर्यात बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा। ओमान सालाना छह अरब डालर का तो सिर्फ कृषि पदार्थों का ही आयात करता है जिसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 10 प्रतिशत है। अब फल, हरी सब्जी, प्रोसेस्ड आइटम, मांस, अनाज, समुद्री उत्पाद, डेयरी जैसे आइटम पर शुल्क समाप्त होने से इनका निर्यात बढ़ेगा।

मानव बम बनने की तैयारी कर रहा था जैश आतंकी यासिर, गिरफ्तार

लाल किला ब्लास्ट केस में साजिश रचने में निभाई मुख्य भूमिका, एनआइए ने दबोचा

अब तक नौ आतंकी हो चुके हैं गिरफ्तार, छह राज्यों की पुलिस के साथ जांच में जुटी है एनआइए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

लाल किला के बाहर हरियाणा नंबर की आइ-20 कार में मानव बम बनकर धमाका करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक और आतंकी यासिर अहमद डार को दिल्ली के एक मुस्लिम बहुल इलाके से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में गिरफ्तार यासिर नौवां आतंकी है।

एनआइए की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि यासिर भी लाल किला कार धमाके में मारे गए आतंकी डा. उमर की तरह मानव बम बनने की तैयारी कर रहा था। वह भी आत्मघाती हमला करने की फिराक में था, पर जब सफेदपोश माड्यूल के कई आतंकी पकड़े गए तो वारदात वाले दिन (10 नवंबर) डा. उमर को मानव बम बनकर धमाका करने की नसीहत यासिर ने ही दी थी। उस दिन उसने खुद को शोपियां (श्रीनगर) में होने के कारण अफसोस जाहिर किया था। जांच में यह भी पता चला है कि यासिर इस मामले में दूसरे आरोपितों डा. उमर उन नबी (बम धमाका करने वाला आतंकी) और मुफ्ती इरफान के संपर्क में था। एनआइए ने आरोपित यासिर अहमद डार को पटियाला कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है।

एनआइए का कहना है कि फरीदाबाद में सफेदपोश माड्यूल (डाक्टरों का आतंकी दस्ता) के कई आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो डा. उमर ने आनन-फानन में फरीदाबाद से दिल्ली आकर बीती 10 नवंबर को लाल किला के बाहर मानव बम बनकर धमाका कर दिया था। वैसे इस माड्यूल की योजना फिलहाल अभी धमाका करने की नहीं थी। अभी वे केवल प्लानिंग ही कर रहे थे। यदि यासिर भी उस समय एनसीआर में होता तब वह भी मानव बम बनकर एनसीआर को दहला सकता था। लाल किला ब्लास्ट मामले में 15 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 22 लोग घायल हुए थे।

लाल किला ब्लास्ट का आरोपित यासिर अहमद डार (काले कपड़े से ढंका चेहरा) को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। जागरण

जम्मू-कश्मीर के शोपियां का है निवासी है यासिर

एनआइए का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के शोपियां निवासी यासिर अहमद डार ने दसवीं से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी और बागवानी के काम से जुड़ा था। लाल किला बम धमाके में उसकी अहम भूमिका थी। विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए एनआइए आतंकी हमले के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। इस माह के शुरुआत में टीम ने जम्मू-कश्मीर और उप्र में कई संदिग्धों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली। कई डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। इससे पहले मुख्य आरोपित डा. मुजम्मिल शकील गनी और डा. शाहीन सईद के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई थी, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी कांप्लेक्स और फरीदाबाद में अन्य जगहों पर थे।

'सेवानिवृत्ति से पहले जजों का कई आदेश पारित करना, आखिरी ओवर में छक्के मारने जैसा'

- सीजेआइ ने कहा, सेवानिवृत्ति से ठीक पहले कई सारे आदेश पारित करने का बढ़ रहा चलन

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले जजों द्वारा कई सारे आदेश पारित करने के बढ़ते चलन पर आपत्ति जताई है। शीर्ष अदालत ने इसकी तुलना किसी क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर में बल्लेबाज के छक्के मारने से की।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ मप्र के एक प्रधान एवं जिला जज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कुछ संदिग्ध न्यायिक आदेशों के कारण उन्हें तय सेवानिवृत्ति से 10 दिन पहले निलंबित कर दिया गया था। पीठ ने बुधवार को कहा, ''याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले छक्के मारने शुरू कर दिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण चलन है। वे इस पर और विस्तार से बात नहीं करना चाहते।''

मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे, पर कथित तौर पर दो न्यायिक आदेश पारित करने के कारण उन्हें 19 नवंबर को निलंबित कर दिया गया था। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील विपिन सांघी ने कहा, उनका सर्विस रिकार्ड बेदाग रहा है। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में लगातार उच्च रेटिंग मिली है। तर्क दिया कि न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध सिर्फ न्यायिक आदेश पारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। कहा, ''एक अधिकारी को उन न्यायिक आदेशों के लिए कैसे निलंबित किया जा सकता है जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती हैऔर उच्च न्यायपालिका उन्हें सुधार सकती है?'' पीठ ने इससे सैद्धांतिक सहमति जताते हुए कहा, आमतौर पर गलत आदेशों के लिए किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

जस्टिस सूर्यकांत।

सेवानिवृत्ति से 10 दिन पहले निलंबित मध्य प्रदेश के जिला जज की याचिका पर की टिप्पणी

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, अगर आदेश स्पष्ट तौर पर बेईमान हो तो क्या होगा? पेज>>5

अफ्रीकी चुनौती

आज का मैच (पांचवां टी-20)

भारत vs दक्षिण अफ्रीका

शाम 7:00 बजे स्थान: अहमदाबाद

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क/जियो हाटस्टार

नहीं रहे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू आफ यूनिटी बनाने वाले राम सुतार

नोएडा : प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार नहीं रहे। गुरुवार को 100 वर्ष, 10 माह की आयु में नोएडा स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। सुतार ने अपने जीवनकाल में 1000 से अधिक मूर्तियों को आकार दिया। देश-विदेश के अनेक शहरों में स्थापित उनकी कृतियां भारतीय संस्कृति व मूल्यों की पहचान हैं। गुजरात में उनकी बनाई सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची 'स्टैच्यू आफ यूनिटी' विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। राम वी सुतार पद्मश्री, पद्मभूषण समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके थे। (पेज-2)

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में धोखाधड़ी, 71 अपात्रों को मिला लाभ

अभिषेक राय • नईदुनिया

- तीन लाख से अधिक वार्षिक आय वालों को आवंटित हुए आवास
- विस में पेश कैग रिपोर्ट में राजफाश, अधिकारी-कर्मियों को दिया गया लाभ

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत आवास आवंटन में गंभीर अनियमितताएं सामने आयीं हैं। पात्रता मानकों की अनदेखी करते हुए तीन लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले 71 लोगों को आवास आवंटित किए गए। इनमें से 51 लाभार्थी स्थानीय निकायों और विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी हैं।

विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की वर्ष 2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह राजफाश हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, पीएम आवास योजना में स्पष्ट प्रविधान है कि तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले ही किफायती आवास व हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का लाभ उठा सकते हैं। इसके बावजूद चार बिलासपुर, रायपुर, कोरबा व प्रेमनगर नगर पंचायत में ऐसे 71 लोगों का चयन किया गया, जिनकी आय तय सीमा से अधिक थी। अफसरों- कर्मियों ने वार्षिक आय की झूठी जानकारी देकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत योजना का लाभ उठाया। इस बात की जानकारी होने के बावजूद अयोग्य हितग्राहियों को लाभ दिया गया।

चार भागों में बांटकर दिया जाता है लाभ पेज>>4

हंगामे के बीच लोकसभा से जी राम जी बिल पास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विपक्ष ने आसन के सामने बिल की प्रतियां फाड़कर उड़ाई, शिवराज बोले 'गुंडाराज'
- लोस के बाद बिल रास में पेश, विपक्ष ने की संसदीय समिति में भेजने की मांग

विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत जी राम जी विधेयक को आठ घंटे की चर्चा के बाद राजनीतिक टकराव और भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। चर्चा में 99 सदस्यों ने भाग लिया। विपक्ष ने नाम के विरोध में वेल में आकर हंगामा किया। आसन के सामने विधेयक की प्रतियां फाड़कर उड़ाईं। विपक्ष के इस व्यवहार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाद में भाजपा कार्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस कर 'गुंडाराज' करार दिया और कहा कि विपक्ष सिर्फ नाम पर राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार काम पर विश्वास करती है। बाद में सरकार ने विपक्ष के विरोध के बीच विधेयक को राज्यसभा में पेश कर दिया। विपक्ष इसे संसदीय समिति में भेजने और महात्मा गांधी का नाम जोड़ने की मांग कर रहा है।

विधेयक पर विपक्ष पहले दिन से आक्रामक था। गुरुवार को भी कांग्रेस की ओर से कोशिश की गई कि इसे स्थायी समिति को भेज दिया जाए। यह संयोग भी हो सकता है कि पहले दिन विधेयक का औपचारिक विरोध करने वाली प्रियंका काले कपड़े में थीं। योजना का नाम बदलने का विरोध करते हुए विपक्षी सदस्य भाजपा को गांधी विरोधी ठहराने की कोशिश करते रहे। हालांकि यह आश्चर्यजनक था कि जिस विधेयक का विपक्ष विरोध कर रहा था, उसके पारित होने के दिन विपक्ष की अधिकतर सीटें खाली थीं, पर वेल में पूरा विरोध हुआ।

शिवराज सिंह ने अपने जवाब में कहा, कांग्रेस ने सिर्फ महात्मा गांधी के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया, जबकि मोदी सरकार बापू के आदर्शों पर चल रही है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर और सरकारी भ्रष्टाचार के जरिये बापू के आदर्शों की हत्या की, जबकि मोदी सरकार ने गांव, गरीब व मजदूर को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई हैं। नरेगा की शुरुआत में महात्मा गांधी का नाम नहीं था। 2009 में चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस को गांधी याद आए और चुनावी लाभ के लिए उनका नाम जोड़ा गया। कांग्रेस ने मनरेगा को गंभीरता से नहीं चलाया, जबकि मोदी सरकार ने प्रभावी ढंग से लागू किया और रिकार्ड बजट उपलब्ध कराया।

लोकसभा में गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान के सामने विपक्ष द्वारा फाड़कर फेंके गए बिल की कापी के टुकड़े। एएनआइ

नाम बदलने की सनक कांग्रेस में रही है पेज>>3

मोदी सरकार का लक्ष्य किसी परिवार का महिमामंडन नहीं, जनकल्याण है पेज>>3

फिल्म की धूम

धुरंधर ने पाकिस्तानियों के सामने उजागर किया मुल्क का आतंकी चेहरा

कंधार कांड व मुंबई हमले पर आधारित फिल्म पाकिस्तानी शासन को नहीं आई रास, फिल्म ने जिस तरह की सनसनी पैदा की है, उससे आइएसआइ के लिए खड़ी हुई समस्या, दो हफ्ते में फिल्म को पाक में 20 लाख बार अवैध तरीके से डाउनलोड किया गया

नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तान और कुछ खाड़ी देशों द्वारा धुरंधर पर लगाए गए प्रतिबंध का फिल्म की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस फिल्म ने जिस तरह की सनसनी पैदा की है, उससे पाकिस्तान में आइएसआइ के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 1999 का कंधार विमान अपहरण, मुंबई हमले (26/11) और ल्यारी गिरोह के संघर्षों पर आधारित यह फिल्म पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान को रास नहीं आई है और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। हालांकि, आइएसआइ का डिजिटल प्लेटफार्म पर नियंत्रण खत्म हो चुका है और फिल्म ब्लाक करने के प्रयास विफल रहे हैं। धुरंधर ने पाकिस्तानियों के सामने मुल्क का आतंकी चेहरा उजागर कर दिया है।

महज दो हफ्ते में पाक में इस फिल्म को 20 लाख बार अवैध तरीके से डाउनलोड किया गया है। धुरंधर पाक में सबसे ज्यादा पायरेटेड फिल्म बन गई है, जिसने रजनीकांत अभिनीत रोबोट 2.0 व शाहरुख की रईस को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में प्रतिबंध से फिल्म निर्माताओं को 50-60 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ होगा, पर पाक के आतंकी राज्य होने का संदेश पूरे देश में पहुंच गया है। भले ही पाकिस्तानियों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका देश क्या है, पर भारत के लिए यह मनोवैज्ञानिक जीत है। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान विशेष रूप से ल्यारी के चित्रण से खफा है। वह इस नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए इतना बेताब है कि उसने ल्यारी पर ऐसी फिल्म बनाने का फैसला किया है, जो उस जगह को सकारात्मक रूप में दिखाए।

सिंध प्रांत के वरिष्ठ सूचना मंत्री शरजील इनाम मेमन ने एक्स पर लिखा, भारतीय फिल्म 'धुरंधर' पाकिस्तान, विशेष रूप से ल्यारी को निशाना बनाकर किए जा रहे नकारात्मक प्रचार का उदाहरण है। ल्यारी हिंसा का नहीं संस्कृति, शांति, प्रतिभा व दृढ़ता का प्रतीक है। अगले माह 'मेरा ल्यारी' फिल्म रिलीज होगी, जो ल्यारी का असली चेहरा दिखाएगी-शांति, समृद्धि और गौरव।

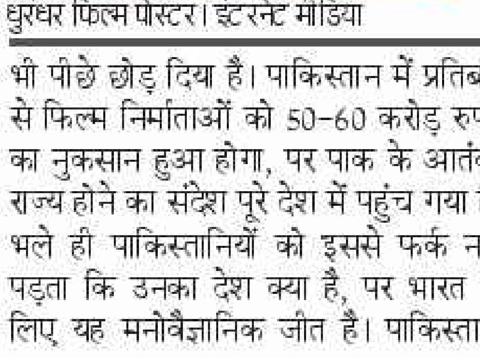

धुरंधर फिल्म पोस्टर। इंटरनेट मीडिया

फिल्म को रोकने में आइएसआइ पूरी तरह विफल

फिल्म से संबंधित इंटरनेट एड्रेस पर निगरानी रखने के बावजूद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ धुरंधर को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। इंटरनेट पर टोरंट और पायरेसी लिंक भरे पड़े हैं, जिनका इस्तेमाल फिल्म डाउनलोड करने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान के डार्क वेब विशेषज्ञ श्रीलंका, नेपाल और मलेशिया में स्थित सर्वरों का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवैध रूप से फिल्म डाउनलोड कर सकें और उसे देख सकें। पाकिस्तानी लोग टेलीग्राम चैनलों, गुप्त वेबसाइटों और वीपीएन के माध्यम से फिल्म डाउनलोड कर रहे हैं।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अदालत पहुंची

पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म की लोकप्रियता और वहां के लोगों पर इसका प्रभाव कितना है, इसे इस बात से भी जाना जा सकता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) अदलत तक पहुंच गई है। पीपीपी ने कराची की एक अदालत में बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों के इस्तेमाल को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। याचिका में फिल्म के कलाकारों और निर्माता-निर्देशक समेत फिल्म निर्माण में शामिल सभी लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज किए जाने की मांग की गई है।

'पीयूसी नहीं तो तेल नहीं' अभियान का असर, पीयूसी जांच 30 हजार के पार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से जूझती दिल्ली को 'पीयूसी नहीं तो तेल नहीं' अभियान से उम्मीद दिखने लगी है। गुरुवार को अभियान के पहले ही दिन कार्रवाई से बचने के लिए बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) बनवाया। कुल 31,197 वाहनों की जांच के बाद प्रमाणपत्र जारी किए गए। पीयूसीसी सेंटरों पर जांच के लिए वाहनों की भारी भीड़ दिखी। कहीं-कहीं जांच में तीन घंटे से अधिक समय लगा। वहीं, पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों ने वैध पीयूसी के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया। बहुत से लोगों को लौटाया गया। दिल्ली गेट तथा अरुणा आसफ अली रोड समेत कुछ स्थानों पर विवाद की स्थिति में पंप कर्मियों ने पीयूसी जांच के बिना ही पेट्रोल देते दिखे।

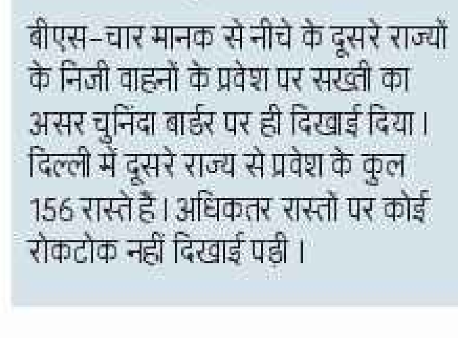

बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जुटी भीड़। चंद्र प्रकाश मिश्र

रोक के बावजूद बीएस-4 मानक से नीचे के वाहन चलते दिखे

बीएस-चार मानक से नीचे के दूसरे राज्यों के निजी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती का असर चुनिंदा बार्डर पर ही दिखाई दिया। दिल्ली में दूसरे राज्य से प्रवेश के कुल 156 रास्ते हैं। अधिकतर रास्तों पर कोई रोकटोक नहीं दिखाई पड़ी।

****

18 दिसंबर रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन, कोहरे ने भी किया परेशान, अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आज का मौसम

शुक्रवार की सुबह ज्यादातर जगह मध्यम कोहरा होगा।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
19 दिसंबर	22.0	9.0
20 दिसंबर	22.0	8.0
नोएडा		
19 दिसंबर	14.0	9.0
20 दिसंबर	15.0	10.0
गुरुग्राम		
19 दिसंबर	23.0	10.0
20 दिसंबर	24.0	10.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

आइजीआइ पर 27 उड़ानें रद और 50 से अधिक विलंबित

नई दिल्ली: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाई अड्डे पर गुरुवार को कम दृश्यता के कारण हवाई सेवाओं पर बुरा असर पड़ा। कोहरे के कारण 27 उड़ानें (आगमन व प्रस्थान) रद कर दी गईं और 50 से अधिक उड़ानें विलंबित रहीं। रद हुई उड़ानों में 16 प्रस्थान और 11 आगमन की उड़ानें शामिल हैं। (जासं)

डीयू परीक्षाओं में 2.28 लाख से अधिक छात्र शामिल

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की चल रही शीतकालीन सेमेस्टर परीक्षाओं में बुधवार को रिकार्ड संख्या में छात्रों की भागीदारी दर्ज की गई। विश्वविद्यालय के इतिहास के सबसे बड़े एक दिवसीय परीक्षा अभियानों में से एक के तहत कुल 2,28,781 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के अंतर्गत आयोजित की जा रही हैं। (जासं)

नकली लुब्रिकेंट तेल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी, एक गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नांगलोई में नकली लुब्रिकेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री में नकली लुब्रिकेंट को कैस्ट्रोल कंपनी के पैक और बोतलों में बेचा जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार करते हुए 3950 लीटर से ज्यादा कच्चा और नकली लुब्रिकेंट तेल, 12,000 खाली कैस्ट्रोल कंपनी की बोतलें व मशीनरी सामान बरामद किया है, जो एक करोड़ से ज्यादा का है। (जासं)

16 साल पुराने वायु गुणवत्ता मानकों के जरिये लड़ी जा रही प्रदूषण से जंग

संजीव गुप्ता • जागरण

नई दिल्ली : राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) ही देश में यह तय करते हैं कि लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए हवा कितनी साफ होनी चाहिए। कौन सा प्रदूषक कितनी सीमा तक स्वीकार्य है। लेकिन मौजूदा मानकों को अपडेट हुए डेढ़ दशक से अधिक समय हो चुका है। इस दौरान प्रदूषण के स्रोत बदल चुके हैं, शहरों का तेजी से विस्तार हुआ है व वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान भी ज्यादा स्पष्ट हुए हैं। ऐसे में मानकों का पुनरीक्षण बहुत जरूरी हो गया है। अभी भी 16 साल पुराने वायु गुणवत्ता मानकों के जरिये प्रदूषण से जंग लड़ी जा रही है।

जानकारी के मुताबिक वर्तमान मानक 2009 में अपडेट किए गए थे। इनमें 12 प्रदूषक शामिल हैं। पीएम 10, पीएम 2.5, एसओ 2, एनओ 2, ओ 3, सीओ, एनएच 3, लेड, बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक व निकल। 1981 में वायु अधिनियम बनने के बाद 1982 में पहले मानक आए। इसके बाद 1994, 1998 और फिर 2009 में अपडेट हुए।

इनमें प्रदूषकों की सीमा घटाई गई और मानकों को सख्त किया गया। लेकिन इसके बाद फिर यह प्रक्रिया दोबारा हुई ही नहीं।

सुझाव

- चुनिंदा शहरों और एयरशेड में पीएम 2.5 की रासायनिक निगरानी की जाए।
- वालेटाइल आर्गेनिक कम्पाउंड और अमोनिया की लक्षित माप हो।
- ओजोन के लिए आठ घंटे व मौसमी औसत का उपयोग किया जाए।
- खेती और कचरे से निकलने वाली अमोनिया को कम करना जरूरी।
- वाहनों और साल्वेंट से निकलने वाले वालेटाइल आर्गेनिक कम्पाउंड पर भी सख्ती जरूरी।
- पीएम 2.5 और ओजोन के लिए संयुक्त नीति अपनाना अनिवार्य।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम व वायु गुणवत्ता मानकों में तालमेल सुनिश्चित करना।
- प्रगति का मूल्यांकन केवल प्रतिशत कमी से नहीं, बल्कि मानकों से हो।

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 2009 का पुनरीक्षण अब अनिवार्य हो चुका है। नए मानक स्वास्थ्य-केंद्रित, विनक और एयरशेड-आधारित होने चाहिए। इनसे प्रदूषण नियंत्रण भी बेहतर होगा, नियमों का पालन बढ़ेगा एवं लंबे समय में जनस्वास्थ्य की सेहत की रक्षा हो पाएगी।

– डा एस के त्यागी, पूर्व अपर निदेशक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 2009 में संशोधन जरूरी है। पीएम एक एवं माइक्रोप्लास्टिक को भी इनमें लेना चाहिए। अगली बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा।

– डा अनिल गुप्ता, सदस्य, सीपीसीबी

दिल्ली की हवा में 60 प्रतिशत तक जहर घोल रहा पड़ोसी जिलों का धुआं

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण का करीब 65 प्रतिशत हिस्सा शहर के बाहर से आ रहा है। इसमें झज्जर जिला बड़ा योगदानकर्ता है। गुरुवार के आंकड़ों के अनुसार झज्जर जिला दिल्ली के कुल पीएम 2.5 प्रदूषण में 12.3 प्रतिशत का योगदान दे रहा था। झज्जर अकेला दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अन्य एनसीआर जिलों रोहतक ने 4.8 प्रतिशत, भिवानी ने 1.4 प्रतिशत व सोनीपत ने 8.8 प्रतिशत योगदान दिया। पड़ोसी एनसीआर जिलों से करीब 33 प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली पहुंच रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार झज्जर में दो बड़े कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट प्रमुख कारण हैं। रोहतक, भिवानी व सोनीपत में क्लस्टर भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं।

प्रदूषण रोधी कड़े उपायों के बावजूद फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा

- गुरुवार को 15 जगहों पर एक्यूआइ 400 पार दर्ज किया गया यानी पहुंचा 'गंभीर' श्रेणी में

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

घना कोहरा, हवा की गति में कमी और बादलों से घिरी राजधानी में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। एक दिन पहले बुधवार को ही हवा की रफ्तार बढ़ने और धूप खिलने के कारण राजधानी के लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली थी लेकिन गुरुवार को फिर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन भर स्माग छाया रहा। आने वाले कुछ दिन दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम ही है।

गुरुवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआइ 373 दर्ज किया गया। इसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। बुधवार को यह 334 रहा। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 41 अंकों की वृद्धि हो गई। शहर के 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 15 ने 'गंभीर' वायु गुणवत्ता दर्ज की। समीर एप के अनुसार, आनंद विहार में सबसे अधिक एक्यूआइ 441 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है, 24 केंद्रों ने 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता दर्ज की। आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण परिवहन का योगदान 18.3 प्रतिशत है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों का योगदान 9.2 प्रतिशत रहा, आवासीय स्रोतों का 4.5 प्रतिशत व निर्माण गतिविधियों का 2.5 प्रतिशत रहा। कचरा जलाने से 1.6 प्रतिशत, धूल से 1.3 प्रतिशत, अन्य क्षेत्रों से 1.2 प्रतिशत व बिजली उत्पादन से 1.2 प्रतिशत प्रदूषण हुआ।

2029 है स्वच्छ यमुना की नई डेडलाइन

प्रवेश वर्मा ने कहा, एक या दो साल में नहीं, 2029 में साफ होगी यमुना

दावा किया, यमुना को साफ करने की योजनाएं भी बनेंगी, उन पर अमल भी होगा

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

यमुना को साफ करने की दिल्ली सरकार ने अब नई डेडलाइन दे दी है। अब 2029 तक यमुना को स्वच्छ करने का दावा किया गया है। जल और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेसवार्ता में कहा कि जनता ने पांच साल के लिए उनकी सरकार को चुना है, लोग थोड़ा इंतजार करें, सभी मुद्दों और समस्याओं का हल होगा। दिल्ली में एक दो साल के हिसाब से नहीं, पिछले 40, 50 साल की योजना को लेकर काम हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2029 तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा। मंत्री ने आरोप लगाया कि यमुना की हालत इसलिए भी खराब है कि पूर्व की सरकार ने एक तो ठीक से योजनाएं नहीं बनाईं और जो बनाईं भी, उन पर भी ठीक से अमल नहीं किया और यही कारण है कि यमुना अब तक साफ नहीं हो पाई।

जल मंत्री वर्मा ने कहा कि बार-बार पूछा जाता है कि यमुना कब साफ होगी? मैं बताना चाहता हूं कि यमुना चार या छह महीने में साफ नहीं होगी या फिर एक या दो साल में भी साफ नहीं होगी। इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जा चुका है। यमुना 2029 में साफ होगी। उन्होंने दावा किया कि हमने इसके लिए उन सभी कालोनियों में सीवर लाइन डालने की योजना बनाई है, जहां सीवर लाइन नहीं है। साथ ही झुग्गी कालोनियों को भी सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। दिल्ली भर के सीवर के पानी को एसटीपी में ले जाएगा। एसटीपी में इस पानी को उपचारित कर पार्कों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके बाद जो पानी बचेगा उसे शोधित कर यमुना में छोड़ा जाएगा। जिन नालों के माध्यम से सीवर का पानी यमुना में गिरता है उन नालों की भी सफाई की जाएगी। इसके लिए मशीनें आ रही हैं। मंत्री ने दावा किया कि 2029 में हम यमुना को साफ करके दिखाएंगे, यह हमारी सरकार का संकल्प है।

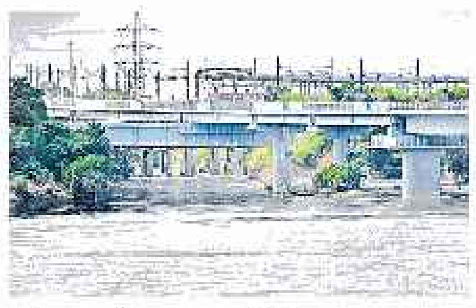

वजीराबाद के पास यमुना में गिरता नजफगढ़ नाला। ध्रुव कुमार

एसटीपी कम हैं और कई मानकों पर खरे नहीं उतरे : दिल्ली में हर दिन लगभग 792 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) सीवेज उत्पन्न होता है, जिसमें से करीब 600 एमजीडी को उपचारित किया जाता है, लेकिन लगभग 200 एमजीडी अशोधित सीवेज नालों के माध्यम से यमुना में बह जाता है। बताया गया है कि एसटीपी की संख्या जरूरत के हिसाब से कम है, सभी एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं और कई मानकों पर खरे भी नहीं उतरते हैं। दिल्ली में 37 एसटीपी काम कर रहे हैं।

यमुना सफाई की यह है योजना : दिल्ली में 48 किमी लंबी यमुना की सफाई के लिए 45 प्वाइंट एक्शन पर काम चल रहा है। जिसमें जल बोर्ड, सिंचाई व बाढ़ विभाग, एमसीडी, डीपीसीसी, डीडीए और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सभी को मिलकर काम करना है। अगले तीन सालों में फेज-वाइज काम किया जाएगा, ताकि यमुना पूरी तरह से साफ हो सके। इस योजना के तहत ही 8000 करोड़ रुपये से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। योजना के तहत नालों के गंदे पानी को ट्रीट करना, सीवरेज नेटवर्क में विस्तार, आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं।

सड़क बनाने वाली कंपनी ही पांच साल तक करेगी उसका रखरखाव : प्रवेश वर्मा

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: सड़कों के निर्माण होने पर अब पांच साल के लिए वही कंपनी उसकी मरम्मत करेगी जो उस सड़क को बनाएगी। निर्माण के समय सड़क बनाने वाली कंपनी का नाम और अधिकारियों के मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह जानकारी प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने कहा कि सड़क बनाने से पहले सभी सिविक एजेंसियों को पत्र लिखकर उनकी दो साल की योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। अगर किसी ने जानकारी नहीं दी और छह महीने बाद सड़क को खोदने के लिए वह आती है तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। अब सड़क बार-बार खोदने की अनुमति नहीं मिलेगी। मार्च तक दिल्ली की 450 किलोमीटर सड़कें बन जाएंगी। इसके बाद नवंबर 2026 तक दिल्ली की कुल 1150 किलोमीटर सड़कें बन चुकी होंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कार्य योजना तैयार कर ली है। वर्मा ने बृहस्पतिवार को प्रेसवार्ता में पूर्व की आप सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में लंबित रहे कार्यों से जुड़ी फाइलों का बड़ा पुलिंदा प्रस्तुत किया।

वाहन जांच को लंबी कतारें, वैध पीयूसी बिना पंपों से वाहनों को लौटाया गया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से जूझती दिल्ली को 'पीयूसी नहीं तो तेल नहीं' अभियान से उम्मीद दिखने लगी है। बुधवार को अभियान में कार्रवाई से बचने के लिए बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अपने वाहनों की प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) जांच कराना शुरू कर दिया है। इसके चलते एक दिन में बुधवार को कुल पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने की संख्या 31,197 तक पहुंच गई। एक दिन पहले यह मात्र 17,732 थी। अभियान से सरकार की कोशिश है कि सड़कों पर कम से कम प्रदूषण करने वाले वाहन ही चलें। वाहन चालकों को जागरूक करने को लेकर पंपों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। साथ ही वाहन मालिकों को जागरूक किया जा रहा है।

कुछ स्थानों पर एक से तीन घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी : अभियान के पहले दिन भी पीयूसीसी सेंटरों पर वाहनों का भारी दबाव देखा गया। हालांकि, अचानक बढ़े भारी दबाव के चलते दिल्ली के अलग-अलग पीयूसी सेंटरों से सर्वर धीमा रहने की शिकायतें भी आईं। ऐसे में वाहनों की जांच में कहीं-कहीं तीन घंटे से अधिक समय लगा।

पेट्रो पदार्थों की बिक्री पर दिखा असर : इस अभियान का असर पेट्रो पदार्थों की बिक्री पर भी पड़ा है। आम दिनों के मुकाबले इन पंपों पर वाहनों की संख्या में 25 प्रतिशत की गिरावट है। इसी तरह, बीएस-चार मानक से नीचे के दूसरे राज्यों के निजी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती का असर कुछ चुनिंदा बार्डर पर ही दिखाई दिया। दिल्ली में दूसरे राज्य से प्रवेश के कुल 156 रास्ते हैं। इनमें से आनंद विहार, गाजीपुर, चिल्ला बार्डर, दिल्ली-फरीदाबाद बार्डर समेत कुछ बार्डर पर यातायात पुलिसकर्मी व परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की जांच कर उन्हें वापस लौटाते दिखे।

ओखला स्थित पेट्रोल पंप पर एनाउंसमेंट सिस्टम खराब होने की स्थिति में प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच करता डीडीसी कर्मचारी। विपिन शर्मा

एनसीआर में भी लागू हो यह नियम : दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा, कुछ पंपों पर पीयूसी देखने व पेट्रो पदार्थ देने से इन्कार पर विवाद को छोड़ बाकी जगह स्थिति शांतिपूर्ण रही। इसे पूरे एनसीआर में लागू करने की मांग कर रहे हैं।

16 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, देशभर से नौ आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की पश्चिमी जिला टीम ने एक बड़े अंतरराज्यीय संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट को ध्वस्त करते हुए नौ आरोपितों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। इसकी शुरुआत पश्चिमी दिल्ली जिले के साइबर थाने में दर्ज 21 लाख रुपये की ठगी की एक शिकायत की जांच से हुई थी, जिसकी कड़ियां जुड़ती गईं तो सामने आया कि आरोपितों के बैंक खातों से देशभर में दर्ज 286 साइबर ठगी की शिकायतों के तार जुड़े हुए हैं। जिसमें उन्होंने 16 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपितों में शौकत अली (कर्नाटक), बाबू पायनादथ (केरल), एन्थोनी बाबू (केरल), देवेंद्र पांडे (उत्तर प्रदेश), दुरव राज मिश्रा (उत्तर प्रदेश), फारूक (दिल्ली), मोहम्मद अदनान रजा (उत्तर प्रदेश), अम्मा गुंटा कविता (आंध्र प्रदेश) और केवी शिव योगी (कर्नाटक) शामिल हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड दुबई में बैठकर मोबाइल एप के जरिए इन सभी बैंक खातों को रिमोटली नियंत्रित करता था।

सीएम ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को डीटीसी के बेड़े में किया शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रहे तमाम प्रयासों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर डीटीसी के बेड़े में शामिल किया। राजधानी में अब ई-बसों की संख्या 3,500 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही धौलाकुआं से धारूहेड़ा तक अंतरराज्यीय बस सेवा की भी शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस सेवा से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। कश्मीरी गेट आइएसबीटी में हुए लोकार्पण कार्यक्रम में परिवहन मंत्री डा. पंकज सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सशक्त बनाने, यात्रा को मंजिल तक पहुंचाने और प्रमुख मार्गों पर जाम एवं प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि धौलाकुआं-धारूहेड़ा रूट पर ई-बस सेवा क्षेत्रीय आवागमन को मजबूत करने के साथ-साथ दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में भी अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजधानी में वाहनों के पीयूसी जांच के लिए नंदनगरी, तेहखंड और बुराड़ी में आटोमेटेड परीक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां हजारों वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के लिए पिंक कार्ड सुविधा जल्द शुरू की जा रही है।

कश्मीरी गेट पर इलेक्ट्रिक डीटीसी बस को हरी झंडी दिखा रवाना करती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साथ में परिवहन मंत्री डा.पंकज सिंह। ध्रुव कुमार

इंटरनेट पर बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड मामले में 52 केस दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: बाल यौन शोषण सामग्री को इंटरनेट मीडिया पर साझा करने व प्रसारित करने के मामले में दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल यूनिट ने 52 एफआइआर दर्ज की है। सभी मामलों की गहन जांच की जा रही है। आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है।

महिला एवं बाल यूनिट की डीसीपी अंजिता चेपयाला का कहना है कि बाल यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों के प्रति 'शून्य सहनशीलता' की नीति अपनाई गई है। डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए महिला व बाल यूनिट ने बाल यौन शोषण एवं शोषण सामग्री से जुड़े साइबर मामलों में व्यापक कार्रवाई की है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आनलाइन प्लेटफार्म पर फैल रहे गंभीर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। नानकपुरा स्थित यह यूनिट राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट्स की निगरानी कर रही है।

नहीं रहे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू आफ यूनिटी बनाने वाले राम सुतार

जागरण संवाददाता, नोएडा : मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की भव्य प्रतिमा व बच्चों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने की अधूरी इच्छा दिल में संजोए प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार नहीं रहे। गुरुवार को 100 वर्ष, 10 महीने की आयु में नोएडा स्थित आवास पर अंतिम सांस ली।

सुतार ने जीवनकाल में एक हजार से अधिक मूर्तियों को आकार दिया। देश-विदेश के अनेक शहरों में स्थापित उनकी कृतियां भारतीय संस्कृति, शौर्य व मूल्यों की पहचान हैं। उनकी बनाई गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची 'स्टैच्यू आफ यूनिटी' विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। वे पद्मश्री, पद्मभूषण समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके थे। 2021 में ग्रेटर नोएडा में दैनिक जागरण की ओर से आयोजित जागरण विमर्श कार्यक्रम में उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया था।

राम वी सुतार की फाइल फोटो। जागरण

एक साल पहले दैनिक जागरण से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनकी दो इच्छा अब भी शेष हैं। वह यह कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दो बच्चों के साथ वाली मूर्ति सबसे ऊंचे आकार में बनाएं। प्रभु श्रीराम की सरयू पर जो मूर्ति बनानी है, उसे भी ईश्वर उन्हें बनाने का अवसर दें। उनके बेटे अनिल सुतार ने बताया कि श्रीराम की प्रतिमा और बच्चों के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा समुद्र के बीच बनाने की थी। यह इच्छा पूरी न होने पर उन्होंने पटना में 40 फीट की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई।

बिच्छू की आकृति से शुरू हुआ था सफर : मूलरूप से महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंडूर के सुतार मूर्तिकार बनने का जुनून लेकर दिल्ली आए। पहली आकृति पांच वर्ष की उम्र में पेन से पेपर पर बिच्छू की उकेरी थी।

राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया शोक: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक्स पर मराठी भाषा में संवेदना व्यक्त की। लिखा-राम सुतारजी के निधन से दुख हुआ। वे एक शानदार मूर्तिकार थे। उनके काम को हमेशा देश के इतिहास, संस्कृति व सामूहिक भावना की दमदार अभिव्यक्ति के तौर पर सराहा जाएगा।

सुंदरीकरण

एनडीएमसी इस साल 3.25 लाख और डीडीए लगाएगा लगभग दो लाख ट्यूलिप, एनडीएमसी ने नीदरलैंड से मंगाए ट्यूलिप के बल्ब, 27 से शुरू होगा रोपण

राजधानी की सड़कों के किनारे व पार्कों में खिलेंगे ट्यूलिप के फूल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रपति भवन के बाद अब राजधानी में सड़कों के किनारे और पार्कों में भी ट्यूलिप लगाए जाने लगे हैं। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) हर वर्ष इसको लेकर अलग-अलग प्रयोग करती है। इस वर्ष वह पहली बार ट्यूलिप से वन नेशन वन इलेक्शन, एक पेड़ मां के नाम और विकसित भारत की आकृति बनाएगी। इसके लिए नीदरलैंड से आठ किस्म के ट्यूलिप के बल्ब मंगवाए जा रहे हैं, जो अगले सप्ताह तक आ जाएंगे। 27 दिसंबर से इनको रोपने का कार्य शुरू होगा।

एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि नई दिल्ली में सुंदरीकरण को बढ़ावा देने और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्य किया जाता है, ताकि सड़कों के किनारे लगे ट्यूलिप से शहर आकर्षित लगे। चहल ने बताया कि नीदरलैंड से मंगाए गए ट्यूलिप बल्ब दिसंबर के अगले सप्ताह तक भारत पहुंच जाएंगे। पालमपुर सीएसआइआर अनुसंधान केंद्र में संरक्षित 20,700 ट्यूलिप बल्ब आ गए हैं, जिन्हें पुराना किला रोड स्थित नर्सरी में रखा गया है। चहल ने बताया कि इस वर्ष विशेष रूप से नई दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों, जैसे बिरला मंदिर, हनुमान मंदिर एवं बंगला साहिब गुरुद्वारा परिसर आदि में ट्यूलिप लगाए जाएंगे। जहां इनका रोपण संभव नहीं है, वहां गमलों में इनको लगाया जाएगा। चहल ने कहा कि इस वर्ष एनडीएमसी ट्यूलिप से 'एक पेड़ मां के नाम', 'वन नेशन वन इलेक्शन' और 'विकसित भारत' के नाम उकेरेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 5,17,500 ट्यूलिप बल्ब मंगाए गए हैं। इसमें तीन लाख 25 हजार बल्ब एनडीएमसी और 1,92,500 बल्ब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के लिए है।

पुराना किला स्थित नर्सरी में संरक्षित ट्यूलिप बल्ब की जानकारी लेते एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल। सौजन्य: एनडीएमसी

आम लोग खरीद सकेंगे गमलों में लगे ट्यूलिप : एनडीएमसी 2.25 लाख ट्यूलिप बल्ब शांति पथ, कनाट प्लेस का सेंट्रल पार्क, कन्वेंशन सेंटर, लोदी गार्डन, तलकटोरा गार्डन, सरदार पटेल मार्ग, मंडी हाउस, विंडसर प्लेस, शेरशाह सूरी मार्ग और उपराष्ट्रपति भवन के समीप गोल चक्करों में लगाए जाएंगे। लगभग एक लाख ट्यूलिप बल्ब गमलों में लगाए जाएंगे और आमजन उनको खरीद सकेंगे।

गाजियाबाद में किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

पांच महीने से किराया नहीं देने वाले दंपती ने किराया लेने आई मकान मालकिन पर कुकर से हमला किया और चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सूटकेस में छिपाने की साजिश रची। हालांकि, घरेलू सहायक महिला की सूझबूझ से आरोपित दंपती शव ठिकाने लगाने से पहले ही पकड़ा गया।

उमेश शर्मा के अनुसार, वह गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं और कुछ माह से वहीं रह रहे हैं। उनकी 48 वर्षीय पत्नी दीपशिखा शर्मा और घरेलू सहायिका मिनी बुधवार शाम को राजनगर एक्सटेंशन की औरा चिमेरा सोसायटी स्थित फ्लैट में थीं। यहां उनके पास दो फ्लैट हैं। एक में खुद परिवार के साथ रहते हैं, जबकि दूसरे में अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता को एक साल पहले 18 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया था। उमेश शर्मा के अनुसार, किरायेदार ने पिछले पांच महीनों से किराया नहीं चुकाया था। बुधवार शाम को अजय ने फोन कर दीपशिक्षा को किराया लेने बुलाया। दीपशिखा रात करीब 7:52 बजे अपने फ्लैट से निकलीं। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो मिनी को चिंता हुई। मिनी ने किरायेदार के फ्लैट पर जाकर जानकारी ली, जहां उसे बताया गया कि दीपशिखा किराया लेकर जा चुकी हैं।

दीपशिखा शर्मा की फाइल फोटो। सौ. स्वजन

****

मनरेगा की 'व्यवस्थित हत्या' के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन करेगा विपक्ष

खरगे और सोनिया की अगुआई में विपक्षी सदस्यों ने संसद परिसर में निकाला विरोध मार्च

कांग्रेस ने राजनीतिक लड़ाई की रणनीति तय करने के लिए 27 दिसंबर को बुलाई कार्यसमिति की बैठक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद परिसर में गुरुवार को प्रदर्शन करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत विपक्षी दलों के सांसद। प्रेट्र

विपक्षी दलों ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए लाए गए जी राम जी विधेयक का संसद से सड़क तक विरोध तेज करते हुए गुरुवार को संसद परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों ने गांधी प्रतिमा से संसद के मकर द्वार तक विरोध मार्च करते हुए नए विधेयक को वापस लेने की मांग की। खरगे ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा की "व्यवस्थित हत्या" के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन होगा।

नाम समेत मनरेगा में बदलाव के विरुद्ध आगे की राजनीतिक लड़ाई की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस ने 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। सरकार द्वारा जी राम जी विधेयक लोस से पारित कराए जाने के विरुद्ध विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार सुबह संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें खरगे-सोनिया के अलावा द्रमुक के टीआर बालू, ए. राजा, कनिमोरी, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन जैसे अन्य नेता शामिल हुए।

बाद में खरगे ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'यह केवल महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलने की बात नहीं है। यह भाजपा-आरएसएस की मनरेगा को खत्म करनी साजिश है। संघ के 100 वर्ष पर गांधी का नाम मिटाना यह दिखाता है कि जो मोदी जी विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं, वह कितने खोखले और दिखावटी हैं। जो सरकार गरीब के हक से चिढ़ती हो, वही मनरेगा पर वार करती है। इस अहंकारी सत्ता का ऐसा कोई भी निर्णय जो गरीब और मजदूर विरोधी होगा, उस प्रविधान के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी संसद और सड़क पर उसका पुरजोर विरोध करेगी। करोड़ों गरीबों, मजदूरों और कामगारों के हकों को हम सत्ता के हाथों छिनने नहीं देंगे।'

मनरेगा को पूरी तरह खत्म कर देगा जी राम जी, विपक्ष जोरदार विरोध के लिए एकजुट

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से कहा जी राम जी विधेयक मनरेगा को पूरी तरह खत्म कर देगा, इसलिए विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के कदम का जोरदार विरोध करने के लिए एकजुट है। नए विधेयक में काम 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना उनका धोखा है क्योंकि जो भी विधेयक को ध्यान से पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा कि यह योजना अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। प्रियंका के अनुसार जैसे ही राज्यों पर बोझ पड़ेगा, योजना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों के पास पर्याप्त पैसा ही नहीं है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसद आज लोकतंत्र की हत्या होते देख रही है और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर व लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ राष्ट्रपिता की विचारधारा को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

नाम बदलने की सनक कांग्रेस में रही है : शिवराज

प्रथम पृष्ठ से आगे

शिवराज ने सदन के बाहर भी कांग्रेस पर हमला जारी रखा। दो दिन पहले प्रियंका वाड्रा के सरकार पर नाम बदलने की सनक के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बताया और कहा, नाम बदलने की सनक कांग्रेस में रही है। नेहरू-गांधी परिवार के नाम पर दर्जनों योजनाएं, संस्थान, पुरस्कार, सड़कें, हवाई अड्डे व यहां तक कि राष्ट्रीय उद्यानों तक के नाम रखे गए।

मोदी सरकार का लक्ष्य किसी परिवार का महिमामंडन नहीं, जनकल्याण है : केंद्रीय मंत्री ने कहा, मोदी सरकार का लक्ष्य किसी परिवार का महिमामंडन नहीं, बल्कि जनकल्याण है। कांग्रेस शासन में मात्र 153 लाख कार्य पूरे हुए, वहीं मोदी सरकार में यह संख्या 862 लाख हो गई। महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस के समय 48 प्रतिशत थी, जो अब 56.73 प्रतिशत है। आधार सीडिंग कांग्रेस के समय 76 लाख थी, जिसे मौजूदा सरकार ने 12 करोड़ से अधिक किया। पहले भुगतान व्यवस्था पारदर्शी नहीं थी। अब सीधे मजदूरों के खाते में पैसे जा रहे हैं। शिवराज ने कहा, नया विधेयक ग्रामीण भारत के समग्र विकास का रोडमैप है। कहा कि महात्मा गांधी मानते थे कि गांव भारत का आत्मा हैं और यह विधेयक उसी सोच को आगे बढ़ाने वाला है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब गांव विकसित होंगे। सवाल किया, "उन्होंने कागज फाड़ दिए, डेस्क के ऊपर खड़े हो गए। क्या यह बापू के आदर्शों की हत्या नहीं है? क्या यह अनैतिक व अशोभनीय नहीं था? क्या बापू विपक्ष के सदस्यों के इस तरह के शर्मनाक व्यवहार को स्वीकार करते।'

बांग्लादेश में चीन के बढ़ते दखल पर संसदीय समिति ने गंभीर चिंता जताई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की गई

समिति ने रिपोर्ट में बांग्लादेश की स्थिति को भारत के लिए चुनौती बताया गया

विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक स्थिति भारत के लिए 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद सबसे गंभीर रणनीतिक चुनौती बन गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इस समिति की रिपोर्ट गुरुवार को संसद में पेश की गई। रिपोर्ट में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथी ताकतों की वापसी और चीन-पाक के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा किया गया है। खास तौर पर चीन की तरफ से बांग्लादेश में एयरबेस, पनडुब्बियों के लिए बेस बनाने व जमात-ए-इस्लामी को लुभाने की कोशिशों का मुद्दा समिति ने उठाया है और सरकार को वहां सक्रिय विदेशी शक्तियों की गतिविधियों पर करीबी नजर रखने का सुझाव दिया है।

इस रिपोर्ट को काफी सामयिक कहा जा सकता है। बांग्लादेश में अभी जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता है। वहां के अतिवादी छात्र समूह निरंतर भारत की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। समिति ने कहा, हांलाकि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति वर्ष 1971 की स्थिति से अलग है,पर वहां की राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी ताकतों का मिश्रण अधिक जटिल, दीर्घकालिक व संरचनात्मक चुनौती पैदा करने की क्षमता रखते हैं। यह क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की पड़ोस नीति को प्रभावित कर सकता है।

पूर्व पीएम शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में जिस तरह से चीन की सक्रियता बढ़ी है, उसे विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। समिति ने मोंगला बंदरगाह के विस्तार का जिक्र किया है, जहां चीन ने मो. यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ करीब 40 करोड़ डालर की परियोजना लागू करने के लिए समझौता किया है। यह बंदरगाह कोलकाता के करीब है और इस परियोजना को चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' चीन की भू-राजनीतिक रणनीति है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बंदरगाहों व सैन्य ठिकानों का नेटवर्क बनाना शामिल है, ताकि वह अपने समुद्री प्रभाव को बढ़ा सके और भारत को घेर सके। समिति ने लालमोनिरहाट एयरबेस के विकास में चीन की मदद पर भी गंभीर चिंता जताई है। यह एयरबेस भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर है और सिलिगुड़ी कारिडोर (चिकन नेक) से करीब है। वैसे बांग्लादेशी सेना ने कहा है कि फिलहाल इसका सैन्य उपयोग नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।

समिति ने जमात-ए-इस्लामी नेताओं की हालिया चीन यात्रा का भी उल्लेख किया, जो बांग्लादेश में विभिन्न गुटों के साथ उसके व्यापक जुड़ाव का संकेत देती है। इसके अलावा, पेकुआ में चीन द्वारा निर्मित पनडुब्बी बेस का जिक्र किया गया है। इस बेस पर आठ पनडुब्बियों को समायोजित करने की क्षमता तैयार की जा रही है, जबकि बांग्लादेश के पास केवल दो पनडुब्बियां हैं। यह बंगाल की खाड़ी में चीन की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की नीति की तरफ संकेत देता है।

रिपोर्ट में भारत की 'शांत कूटनीति' की सराहना की गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से समिति को बताया गया है कि चीन की उपस्थिति लंबे समय से है यह और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों का परिणाम नहीं है। भारत ने खुलना-मोंगला रेलवे लिंक के लिए वित्तीय सहायता की है और पारगमन सुविधाओं के लिए समझौते किए हैं। समिति ने सिफारिश की कि सरकार बांग्लादेश में विदेशी शक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखे। विशेष रूप से सैन्य आधार स्थापित करने की कोशिशों की निगरानी जरूरी है, जो भारत के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं। साथ ही विकास सहयोग में भारत के तुलनात्मक लाभ का उपयोग कर विश्वास बढ़ाने और अपनी स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया गया।

शेख हसीना को शरण देने का समर्थन : प्रेट्र के अनुसार, संसदीय समिति ने कहा है कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत द्वारा शरण देने पर ध्यान दिया है। इस संबंध में देश का दृष्टिकोण उसकी सभ्यतागत नैतिकता और मानवीय परंपरा से प्रेरित है, जिसके तहत गंभीर संकट या अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे व्यक्तियों को शरण दी जाती है। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को भारत के मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप अपना सैद्धांतिक और मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए।

रूस की सेना में तैनात थे 202 भारतीय, 26 की मौत

▶ कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी

कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, राजनयिक प्रयासों से 119 भारतीय रूसी सेना से मुक्त

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा, 2022 से अब तक 202 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया है, जिनमें से 26 की मौत हो गई है। सात लापता हैं। सरकार ने यह जानकारी तृकां के सदस्य साकेत गोखले व कांग्रेस सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए कथित तौर पर मजबूर किए गए या अवैध रूप से भर्ती किए गए भारतीयों की वापसी के बारे में पूछा था।

विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा,भारत के लगातार राजनयिक प्रयासों से 119 भारतीयों को मुक्त करा लिया गया है, जबकि 50 अभी भी रूसी सेना से मुक्त होने का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय उनकी जल्द और सुरक्षित वापसी के लिए रूसी अफसरों के संपर्क में है।

केंद्र ने कहा, इस मुद्दे को कई राजनयिक स्तरों पर उठाया गया है, जिसमें दोनों देशों के नेताओं, मंत्रियों व अफसरों के बीच बातचीत शामिल है। कहा, बाकी भारतीयों की वापसी तक प्रयास जारी रहेंगे। सरकार ने कहा कि मारे गए 26 लोगों में से 10 के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। दो का अंतिम संस्कार भारतीय दूतावास की मदद से रूस में ही किया गया। 18 भारतीयों के परिवार के सदस्यों के डीएनए सैंपल, जिनके बारे में बताया गया था कि वे मर गए हैं या लापता हैं, रूसी अधिकारियों के साथ साझा किए गए हैं ताकि कुछ मृत भारतीय नागरिकों की पहचान स्थापित करने में मदद मिल सके।

निजी क्षेत्र की भागीदारी खोलने वाला परमाणु ऊर्जा विधेयक संसद से पारित

▶ राज्यसभा से ध्वनिमत से पारित, लोकसभा से बुधवार को हुआ था पास

▶ विपक्ष की ओर से पेश विभिन्न संशोधनों को उच्च सदन ने किया खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र: संसद ने गुरुवार को परमाणु ऊर्जा विधेयक पारित कर दिया। कड़े नियंत्रण वाले असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने का प्रविधान करने वाले इस विधेयक 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट आफ न्यूक्लियर एनर्जी फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया' (शांति) को राज्यसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। साथ ही प्रस्तावित कानून को संसदीय समिति को भेजने के लिए विपक्ष की ओर से पेश कई संशोधनों को खारिज कर दिया। लोकसभा ने विधेयक को बुधवार को ही पारित कर दिया था।

परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा,इसका उद्देश्य भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना व ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। परमाणु ऊर्जा चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति का विश्वसनीय स्रोत है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के मामले में ऐसा नहीं है। 2025 में देश ने 8.9 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। रोडमैप का पालन किया तो 2047 तक 100 गीगावाट की क्षमता हासिल कर लेंगे। बड़े पैमाने पर एआइ के आने से देश की ऊर्जा जरूरत परमाणु स्रोतों पर ज्यादा निर्भर होगी।

> संसद के दोनों सदनों से 'शांति' विधेयक पारित होना भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए बदलाव लाने वाला पल है। यह भारत में निवेश करने, नवाचार करने और निर्माण करने का सबसे अच्छा समय है। यह विधेयक निजी क्षेत्र और युवाओं के लिए कई मौके खोलता है।
>
> – **नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने का बचाव करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा,विभिन्न क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के परिणाम बेहद फायदेमंद रहे हैं। साथ ही आश्वस्त किया कि विधेयक में सुरक्षा प्रविधानों से किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। सुरक्षा प्रविधान और उनकी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) वही हैं जो 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम में थे, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में लागू किया गया था। इस एसओपी में साफ तौर पर 'पहले सुरक्षा, फिर उत्पादन' का उल्लेख है। विकिरण के डर को दूर करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक जनता को विकिरण से जुड़े किसी खतरे की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा, "पिछले 10-11 वर्षों में भारत ने वैश्विक भूमिका निभाई है। भारत अब दूसरों का अनुगामी नहीं है, अब हम पहली पंक्ति के देश हैं। 2014 के बाद यह पहली बार है जब जलवायु, ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा या स्वच्छ ऊर्जा जैसी वैश्विक चिंताओं को प्राथमिकता दी जा रही है।।

अफगानिस्तान में चिकित्सा सेवाओं का आधारभूत ढांचा खड़ा करने में मदद करेगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ नए अस्पताल से खोलने से लेकर दवाओं और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति का समझौता

नई दिल्ली में गुरुवार को अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। प्रेट्र

अफगानिस्तान में चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे के विकास के साथ ही गंभीर चिकित्सा सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने में भारत मदद करेगा। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली के साथ मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरसंभव मदद का भरोसा दिया। इससे आने वाले वर्षों में इलाज के लिए अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। गुरुवार को दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों की बातचीत में अफगानिस्तान में अहम मेडिकल प्रोजेक्ट को लागू करने का फैसला लिया गया। इनमें पटकिया, खोस्त और पाकटिका प्रांत में पांच मातृत्व व स्वास्थ्य क्लिनिक खोलने के साथ काबुल में 30 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण शामिल है। इसके अलावा काबुल में कैंसर उपचार सेंटर, ट्रामा सेंटर, डायगनोस्टिक सेंटर और थैलेसेमिया सेंटर खोलने का भी निर्णय हुआ। अफगानिस्तान की ओर से की गई अन्य मांगों पर विचार का भरोसा दिया गया।

जेपी नड्डा ने कहा कि मानवीय सहायता के तहत भारत अफगानिस्तान को पिछले चार वर्षों में 327 टन दवाइयां भेज चुका है। अफगानिस्तान के अनुरोध पर कैंसर दवाओं और सीटी स्कैन मशीन को भेजने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा रेडियोथैरेपी मशीन और अतिरिक्त दवाएं भेजने की प्रक्रिया जारी है। भारत में अफगानिस्तान के लोगों का गंभीर बीमारियों से मुफ्त इलाज की सुविधा जारी रहेगी। इसके तहत अप्रैल से अब तक 200 मेडिकल वीजा जारी किया जा चुका है।

शेयर बाजार संहिता में होगा बदलाव, सिक्युरिटी मार्केट्स कोड बिल पेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार और बाजार में निवेशकों व निवेश में भारी वृद्धि को देखते हुए सरकार शेयर बाजार संबंधी संहिता को सरल और पारदर्शी बनाने जा रही है। इसके तहत गुरुवार को संसद में सिक्युरिटी मार्केट्स कोड (एसएमसी) बिल, 2025 पेश किया गया। हालांकि इस बिल को वित्त से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। इसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सदस्यों की संख्या नौ से 15 करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इस बिल का उद्देश्य शेयर बाजार, म्युचुअल फंड, बांड आदि से जुड़ी अलग-अलग संहिताओं को एक बनाना है ताकि यह निवेशकों की रक्षा के साथ पूंजी को इकट्ठा कर सके। अलग-अलग संहिता होने से कई संहिताएं एक जैसी थीं, जिन्हें समाप्त कर दिया गया है। भाषा सरल की गई है ताकि निवेशक उसे आसानी से समझ सके। अनुपालन नियम कम किया गया है, टेक्नोलाजी को अपनाने पर जोर दिया गया है जिससे कारोबार व निवेश आसान हो सके।

डच विदेश मंत्री से मिले राजनाथ, रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर

▶ भारत-नीदरलैंड के मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी की पुष्टि की

▶ रक्षा सचिव राजेश और नीदरलैंड के राजदूत ने किया दस्तावेजों का आदान-प्रदान

नई दिल्ली में गुरुवार को नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वान वील को स्मृति चिह्न भेंट करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां डच विदेश मंत्री डेविड वान वील से भेंट की, जिसमें दोनों नेताओं ने "सह-विकास और सह-उत्पादन" के लिए रक्षा उपकरणों के प्राथमिक क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। भारत-नीदरलैंड के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता पत्र भी दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह व भारत में नीदरलैंड के राजदूत मारिसा गेराड्स ने गुरुवार को इन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया।

रक्षा मंत्रालय ने कहा,राजनाथ सिंह ने डच विदेश मंत्री के साथ भेंट में "दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ती रक्षा साझेदारी" की पुष्टि की। दोनों ने द्विपक्षीय सुरक्षा व रक्षा मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन के प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने सैन्य सहयोग को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। चर्चाओं में भारत-नीदरलैंड के बीच स्वतंत्र, खुला, समावेशी व नियम-आधारित हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी उजागर किया गया। तकनीक के क्षेत्र में दोनों नेताओं ने "नजदीकी रक्षा साझेदारी" की जरूरत और दोनों देशों की रक्षा उद्योगों को जोड़ने पर जोर दिया। दोनों देशरक्षा सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने का इरादा रखते हैं, ताकि प्रौद्योगिकी सहयोग, सह-उत्पादन और प्लेटफार्मों और उपकरणों के सह-विकास के लिए एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप विकसित किया जा सके। सिंह के हवाले से बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच जनसंपर्क संबंध बहुत मजबूत हैं, जिसमें नीदरलैंड में एक बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय एक जीवित पुल के रूप में कार्य कर रहा है और मित्रता के बंधनों को मजबूत कर रहा है।

आपदा प्रबंधन में माडल बनेंगे 20 राज्यों के 20 गांव

रूपरेखा तैयार

प्राकृतिक आपदा से निपटने की गृह मंत्री शाह के आह्वान को धरातल पर उतारेगा पंचायतीराज मंत्रालय, देशभर के 81 संवेदनशील जिलों से चिन्हित किए जाने हैं गांव, दो वर्ष की कार्ययोजना पर खर्च होंगे 507 .37 करोड़ रुपये

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भौगोलिक परिस्थितियों के कारण देश के अलग-अलग राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। इनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सक्रिय रहते हैं, पर गृह मंत्री अमित शाह ने विजन दिया कि जो गांव बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, तट क्षरण व नदियों के कटाव जैसी छह प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। यदि उसी पहले मोर्चे पर तैयारी मजबूत की जाए तो बेहतर होगा।

गृह मंत्री के इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय और एनडीएमए ने विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत ऐसी परिस्थितियों से जूझने वाले 20 राज्यों में एक-एक गांव को आपदा प्रबंधन के माडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।

गृह और पंचायतीराज मंत्रालय ने इस दो वर्षीय कार्यक्रम को इस उद्देश्य के साथ तैयार किया है कि आपदा के बाद इससे निपटने के स्थान पर आपदा से पहले ही बचाव व जोखिमों को कम से कम करने की तैयारी गांव स्तर पर कर ली जाए। इसके तहत 20 राज्यों में प्राकृतिक आपदा के मामले में संवेदनशील 81 जिलों को कार्ययोजना में शामिल किया गया है। इसके दायरे में कुल 1620 ग्राम पंचायतें आ रही हैं।

केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य स्वयं चिन्हित करें कि उनके क्षेत्र में जिस आपदा की आशंका सबसे अधिक रहती है, उसकी तैयारी के लिए एक गांव को माडल के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित करें। इसके बाद चिन्हित गांव की ग्राम पंचायत विकास योजना में संबंधित आपदा के प्रबंधन का एकीकरण किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण की योजना है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे सरपंच व अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण, पंचायत कार्यकर्ताओं के लिए कौशल विकास, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों के साथ सीधा जुड़ाव, सामुदायिक स्वयंसेवकों (आपदा मित्रों) तैयार करना, एनसीसी, एनएसएस के माध्यम से युवा संगठन तैयार करना, बहुस्तरीय शमन रणनीति आदि को शामिल किया जाएगा। यह दो वर्ष का कार्यक्रम वर्ष 2027 तक चलेगा, जिसमें बीस माडल गांव देशभर में तैयार हो जाएंगे। वह जिस कुशलता से आपदा से निपटेंगे, उसका अनुकरण देश के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए गत दिवस उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह कुल 507.37 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दे चुके हैं।

राज्य	चिन्हित जिले	आपदा प्रबंधन
उत्तर प्रदेश	छह	भूकंप या बाढ़
केरल	छह	तटीय क्षरण
ओडिशा	छह	चक्रवात या सूखा
असम	छह	बाढ़
महाराष्ट्र	छह	सूखा या भूकंप
राजस्थान	छह	सूखा या बाढ़
तमिलनाडु	पांच	चक्रवात या सूखा
बिहार	पांच	भूकंप या बाढ़
गुजरात	पांच	भूकंप या बाढ़
हिमाचल प्रदेश	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
उत्तराखंड	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
अरुणाचल प्रदेश	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
सिक्किम	तीन	भूस्खलन
मेघालय	तीन	बाढ़ या भूस्खलन
कर्नाटक	तीन	सूखा या भूस्खलन
आंध्र प्रदेश	तीन	चक्रवात या भूस्खलन
पंजाब	दो	भूकंप या नदी का कटाव
नगालैंड	दो	भूस्खलन
मिजोरम	दो	बाढ़ या भूस्खलन

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

****

2018 में शिअद ने पंजाब में जिला परिषद की 18 और ब्लाक समिति की 353 और भाजपा ने क्रमशः दो व 62 सीटें जीती थीं।

नितिन के उत्थान से बिहार भाजपा में कई चेहरे होंगे नवीन, अटकलें तेज

पटना के अतिपिछड़ा समाज से विधायक संजीव चौरसिया के साथ दो नेताओं का बढ़ सकता कद

मगध क्षेत्र में चंद्रवंशी समाज के दो नेताओं प्रेम कुमार एवं प्रमोद के उपरांत अब सवर्ण समुदाय ने पार्टी पर बढ़ाया दबाव

रमण शुक्ला • जागरण

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई दिल्ली में गुरुवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भेंट की। एएनआइ

पटना: नितिन नबीन का भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना महज एक व्यक्ति विशेष का उत्थान भर नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे पार्टी के व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रस्तावना के रूप में देखा जा रहा है। मकर संक्रांति के उपरांत भाजपा संगठन के साथ ही सत्ता में जिस तरह से फेरबदल की अटकलें तेज हैं, उसमें कई नेताओं के नवीन चेहरे के रूप में उभरने की संभावना प्रबल हो गई है। भाजपा कोटे के पथ निर्माण विभाग का प्रभार दिलीप जायसवाल को दिया जाना पिछड़ा वर्ग के लिए दूरगामी संदेश है।

संगठन के रणनीतिकारों के अनुसार पटना जिले से अतिपिछड़ा समाज से दीघा विधायक संजीव चौरसिया के साथ मगध के दो नेताओं के कद में उभार हो सकता है। वैश्य समाज से आने वाले संजीव चौरसिया की गिनती बिहार भाजपा के बड़े नेताओं में होती है। संजीव चौरसिया बिहार भाजपा के संस्थापक पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद के पुत्र हैं। संगठन में प्रदेश महामंत्री के साथ विभिन्न पदों पर अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। वहीं, मगध क्षेत्र में चंद्रवंशी समाज के दो नेताओं प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष, प्रमोद कुमार को सहकारिता एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन व वन विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाए जाने के उपरांत अब सवर्ण समुदाय का पार्टी पर दबाव बढ़ गया है।

उत्तर बिहार से सवर्ण मंत्री का कोटा रिक्त : भाजपा में उत्तर बिहार की बात करें तो पिछड़ा वर्ग से रमा निषाद, अरूण शंकर प्रसाद एवं नारायण प्रसाद को पार्टी ने मंत्री पद का दायित्व दिया है। ऐसे में अब सवर्ण कोटे का मंत्री पद रिक्त है। इसमें पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा एवं जिवेश कुमार को मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी मौका दे सकती है। इसी तरह 25 वर्षों से संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता एवं पार्टी में विभिन्न पदों पर अहम दायित्व निर्वहन कर चुके राजेश वर्मा को भी नितिन नवीन की जगह आगे करने पर मंथन जारी है। विदित हो कि दोनों एक समुदाय (कायस्थ) से हैं।

अप्रैल में राज्यसभा जा सकते हैं नवीन : भाजपा में चर्चा है कि नितिन नवीन मंत्री पद के उपरांत अप्रैल 2026 में विधायकी से भी त्याग पत्र देंगे। अप्रैल में बिहार से राज्यसभा की पांच सीटें रिक्त हो रही हैं। इनमें एक पद पर पार्टी नितिन नवीन को उच्च सदन भेजेगी। रिक्त होने वाली सीटों में राजद के प्रेम चंद गुप्ता एवं एडी सिंह हैं। दोनों सीटें भाजपा कोटे में आएंगी। जबकि जदयू के दो राज्यसभा सदस्यों के भी कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। इनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह एवं रामनाथ ठाकुर हैं। पांचवीं सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की है, जो खाली होगी। पांचों सदस्यों का कार्यकाल नौ अप्रैल, 2026 को समाप्त हो जाएगा।

बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: बंगाल में अगले साल विस चुनाव है। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारी शुरू दी है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को अकेले चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। बंगाल कांग्रेस का कहना है कि वाममोर्चा के साथ गठबंधन का कोई राजनीतिक फायदा नहीं है, इसलिए अकेले लड़ना ही सबसे मुफीद है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी माकपा नेतृत्व वाले वाममोर्चे दलों के गठबंधन वाममोर्चे के साथ समझौते के पक्ष में हैं।

प्रदेश की मौजूदा इकाई का मानना है कि अगर नेतृत्व ये तय करे कि वाममोर्चा के साथ गठबंधन हो तो 50-50 के फार्मूले पर हो। इससे पहले वाममोर्चा के साथ गठबंधन 2:1 के अनुपात पर होता था लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस आधे-आधे सीट पर लड़ना चाहती है।

प्रदेश कांग्रेस 100 से 125 सीट पर चुनाव गंभीरता से लड़ना चाहती है। ऐसे लगता है कि इस स्थिति में वह 15 से 25 सीट जीतने की स्थिति में होगी क्योंकि अभी भी दो तीन जिले जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार जैसे इलाकों में कांग्रेस की उपस्थिति अच्छी है। हालांकि, अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। शुक्रवार को कोलकाता में कांग्रेस की राज्य कमेटी की बैठक में इस पर विचार होगा। दरअसल, पिछले चुनावों में कांग्रेस को गठबंधन से निराशा हुई थी।

बंगाल में महात्मा गांधी के नाम से जानी जाएगी रोजगार गारंटी योजना: ममता

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- कहा- मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता का नाम हटाया जाना बेहद शर्मनाक
- अगर केंद्र राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकता तो हम देंगे

ममता बनर्जी। फाइल

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा यूपीए जमाने की मनरेगा रोजगार योजना का नाम बदलकर विकसित भारत- जी रामजी करने के कदम की गुरुवार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की।

ममता ने कोलकाता के धनधान्य आडिटोरियम में राज्य सरकार द्वारा आयोजित व्यापार व उद्योग सम्मेलन के मंच से बिना नाम लिए भाजपा व मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र द्वारा मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद शर्मनाक है। अगर वह लोग (भाजपा व केंद्र) राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकते तो हम देंगे। अब हम अपने राज्य की कर्मश्री योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखेंगे। ममता की ओर से यह घोषणा ऐसे समय आई है जब विपक्षी दलों के भारी विरोध व हंगामे के बीच गुरुवार को लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक या जीरामजी विधेयक पारित कर दिया, जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेगा। यह योजना ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों को रोजगार की गारंटी देता है।

दिसंबर, 2021 से बंद है राशि

बता दें कि मनरेगा की निधि बंद किए जाने पर ममता सरकार ने 2024 में कर्मश्री योजना शुरू की थी। भ्रष्टाचार के कारण दिसंबर, 2021 से ही केंद्र ने मनरेगा योजना में बंगाल की निधि रोक कर रखा है। इसको लेकर बंगाल सरकार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस साल एक अगस्त 2025 से केंद्र को बंगाल में मनरेगा योजना फिर से लागू करने का निर्देश दिया था। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए एक अगस्त से इसे लागू करने का निर्देश दिया था।

फ्लैट घोटाले में दोषी ठहराए गए महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे का त्यागपत्र मंजूर

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

- माणिकराव कोकाटे को तीन दशक पुराने फ्लैट घोटाले में मिल चुकी है दो साल की सजा
- स्वास्थ्य कारणों से एक अस्पताल में हो गए हैं भर्ती, कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में दी है चुनौती
- मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से कोकाटे की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ था

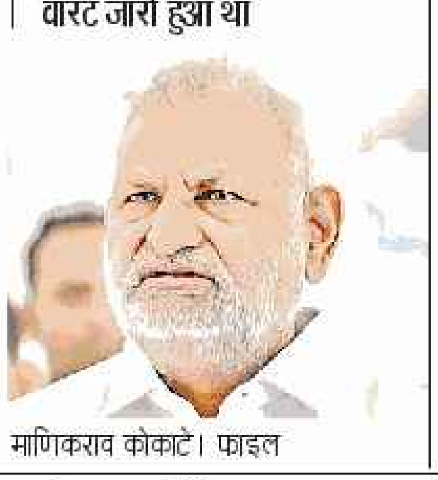

माणिकराव कोकाटे। फाइल

हुई थी लंबी बैठक

कोकाटे को सत्र न्यायालय से सजा सुनाए जाने के बाद बुधवार को अजीत पवार एवं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच एक लंबी बैठक हुई थी। इस बैठक में कोकाटे के मंत्रिमंडल से हटने के बाद उनके स्थान पर लिए जाने वाले व्यक्ति के बारे में चर्चा हुई थी।

महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे को तीन दशक पुराने फ्लैट घोटाले में दो साल की सजा मिलने के बाद उनके त्यागपत्र को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने स्वीकार कर लिया है। फड़णवीस ने कोकाटे का त्यागपत्र राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। कोकाटे को कुछ माह पहले नासिक के मजिस्ट्रेट कोर्ट से दो साल की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। कोकाटे ने इस सजा को जिला सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन सोमवार को सत्र न्यायालय ने भी मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा पर ही मुहर लगा दी। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से कोकाटे की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया है।

चूंकि कोकाटे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कोटे से खेलमंत्री बने थे, इसलिए यह प्रकरण सामने आने के बाद अजीत पवार एवं मुख्यमंत्री फडणवीस ने बैठककर त्वरित प्रभाव से कोकाटे का त्यागपत्र लेने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार, कोकाटे ने मंगलवार रात ही अपना त्यागपत्र अजीत पवार को सौंप दिया था। पवार ने गुरुवार को यह त्यागपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा, जिसे स्वीकार कर फडणवीस ने मंजूरी के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पास भेज दिया है।

इस बीच, कोकाटे स्वास्थ्य कारणों से एक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने सत्र न्यायालय के फैसले को बांबे हाई कोर्ट में चुनौती भी दे रखी है। उनकी याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अभी भाजपानीत महायुति सरकार के बने एक वर्ष ही हुए हैं। इसी दौरान भाजपा के सहयोगी दल राकांपा के दो मंत्रियों को अलग-अलग विवादों में घिरने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा है। कोकाटे से पहले धनंजय मुंडे अपना त्यागपत्र दे चुके हैं।

पलक्कड़ में भाजपा को रोकने को यूडीएफ-एलडीएफ गठबंधन की तैयारी

पलक्कड़, प्रेट्र: केरल में पलक्कड़ नगर पालिका पर भाजपा को फिर से काबिज होने से रोकने के लिए यूडीएफ-एलडीएफ गठबंधन की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी इसे स्वीकृति देने को तैयार है।

मुस्लिम लीग पलक्कड़ के जिला अध्यक्ष मरक्कर मारयामंगलम ने कहा कि हालांकि यूडीएफ ने इस संदर्भ में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उनकी पार्टी पलक्कड़ नगर पालिका में यूडीएफ-एलडीएफ गठबंधन का समर्थन करने के लिए तैयार है।

हालिया नगर पालिका चुनाव में 53 सीटों में से 25 भाजपा के खाते में गईं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले तीन कम हैं।

यूडीएफ को 17 पर जीत मिली, जबकि वाम दलों के गठबंधन एलडीएफ को आठ सीटों से संतोष करना पड़ा है। तीन निर्दलीय भी जीते हैं। उन्होंने कहा, 'हम इस तरह के गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के शासन में पलक्कड़ में कोई विकास नहीं हुआ है।'

पंजाब में जिला परिषद व ब्लाक समिति चुनाव में आप को प्रचंड बहुमत, भाजपा की सीटें बढ़ीं

कैलाश नाथ • जागरण

- जिला परिषद की 63 तो ब्लाक समिति की 54 प्रतिशत सीटों पर रही विजयी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। फाइल

शिअद को रास आया चुनाव

आठ वर्षों से राजनीतिक हाशिये पर चल रहे शिअद को यह चुनाव रास आया है। तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद शिअद बठिंडा और मुक्तसर जिला परिषद में अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब रहा है। बठिंडा की 17 में से 13 और श्री मुक्तसर साहिब की 13 में से सात सीटें शिअद जीती हैं। नवांशहर में कांग्रेस ने जिला परिषद की 10 में से छह सीटें जीतकर वहां अपना चेयरमैन बनाना पक्का किया है।

भाजपा का अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दावा पड़ा कमजोर

पहली बार अकेले लड़ रही भाजपा ने जिला परिषद और ब्लाक समिति में सीटें जरूर बढ़ाई हैं लेकिन 2027 में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दावा कमजोर पड़ गया है क्योंकि जिला परिषद चुनाव में 20 जिलों तथा ब्लाक समिति चुनाव में 11 जिलों में भाजपा का खाता ही नहीं खुल पाया। जिला परिषद में पठानकोट में चार और फिरोजपुर में तीन सीटें मिली हैं।

चंडीगढ़: पंजाब में जिला परिषद और ब्लाक समिति के चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। बुधवार सुबह आठ बजे शुरू हुई मतगणना देर रात तक जारी रही और आप ने 22 जिला परिषद के 347 सीटों में से करीब 63 प्रतिशत अर्थात 218 पर जीत हासिल की है। इसी तरह 154 ब्लाक समितियों के 2,838 में से आप के खाते में करीब 54 प्रतिशत अर्थात 1,531 सीटें आईं। इस चुनाव में कांग्रेस चाहे दूसरे स्थान पर रही लेकिन वर्ष 2018 के मुकाबले उसे कम सीटें मिली हैं। इस बार कांग्रेस के खाते में जिला परिषद की 62 और ब्लाक समिति की 612 सीटें आई हैं। 2018 में कांग्रेस को जिला परिषद की 331 और ब्लाक समिति में 2,351 सीटें मिली थीं। इस चुनाव में शिअद और भाजपा अलग-अलग चुनाव लड़ने के बावजूद अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब रहे हैं।

शिअद ने जिला परिषद की 46 और ब्लाक समिति की 445 सीटों पर जीत हासिल की है। इसी तरह भाजपा ने सात और 73 सीटें जीतीं। इससे पहले वर्ष 2018 में शिअद ने जिला परिषद की 18 और ब्लाक समिति की 353 और भाजपा ने क्रमशः दो व 62 सीटें जीती थीं। इस चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है लेकिन तीन जिला परिषद में विपक्ष का चेयरमैन बनना तय है।

राष्ट्रीय फलक

जल समस्या का समाधान होने पर पांच साल बाद विधायक ने कटवाए बाल

मुंबई, प्रेट्र : भाजपा विधायक राम कदम ने गुरुवार को कहा कि मुंबई के घाटकोपर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में जल संकट का समाधान करने का वादा पूरा करने के बाद उन्होंने पांच साल में पहली बार सिर के बाल कटवाए हैं। उन्होंने कहा कि बाल कटवाना जनता की जीत और उनसे किए गए वादे को पूरा करने का प्रतीक है।

समस्या से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताते हुए कदम ने कहा कि एक व्यापक योजना लागू की गई, जिसमें लगभग 20.7 मिलियन लीटर क्षमता वाले जल टैंक का निर्माण शामिल है। टैंक में पानी की आपूर्ति के लिए भांडुप से लगभग चार किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बिछाई गई। परियोजना के पूरा होने से घाटकोपर पश्चिम की हजारों बस्तियों और आवासीय समितियों को जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान के जनाधार कार्ड धारक दूसरे राज्यों में भी करवा सकेंगे 25 लाख तक का इलाज

जासं, जयपुर

- सबसे अधिक लाभ दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के निजी अस्पतालों में उपचार के लिए जाने वाले मरीजों को होगा

राजस्थान सरकार के आयुष्मान कार्ड धारक मरीज अब देश के किसी भी राज्य के निजी अस्पताल में 25 लाख रुपये तक की सीमा में उपचार करवा सकेंगे। ऐसे मरीजों को जनाधार कार्ड के साथ ही आयुष्मान कार्ड दिखाने पर यह सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार शुक्रवार से इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर रही है। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर तकनीकी प्रयास किए गए हैं। इससे देश में किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहे राजस्थान मूल के लोगों को लाभ मिल सकेगा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार इस योजना के माध्यम से लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारी का उपचार उनकी पसंद के अस्पताल में करवाने की सुविधा प्रदान करेगी। यह सुविधा 19 दिसंबर से लागू होगी।

साथ ही अन्य किसी भी राज्य की यात्रा करते समय बीमार होने वाले रोगियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यह सुविधा राज्य सरकार की ओर से अधिकृत अस्पतालों में ही मिल सकेगी। र

ाज्य सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक लाभ दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के निजी अस्पतालों में उपचार के लिए जाने वाले राजस्थान के मरीजों को होगा। इन राज्यों में प्रदेश के मरीज बड़ी संख्या में उपचार के लिए जाते हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार किसी भी अस्पताल में मरीज भर्ती होने अथवा उपचार करवाते समय संबंधित अस्पताल को अपना जनाधार कार्ड प्रस्तुत करेंगे। अस्पताल राजस्थान सरकार की स्टेट हेल्थ इश्योरेंस एजेंसी को कार्ड एवं मरीज का विवरण भेजेगी और वहां से अनुमोदन होने के बाद 25 लाख रुपये तक की सीमा में उपचार हो सकेगा। अब तक यह सुविधा राजस्थान के अधिकृत निजी अस्पतालों में ही मिलती थी। राज्य सरकार ने सोमवार से पूरे देश के अधिकृत अस्पतालों में उपचार करवाने के लिए यह सुविधा प्रारंभ की है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत दो हजार 370 बीमारियों के उपचार की सुविधा हैं। यह उपचार देश के 14 हजार निजी अस्पतालों में भी संभव हो सकेगा।

महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता प्रज्ञा सातव भाजपा में शामिल

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र में कांग्रेस की नेता और विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा सातव ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के उच्च सदन से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद भाजपा का दामन थाम लिया। सातव ने भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली जिले की रहने वाली प्रज्ञा सातव दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव सातव की पत्नी हैं। इन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। वह पहली बार 2021 में महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य चुनी गई थीं। स्थानीय निकाय चुनावों के बीच उनके इस्तीफे को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पति राजीव सातव के निधन के बाद उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। प्रज्ञा को जुलाई 2024 में दूसरी बार विधान परिषद के लिए नामित किया गया था।

चार भागों में बांटकर दिया जाता है लाभ

प्रथम पृष्ठ से आगे

विभाग के अधिकारियों के कहना है कि पीएम आवास योजना-शहरी के मुख्य चार घटक होते हैं। इनमें क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस), पार्टनरशिप में किफायती आवास (एएचपी), झुग्गीवासियों का इन-सिटू पुनर्वास (आइएसएसआर) और सब्सिडी प्राप्त व्यक्तिगत घर का निर्माण या विस्तार (बीएलसी) है। चारों घटकों का उद्देश्य पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। पीएम आवास योजना- शहरी 2.0 में आइएसएसआर की जगह किफायती किराये के आवास परिसर घटक को शामिल किया गया है।

42 शहरी निकायों में 99 हितग्राहियों ने पीएम ग्रामीण आवास योजना-शहरी और ग्रामीण दोनों का लाभ लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 52 हितग्राहियों ने दोनों योजनाओं के तहत आवास पूर्ण किए हैं। वहीं, 47 ने कार्य एक योजना में पूरा किया था और प्रगति दूसरी योजना में हुई थी।

अपात्र हितग्राहियों की जानकारी मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में पीएम आवास के माध्यम से लोगों के सपने साकार हो रहे हैं। कहीं भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से संज्ञान लेकर जांच कराई जाएगी।

\- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री

पुष्टि किए बिना 4.05 करोड़ रुपये जारी: सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि शहरी स्थानीय निकायों के दस्तावेजों की जांच में पाया गया है कि 250 हितग्राहियों द्वारा उनके नाम पर भूखंड के हस्तांतरण के दस्तावेज जमा किए बिना ही निर्माण कार्य शुरू किया गया है। निकायों ने हितग्राहियों के नाम पर भूमि हस्तांतरण सुनिश्चित किए बिना 250 हितग्राहियों को 4.05 करोड़ रुपये की सहायता का भुगतान किया गया। इस पर राज्य सरकार ने कहा है कि हितग्राहियों के नाम पर भूमि हस्तांतरण के दस्तावेजों का जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

जमशेदपुर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भिड़े भाजपाई व कांग्रेसी

जासं, जमशेदपुर: जमशेदपुर के साकची स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर कांग्रेसियों ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने "वोट चोर गद्दी छोड़" के नारे लगाए, जिसका जवाब भाजपाइयों ने नारेबाजी करके दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और जमकर नारेबाजी हुई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बीच में बैरिकेडिंग थी और पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग करने की कोशिश में जुटी रही। नारेबाजी के दौरान दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन बाद में स्थिति को संभालने के लिए कुछ बड़े नेताओं ने बीच-बचाव किया और दोनों पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को अलग किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि इस क्रम में उनके झंडे फाड़ दिए गए।

'चाहरदीवारी के भीतर हुई घटना 'पब्लिक व्यू' नहीं माना जा सकता'

जासं, जोधपुर

- एससी एसटी मामले में निचली अदालत के 31 साल पुराने फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट ने पलटा

अगर कोई घटना बंद दुकान या घर की चाहरदीवारी के भीतर होती है तो उसे 'पब्लिक व्यू' में नहीं माना जा सकता। जो इस एक्ट के लिए अनिवार्य शर्त है।" यह कहते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में एससी-एसटी मामले में निचली अदालत के 31 साल पुराने फैसले को पलट दिया।

कोर्ट के जज फरजंद अली ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि दो व्यक्तियों के बीच निजी या व्यावसायिक लेन-देन के विवाद को एससी-एसटी एक्ट का रूप देना कानून का सरासर गलत इस्तेमाल है।

कोर्ट ने 1994 में निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा को रद करते हुए आरोपी शोरूम मालिक को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने एक निजी विवाद में एससी-एसटी कानून के कड़े प्रविधान लागू करके कानून का गलत इस्तेमाल किया है।

नाजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कथित जातिसूचक अपमान या गाली किसी बंद दुकान, शोरूम या चाहरदीवारी के भीतर हुई हो, जहां आम जनता की मौजूदगी या दृश्यता न हो, तो उसे कानून की दृष्टि में 'सार्वजनिक दृष्टि में' किया गया कृत्य नहीं माना जा सकता।

मामला एक वाहन शोरूम संचालक से जुड़ा था, जिस पर आरोप था कि उसने एक ग्राहक के साथ जातिसूचक गाली-गलौज और मारपीट की।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को एससी-एसटी एक्ट की धारा के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने अपील में खारिज कर दिया।

अपनों की पहचान के लिए डीएनए रिपोर्ट का इंतजार

जागरण संवाददाता, मथुरा

मथुरा : कानपुर के राधा नगर निवासी अनुज श्रीवास्तव का शव लेने के लिए उनके पिता उमाकांत श्रीवास्तव ने बुधवार को डीएनए सैंपल दिया था। आज सैंपल की जानकारी लेने के लिए कलक्ट्रेट पहुंचे छोटे भाई शुभम, पत्नी ज्योति। जागरण

वे न घायलों की सूची में मिले और न मरने वालों की। पोस्टमार्टम हाउस के बाडी बैग में टुकड़ों के रूप में रखे शव उनके अपनों के हैं, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। रो-रोकर आंसू सूख चुके हैं, लेकिन आंखों में वहीं दृश्य बार-बार आ रहा है, जब वे बस में सवार हुए थे। अपनों को अंतिम विदाई देने के इंतजार में बैठे 15 परिवार बार-बार यही पूछ रहे हैं कि डीएनए रिपोर्ट कब आएगी। कोई कलेक्ट्रेट पहुंच रहा है तो कोई अस्पताल में फोन कर रहा है। रिपोर्ट आने में जितना समय लग रहा है, उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही है। सबकी निगाहें पोस्टमार्टम हाउस पर टिकी हैं कि कब उनका बुलावा आए और अपने का शव लेकर घर लौटें।

मंगलवार की सुबह चार बजे यमुना एक्सप्रेसवे के नोएडा की ओर जाने वाली साइड के माइल स्टोर 127 पर कोहरे में भिड़े 11 वाहनों में नौ खाक हो गए थे। हादसे में 19 की मौत हो गई थी, जबकि सौ से अधिक लोग घायल हुए। अब तक केवल चार शवों की ही पहचान हो सकी है। 15 शव बाडी बैग में पैक पोस्टमार्टम हाउस पर रखे हैं। इनकी पहचान के लिए बुधवार को 11 और गुरुवार को तीन लोगों ने डीएनए जांच के लिए रक्त के सैंपल दिए। एक सैंपल शुक्रवार को लिया जाएगा। उधर, पोस्टमार्टम हाउस में रखे शवों की भी डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया गया है। अब तक लिए गए 14 सैंपल को मिलान के लिए आगरा की लैब में भेजा गया है। समय शताब्दी बस की स्टीयरिंग में फंसकर जिंदा जले कानपुर के चालक सलीम रिजवी के बेटे अली अब्बास जांच के लिए सैंपल देकर घर लौट गए। वहां से अस्पताल के कर्मचारियों को फोन कर पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट कब तक आएगी। हादसे में जिंदा जले धौलपुर के भोलू की बहन सितारा ने बुधवार को डीएनए जांच के लिए सैंपल दिया था। गुरुवार को उनकी बेटी रेशमा पहुंची। बोली, अब्बू का शव कब मिलेगा?

समन की अवहेलना में दस्तावेज जमा करने को हेमंत सोरेन ने मांगा समय

राज्य ब्यूरो, जागरण • रांची: हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी हेमंत सोरेन की ओर से कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया। अदालत ने 15 जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की। हेमंत सोरेन ने एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में अदालत के संज्ञान को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया गया है। हेमंत के खिलाफ ईडी ने समन का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है, जिसमें सुनवाई जारी है। ईडी ने कहा है कि रांची के बड़गाईं अंचल स्थित एक भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में उनकी संलग्नता सामने आई है।

****

2 बाघ और एक तेंदुए के शिकार से जुड़ी हालिया खबरों को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वन्यजीव शिकार के मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया है। मार्च 2026 में प्रस्तावित अगली सुनवाई से पहले ही कोर्ट ने अचानक मामला सूचीबद्ध कर लिया।

कोलेजियम की पांच जजों को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोलेजियम ने गुरुवार को केंद्र को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पांच जजों की पदोन्नति की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में कोलेजियम ने दिन में एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के 9 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। बांबे हाई कोर्ट की न्यायाधीश रेवती पी. मोहिते डेरे को मेघालय के लिए सिफारिश की गई है, जबकि बांबे के न्यायाधीश एमएस सोनक को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के 8 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट के लिए पदोन्नत किया गया है। केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुश्ताक को सिक्किम के लिए पदोन्नत किया गया है।

आपरेशन सिंदूर कम समय में देश की हाई इंपैक्ट आपरेशनल क्षमता का सुबूत : राजनाथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- रक्षा मंत्री ने वायुसेना कमांडरों से भविष्य की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया
- कहा-21वीं सदी की लड़ाई केवल हथियारों की नहीं, बल्कि विचारों, प्रौद्योगिकी व अनुकूलन क्षमता की भी

नई दिल्ली में गुरुवार को वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्मृति चिह्न भेंट करते वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। प्रेट्र

आपरेशन सिंदूर को कम समय में भारत की हाई-इंपैक्ट आपरेशनल क्षमता का प्रदर्शन बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के कमांडरों से इससे सीख लेने और भविष्य की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। उन्होंने आपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार स्थित आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने में भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदर्शित साहस, गति और सटीकता की सराहना की। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की गैर-जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया का माकूल जवाब देने के लिए भी वायुसेना की प्रशंसा की और कहा कि इस आपरेशन ने हमारी सेनाओं, विशेष रूप से एयर डिफेंस क्षमता पर जनता के गहरे विश्वास को रेखांकित किया।

गुरुवार को वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को तकनीकी रूप से उन्नत, परिचालन के लिहाज से चुस्त, रणनीतिक दृष्टि से आत्मविश्वासी और भविष्योन्मुखी सैन्य बल बताया। उन्होंने कहा कि निरंतर बदलते वैश्विक परिवेश में यह राष्ट्रीय हितों की प्रभावी रक्षा कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब दुश्मन हमला करता है, तो लोग सुरक्षित स्थानों पर जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, तब हमारे नागरिकों ने शांत रहते हुए अपनी दैनिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रखीं। यह हमारी सेनाओं के आपरेशन तैयारियों पर प्रत्येक भारतीय के अटूट भरोसे का प्रमाण है।

तीनों सेनाओं के संयुक्त संचालन पर दिया जोर

राजनाथ ने आपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए तेजी से बदलते परिदृश्य में सेनाओं के संयुक्त संचालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्तता से हमारी सुरक्षा संरचना भी मजबूत होगी और दुश्मनों का सामना हम पहले से अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने भारत की एयर डिफेंस प्रणालियों तथा अन्य सैन्य उपकरणों के प्रभावी प्रदर्शन की भी सराहना की।

रक्षा मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की लड़ाई केवल हथियारों की नहीं, बल्कि विचारों, प्रौद्योगिकी और अनुकूलन क्षमता की भी है। रूस-यूक्रेन संघर्ष, इजरायल-हमास युद्ध, बालाकोट एयर स्ट्राइक और आपरेशन सिंदूर इस तथ्य के सशक्त प्रमाण हैं कि समकालीन परिदृश्य में वायुसेना एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरी है। साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूएवी, सेटेलाइट आधारित निगरानी और अंतरिक्ष-आधारित क्षमताएं युद्ध के स्वरूप को मूल रूप से बदल रही हैं। सटीक और निर्देशित हथियार, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और डाटा आधारित निर्णय-निर्माण अब वैकल्पिक नहीं रहे, बल्कि आधुनिक संघर्षों में सफलता के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं बन चुके हैं। जो देश प्रौद्योगिकी, रणनीतिक दूरदर्शिता और अनुकूलन क्षमता में दक्षता हासिल करेंगे, वही वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर होंगे।

वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी उपस्थित थे। वायुसेना प्रमुख ने इस दौरान वायुसेना की आपरेशन तैयारियों से रक्षामंत्री को अवगत कराया। इस सम्मेलन में वायुसेना नेतृत्व अपनी आपरेशनल प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श कर उभरती चुनौतियों के समाधान खोजने और रक्षा क्षमताओं में इजाफे के लिए अपने शीर्ष कमांडरों से रणनीतिक मंत्रणा करता है।

बांग्लादेश के खुलना, राजशाही में वीजा आवेदन केंद्र बंद किए गए

दोनों बांग्लादेशी शहरों में भारत विरोधी प्रदर्शनों के चलते लिया फैसला

विदेश मंत्रालय ने ढाका में वीजा केंद्र का संचालन फिर से शुरू किया

ढाका, एएनआइ : भारत ने बांग्लादेश के खुलना और राजशाही शहरों में भारत विरोधी प्रदर्शनों के कारण वीजा आवेदन केंद्र को बंद कर दिया है। जबकि भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी ने बताया कि एक दिन बाद ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वीजा केंद्र का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है।

ढाका में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया, "खुलना और राजशाही में प्रदर्शन हुए। जब भी सुरक्षा स्थिति खराब होती है, हमें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमने खुलना और राजशाही में वीजा केंद्र बंद कर दिए हैं। जबकि ढाका में भारत के वीजा आवेदन केंद्र को फिर से शुरू किया है।" राजशाही में भारत विरोधी वर्चस्व मंच "जुलाई 36 मंच" ने भारतीय सहायक उच्चायोग की ओर मार्च का आयोजन किया। मार्च दोपहर में शहर के भद्र मोर से शुरू होकर भारतीय सहायक उच्चायोग के कार्यालय की ओर बढ़ा। हालांकि, पुलिस ने इस कार्यालय से करीब सौ मीटर पहले बैरिकेड लगाकर जुलूस को रोक दिया। खुलना में भी ऐसे ही प्रदर्शनों का आह्वान किया गया। खुलना के दक्षिण-पश्चिमी और राजशाही के उत्तर-पश्चिमी आइवीएसी को सुरक्षा चिंताओं के आधार पर बंद किया गया। ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित आइवीएसी राजधानी में सभी भारतीय वीजा सेवाओं के लिए मुख्य एकीकृत केंद्र है। भारत ने ढाका में गुरुवार को अपने वीजा आवेदन केंद्र का संचालन फिर से शुरू किया है। एक दिन पहले इसे बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण बंद किया गया था।

बुधवार को बांग्लादेश पुलिस ने ढाका के गुलशन क्षेत्र में भारतीय उच्चायोग की ओर बढ़ रहे एक समूह के प्रदर्शनकारियों को रोका, जो पिछले साल जुलाई के विद्रोह के दौरान अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य की वापसी की मांग कर रहे थे।

बांग्लादेश के राजशाही में गुरुवार को भारत के उप उच्चायुक्त कार्यालय की तरफ बढ़ते प्रदर्शनकारियों को रोकती पुलिस। एएफपी

अवामी लीग के सदस्यों को देखते ही गिरफ्तार करने का निर्देश

ढाका, आइएएनएस : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे अवामी लीग के सदस्यों को बिना यह सत्यापित किए कि उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं या नहीं, देखते ही गिरफ्तार करें। स्थानीय मीडिया के अनुसार, उन्होंने यह टिप्पणी बुधवार दोपहर नारायणगंज जिले में की, जहां एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और सात मांगें रखीं। यह नवीनतम कदम मुहम्मद युनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत अवामी लीग के नेताओं पर बढ़ते दमन के संदर्भ में आया है। पिछले महीने अवामी लीग ने युनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर देश को "लाशों का डंपिंग ग्राउंड" बनाने का आरोप लगाया था। पार्टी ने आरोप लगाया कि देश भर में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बेतरतीब हत्याएं एक पूर्व-निर्धारित योजना के तहत की गईं।

चुनावों में हिंसा से अब भारत को सुलगाने में जुटी आइएसआइ

- 'जमात व एनसीपी भूमिका' वाली रणनीति पर काम कर रही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, आइएएनएस : बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले महत्वपूर्ण आम चुनावों से पहले ही व्यापक हिंसा की खबरों के मद्देनजर भारतीय एजेंसियां पड़ोसी देश में होने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ न केवल बांग्लादेश चुनावों में धांधली और हिंसा भड़काने की साजिश रच रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश कर रही है कि यह हिंसा भारत में भी फैले।

हिंसा भड़काने व उकसाने का काम नेशनल सिटिजन पार्टी को सौंपा गया : अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिए जाने के बाद अब सीधा मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी के बीच है। जनमत सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि यह मुकाबला कांटे का होगा क्योंकि जमात के लिए समर्थन तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हिंसा भड़काने और उकसाने का काम नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) को सौंप दिया गया है। आइएसआइ चाहती है कि जमात अच्छे पुलिस वाले की भूमिका निभाए और चुनावी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे, जबकि एनसीपी बुरे पुलिस वाले की भूमिका निभाए और हिंसा भड़काए।

यूनुस जमात की कठपुतली है, सारी कमान अब आइएसआइ के हाथों में: भारतीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है। शेख हसीना सरकार के पतन और मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किए जाने के बाद ढाका और नई दिल्ली के बीच संबंध बेहद खराब हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यूनुस जमात की कठपुतली मात्र है और आज सारी कमान आइएसआइ के हाथों में है। आइएसआइ इस बात से नाखुश है कि नई दिल्ली बीएनपी नेतृत्व के संपर्क में है। बीएनपी ने भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की इच्छा जताई है, जिससे पाकिस्तान बेचैन हो गया है।

बीएनपी सत्ता में आई तो आइएसआइ की भूमिका सीमित होने की आशंका: भारत के साथ मजबूत संबंध रखने वाली हसीना के शासनकाल में आइएसआइ बांग्लादेश में सक्रिय नहीं हो पाई थी। हालांकि, जमात समर्थित यूनुस के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो गई हैं। आइएसआइ को आशंका है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो उसकी भूमिका सीमित हो जाएगी क्योंकि यह पार्टी भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेगी। पिछली बीएनपी सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण थे क्योंकि नई दिल्ली ने बांग्लादेश सरकार पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खतरा पैदा करने वाले चरमपंथियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। बीएनपी इस स्थिति को सुधारना चाहती है और भारत के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना चाहती है।

भारत से संबंध सुधारना चाहती पार्टी: अतीत की तरह बीएनपी का जमात के साथ गठबंधन न करने का निर्णय ही इस बात का संकेत है कि वह भारत के साथ संबंध सुधारना चाहती है। खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान, भारत विरोधी भावना को भड़काने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वह चुनावों से पहले हिंसा भड़काने की भी कोशिश करेगा। इसका उद्देश्य चुनावों में धांधली करना और लोगों के मन में भय पैदा करना है ताकि जमात को फायदा मिल सके। असल मंशा बीएनपी समर्थकों को डराकर मतदान से दूर रखना है ताकि केवल जमात समर्थकों को ही वोट देने का मौका मिले। अवामी लीग के समर्थकों के चुनाव से दूर रहने की संभावना लगभग न के बराबर है। हालांकि, बीएनपी समर्थकों ने बड़ी संख्या में मतदान करने का फैसला किया है, और जमात इसे रोकना चाहती है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, अगर आदेश स्पष्ट तौर पर बेईमान हो तो क्या होगा?

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक त्रुटि और कदाचार के बीच अंतर बताते हुए सवाल किया, ''अगर आदेश स्पष्ट तौर पर बेईमान हो तो क्या होगा?'' उन्होंने यह भी कहा कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने का निर्देश दिया था। नतीजतन, न्यायिक अधिकारी अब 30 नवंबर, 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जब न्यायिक अधिकारी ने विवादित आदेश पारित किए थे, तब उन्हें सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने के बारे में नहीं पता था।

पीठ ने सवाल किया कि न्यायिक अधिकारी ने निलंबन को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क क्यों नहीं किया। इस पर सांघी ने कहा कि चूंकि निलंबन पूरे पूर्ण पीठ के फैसले पर आधारित था, इसलिए अधिकारी का मानना था कि सीधे सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगना ज्यादा सही होगा। इस पर पीठ ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही में हाई कोर्ट ने कई बार पूर्ण पीठ के फैसलों को रद किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि अधिकारी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने निलंबन का विवरण मांगा था। कोर्ट ने कहा, ''एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह जानकारी पाने के लिए आरटीआइ का रास्ता अपनाए। वह एक अभ्यावेदन दे सकता था।''

यूपी व केरल में एसआइआर का समय बढ़ाने की मांग पर जवाब को चुनाव आयोग को मिला समय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया तीन सप्ताह का समय
- एसआइआर की संवैधानिकता के मुद्दे पर आयोग छह जनवरी को रखेगा दलीलें

प्रतीकात्मक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और केरल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग को तीन सप्ताह का समय दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। इसके साथ ही गुरुवार को एसआइआर की वैधानिकता पर भी सुनवाई टल गई। अब चुनाव आयोग इस मामले में छह जनवरी को अपना पक्ष रखेगा।

मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के मामले गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगे थे। उत्तर प्रदेश में एसआइआर के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की गई है। यह याचिका कांग्रेस नेता तनुज पुनिया की ओर से दाखिल की गई है। गुरुवार को तनुज पुनिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और तय समय में एसआइआर का काम पूरा होना संभव नहीं है। वहां अभी निकट भविष्य में चुनाव भी नहीं होने हैं, ऐसे में वहां इसके लिए कोई जल्दी नहीं है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने दो सप्ताह का समय बढ़ाया है, लेकिन समय और बढ़ाया जाना चाहिए। केरल में एसआइआर का समय बढ़ाने की अर्जी पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की।

कपिल सिब्बल ने कहा कि आज एसआइआर के फार्म जमा करने का आखिरी दिन है। केरल में 25 लाख नाम डिलीट किए गए हैं। पति का नाम सूची में है और पत्नी का नाम डिलीट कर दिया गया है। यह स्थिति है। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग उत्तर प्रदेश और केरल के मामलों पर नजर रखे हुए है।

उत्तर प्रदेश में दो सप्ताह का समय बढ़ाया गया है और ऐसा नहीं है कि आगे समय बढ़ाने पर विचार नहीं हो सकता। राकेश द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश और केरल के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से तीन सप्ताह का समय मांग लिया।

कोर्ट ने समय देते हुए मामले को जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया।

पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में 13 स्थानों पर ईडी की छापेमारी

डंकी रूट मामला

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- जालंधर के रिची ट्रैवल्स पर कार्रवाई, मोबाइल, लैपटाप जब्त, नकद लेनदेन का आरोप
- भाजपा नेता समेत हरियाणा के पांच वीजा एजेंटों के घरों पर भी ईडी का छापा

प्रतीकात्मक

डंकी रूट से अमेरिका और अन्य देशों में भारतीयों को भेजने के मामले में ईडी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर छापे मारे हैं। गुरुवार सुबह से छापेमारी चल रही है। एएनआइ के अनुसार इस मामले में मिली कुछ सूचनाओं के आधार पर ईडी के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय की टीमें छापेमारी कर रही है। अवैध तरीके से विदेश जाने वाले रास्ते को डंकी रूट कहते हैं।

जागरण संवाददाता के अनुसार ईडी ने जालंधर के रिची ट्रैवल्स के परिसरों पर छापे मारकर मोबाइल, लैपटाप जब्त किए हैं। जसवंत नगर स्थित आवासीय परिसर पर भी ईडी की टीम पहुंची और रिकार्ड कब्जे में लिया। आरोप है कि रिची ट्रैवल्स ने विदेश भेजने के लिए करोड़ों का लेनदेन कैश में किया।

फरवरी 2025 में अमेरिका द्वारा सैन्य कार्गो विमान से निर्वासित किए गए 330 भारतीयों से संबंधित विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर इस मामले में ईडी ने जांच शुरू की है। अलग-अलग राज्यों में इस तरह के 19 मामले दर्ज किए गए हैं। पीड़ितों ने अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट अपनाया और इस नेटवर्क को कैश में करोड़ों रुपये दिए थे। सूचना के मुताबिक हर व्यक्ति ने अमेरिका जाने के लिए 45 से 50 लाख रुपये इस नेटवर्क से जुड़े लोगों को अलग-अलग समय दिए थे। हालांकि जालंधर में रिची ट्रैवल्स पर इस तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन डंकी रूट और विदेश भेजने के मामलों की जांच में आए एजेंट के साथ उसका संपर्क था।

वसूलते थे भारी भरकम रकम

ईडी ने नौ और 11 जुलाई को पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में दबिश दी थी। इन कार्रवाइयों की जांच के दौरान इनसे जुड़े साक्ष्य मिले। जांच में इस नेटवर्क में शामिल सुविधा देने वाले दूसरे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ लेने वाले तीसरे स्तर के लोगों के नाम सामने आए, जिनकी जांच चल रही है। डंकी रूट के माध्यम से लोगों को विदेश भेजकर कमाई करने वाले लोगों से जुड़ी 5.41 करोड़ रुपये के संपत्तियों को हाल ही में ईडी ने अटैच किया था। ईडी की जांच में पता चला कि ये एजेंट और उनके सहयोगी लोगों को अमेरिका में कानूनी रूप से भेजने का झांसा देते थे और इसके लिए भारी रकम वसूलते थे।

पानीपत के जागरण संवाददाता के अनुसार ईडी की टीमों ने कुरुक्षेत्र के पिहोवा, पानीपत के गांव अहर-कुराना और करनाल के निसिंग में पांच एजेंटों के घर छापामारी की। पांचों जगह ईडी की टीमें सुबह आठ बजे पहुंच गईं और देर रात तक जांच में जुटी रहीं। पानीपत का एजेंट बलवान अहर भाजपा नेता है और वर्ष 2005 में नौल्था विस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका है। दूसरा एजेंट प्रवीण पंचायत विभाग में खेल कोटे से ग्राम सचिव है। उसकी अभी करनाल जिले में पोस्टिंग है। उसके घर भी ईडी की टीम पहुंची। कुरुक्षेत्र के पिहोवा के वीजा एजेंट विशाल चावला के माडल टाउन स्थित घर पर भी छापेमारी की गई। ईडी को शक है कि विशाल ने डंकी रूट से लोगों को अमेरिका समेत अन्य देशों में अवैध रूप से भेजा और इसके बदले करोड़ों रुपये वसूले। विशाल के फरार होने की अटकलें हैं। कुराना गांव के प्रदीप के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। प्रवीण से पूछताछ के बाद प्रदीप के घर पर छापा मारा। दोनों पार्टनर हैं। ईडी अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रानिक उपकरण भी कब्जे में लिए हैं। जांच में पता चला कि डंकी रूट से अवैध रूप से अमेरिका भेजने के लिए ट्रैवल्स एजेंट्स, बिचौलिए, विदेशों में मौजूद उनके साथी, हवाला आपरेटर्स और रहने-खाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला पूरा नेटवर्क काम कर रहा था।

जम्मू कश्मीर

राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी तत्वों के पूरे तंत्र को नष्ट करने के लिए बड़ा कदम, पांच वर्ष में आतंकी गतिविधियों में लिप्त 88 कर्मियों की सेवाएं की गई हैं समाप्त

निजी क्षेत्र में भी नौकरी को पुलिस से क्लीन चिट जरूरी

नवीन नवाज • जागरण

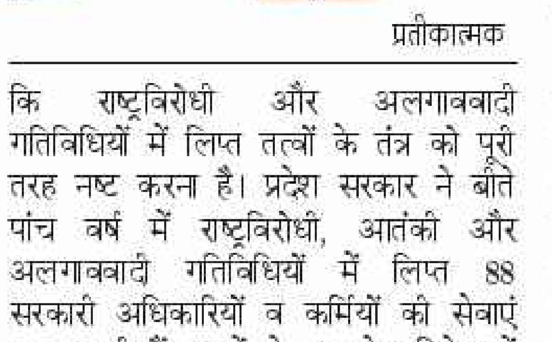

प्रतीकात्मक

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में सेवानिवृत्त होने के बाद निजी क्षेत्र में रोजगार की इच्छा रखने वाले सरकारी अधिकारियों व कर्मियों को अब पुलिस से क्लीनचिट लेनी होगी। बगैर इसके लिए उन्हें नौकरी देने वाली निजी कंपनी या व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

प्रशासन ने यह कदम भ्रष्टाचार और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर निकाले गए कर्मचारियों से निजी क्षेत्र को बचाने के लिए उठाया है। वर्तमान में सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए चयनित होने पर ही पुलिस से क्लीनचिट लेनी होती है। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार ने उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है, जिनमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपित कई अधिकारी और कर्मचारी निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन, सूत्र बताते हैं कि सरकार का मकसद कि राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त तत्वों के तंत्र को पूरी तरह नष्ट करना है। प्रदेश सरकार ने बीते पांच वर्ष में राष्ट्रविरोधी, आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त 88 सरकारी अधिकारियों व कर्मियों की सेवाएं समाप्त की हैं। इनमें से कुछ देश-विदेश में निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। आशंका है कि यह निजी क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाकर वहां भी आतंकी व अलगाववादियों के लिए वातावरण तैयार करेंगे।

डा. निसार का मामला बड़ा उदाहरण : सूत्रों ने बताया कि लाल किला के पास गत माह हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान पाया गया कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी में डा. निसार उल हसन को अलगाववादी विचारधारा के लिए दो वर्ष पूर्व जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने सरकारी सेवा से बर्खास्त किया था। डा. निसार को एनआइए ने हिरासत में लिया था।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मियों के लिए पुलिस की क्लीनचिट व सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी करते हुए कहा कि संबंधित लोगों की जांच और उन्हें अनुमति प्रदान करना पुलिस के सीआइडी विंग की जिम्मेदारी होगी। नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी को नौकरी पर रखने से पूर्व उसके चरित्र, उसकी पृष्ठभूमि की पुलिस से जांच कराए। इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सीईओ बोले-सबसे बुरा दौर बीत चुका है, इंडिगो ने 2,200 उड़ानें फिर से शुरू कीं

- पीटर एल्बर्स बोले- एयरलाइन का ध्यान व्यवधान के असल कारणों के विश्लेषण व पुनर्निर्माण पर है
- इतने कम समय में ऐसी स्थिति से उबरना हमारे टीम वर्क व संचालन सिद्धांतों की मजबूती का प्रमाण

मुंबई, प्रेट्र: इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को कहा कि चुनौतीपूर्ण दौर के बाद एयरलाइन और भी मजबूत होकर उभरी है। विमानों का परिचालन स्थिर होने और एयरलाइन द्वारा 2,200 उड़ानों का नेटवर्क बहाल करने के बाद "सबसे बुरा दौर बीत चुका है"। हाल की बाधाओं के दौरान एकजुट रहने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि एयरलाइन का ध्यान अब तीन चीजों पर है - लचीलापन, मूल कारण विश्लेषण और पुनर्निर्माण। उनका यह बयान इस महीने की शुरुआत में हजारों उड़ानें रद होने के परिणामस्वरूप लाखों यात्रियों को हवाई अड्डों पर होने वाली असुविधा और परेशानी के बाद आया है।

कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक वीडियो संदेश में एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो का ध्यान अब परिचालन के स्थिर होने के बाद एयरलाइन के पुनर्निर्माण पर है, और एयरलाइन के बोर्ड ने मूल कारणों के व्यापक विश्लेषण करने के लिए एक बाहरी विमानन विशेषज्ञ को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा, "नौ दिसंबर को मैंने इंडिगो के परिचालन में स्थिरता आने की जानकारी साझा की थी। उसके बाद, आज (गुरुवार) हमने अपने 2,200 उड़ानों के नेटवर्क को बहाल कर दिया है। अब हम तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं - लचीलापन, मूल कारण विश्लेषण और एयरलाइन का पुनर्निर्माण। इतने कम समय में ऐसी स्थिति से उबरना हमारे टीम वर्क और हमारे संचालन सिद्धांतों की मजबूती का प्रमाण है।"

गौरतलब है कि पायलटों के ड्यूटी पीरियड और आराम संबंधी नए नियमों को लागू करने में उचित योजना की कमी और कर्मचारियों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इंडिगो ने एक से नौ दिसंबर के बीच हजारों उड़ानें रद कर दी थीं। ये नियम एक नवंबर से लागू हुए थे। डीजीसीए समिति इंडिगो में परिचालन संबंधी व्यवधानों की जांच कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने इस महीने की शुरुआत में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद होने के बाद इंडिगो के मौजूदा शीतकालीन शेड्यूल में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी है।

****

26 टन संदिग्ध मांस को भोपाल पुलिस ने पकड़ा है। यह भोपाल से मुंबई के रास्ते विदेश भेजे जा रहा था। हिंदू संगठनों ने बुधवार रात गोमांस होने की शंका जताते हुए कंटेनर को रोका और पुलिस को सूचना दी थी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025

न्यूज गैलरी

बांबे हाई कोर्ट और स्थानीय अदालतों को उड़ाने की धमकी

मुंबई: बांबे हाई कोर्ट, कुछ स्थानीय अदालतों और दक्षिण मुंबई में स्थित दो प्रमुख बैंकों को गुरुवार को ईमेल के जरिये बम की धमकियां मिलीं। लेकिन, इन स्थानों में तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ये धमकियां झूठी निकलीं। एक अधिकारी ने बताया कि नागपुर की एक अदालत को भी इसी तरह की बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला था, जो फर्जी निकला। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, बांबे हाई कोर्ट, ,सत्र अदालत, दक्षिण मुंबई के मझगांव और एस्प्लेनेड अदालत, बांद्रा और अंधेरी में स्थित दो मजिस्ट्रेट अदालत और दो प्रमुख बैंकों को सुबह बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश स्थानों को तुरंत खाली करा लिया गया। बम निरोधक दस्ता बुलाया गया, लेकिन तलाशी में कहीं कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। (प्रेट्र)

रिप का स्टेट्स लगा युवक ने खुद को मार ली गोली

पाली: राजस्थान के पाली में बुधवार की रात एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह युवक को खेत पर चाय के लिए फोन किया गया था। फोन रिसीव नहीं होने पर मां के झोपड़ी में पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि युवक ने आत्महत्या की है। घटना से पहले युवक ने वाट्सअप पर अपने फोटो के साथ दो स्टेटस भी लगाए थे जिसमें आरआइपी यानी रिप लिखा हुआ था। पड़ताल में यह भी पता चला है कि युवक की पत्नी विवाह के कुछ समय बाद उसे छोड़कर चली गई थी तब से वह लगातार अवसाद में था। पाली के बगड़ी नगर थानाधिकारी प्रहलाद सिंह घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे, एमओबी और एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल से जुड़ी जानकारी में यह सामने आया कि रामलाल शादीशुदा था, शादी के कुछ महीने बाद ही पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वह 3 साल से मायके में रह रही है। इसके चलते वह डिप्रेशन में रहने लगा था। (जासं)

भड़काऊ भाषण मामले में आजम खां दोषमुक्त

रामपुर : सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के साढ़े छह साल पुराने एक मामले में राहत मिल गई है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश शोभित बंसल ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए 42 पेज के निर्णय में आजम खां को दोषमुक्त करार दिया। इस दौरान सपा नेता रामपुर जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। अब तक आजम के 15 मामलों में फैसला आ चुका है। (जासं)

खंडपीठ की अध्यक्षता कर सकते हैं तदर्थ के रूप में कार्यरत पूर्व जज

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए की अहम टिप्पणी

हाईकोर्ट के पूर्व जजों को तदर्थ के रूप में नियुक्त करने की नीति बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने 2021 के फैसले में संशोधन करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जिन्हें बाद में आपराधिक मामलों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तदर्थ जज के रूप में नियुक्त किया गया था, एकल जज वाली पीठ या खंडपीठ की अध्यक्षता कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हाईकोर्ट के पूर्व जजों को तदर्थ जजों के रूप में नियुक्त करने के संबंध में एक नीति बनाने या मौजूदा नीति में सुधार करने को कहा। साथ ही, यह भी कहा कि "न्यायिक प्रतिभा का एक विशाल भंडार है...वे 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और उनके अनुभव का उपयोग लंबित मामलों को निपटाने के लिए किया जा सकता है"।

गौरतलब है कि तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 20 अप्रैल, 2021 को हाईकोर्ट्स में लंबित लगभग 57 लाख मामलों का संज्ञान लेते हुए इसे "मामलों का विस्फोट" करार दिया था। इसने आपराधिक मामलों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए दो से तीन साल की अवधि के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की तदर्थ नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था।

पूर्व जजों के कार्यकाल, उनकी संख्या और प्रतिशत के संबंध में कई दिशानिर्देश निर्धारित करते हुए, जिन्हें तदर्थ जजों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, पीठ ने कहा था कि तदर्थ जज एक नियमित जज की अध्यक्षता वाली पीठ में बैठेंगे और लंबित आपराधिक अपीलों पर निर्णय लेंगे।

गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने आदेश के एक पहलू में संशोधन करते हुए कहा कि पूर्व जज भी एकल जज वाली पीठों की अध्यक्षता कर सकते हैं और उन्हें खंडपीठ में बैठते समय नियमित जजों का कनिष्ठ सहयोगी नहीं बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्थिति और आवश्यकता के आधार पर एक नियमित और एक तदर्थ जज या यहां तक कि दो तदर्थ जजों वाली एक खंडपीठ का गठन कर सकते हैं।

चीफ जस्टिस ने कहा, "कई पूर्व जजों ने मुझसे बात की है। वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं और काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन खंडपीठों में कनिष्ठ जज के रूप में बैठने में उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस मौजूदा जज को पूर्व जज के साथ पीठ में सहयोगी के रूप में बैठने के लिए मना सकते हैं।"

संवैधानिक अदालतें ही दे सकती हैं बिना छूट के उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बिना किसी छूट के उम्रकैद की सजा देने का अधिकार केवल संवैधानिक अदालतों को प्राप्त है, सत्र न्यायालयों को नहीं। पीठ ने कहा कि सत्र न्यायालय द्वारा सजा में छूट या कमी करने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है। सत्र न्यायालय द्वारा उम्रकैद की सजा को जीवनभर के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता के प्रविधानों के विपरीत होगा। पीठ ने कहा-माफी या सजा कम करने की राज्य को दी गई शक्ति को छीना नहीं जा सकता। निचली अदालत द्वारा दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए पुष्टि की गई सजा को आजीवन कारावास के रूप में मंजूरी दी जाती है। शीर्ष अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक व्यक्ति ने यौन संबंध बनाने से इन्कार करने पर एक विधवा की आग में जलाकर हत्या कर दी थी।

भारत तेजी से वैश्विक गतिविधियों का केंद्र बन रहा : मोहन भागवत

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी

- सरसंघचालक ने कहा- युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की धुरी है
- स्वयं को हिंदू कहने वालों को संगठित होने की आवश्यकता

सिलीगुड़ी के शताब्दी सदन में युवा सम्मेलन को संबोधित करते संघ प्रमुख मोहन भागवत।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की धुरी हैं। भारत तेजी से वैश्विक गतिविधियों का केंद्र बन रहा है और विविधता के संकट से जूझ रही दुनिया को आने वाले समय में भारत के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। यह बातें उन्होंने गुरुवार को दो दिवसीय प्रवास पर बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचने पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहीं। विश्वास व्यक्त किया कि भारत विश्वगुरु के रूप में उभरेगा।

उत्तर बंगाल के आठ जिलों और पड़ोसी राज्य सिक्किम से आए करीब 7500 युवक-युवतियों की उपस्थिति वाले युवा सम्मेलन में डा. भागवत ने कहा कि स्वयं को हिंदू कहने वालों को संगठित होने की आवश्यकता है। भारत की भक्ति के बिना हिंदुत्व की भावना अधूरी है। संघ पिछले 100 वर्षों से देश सेवा में लगा हुआ है। इस दौरान उसे उपेक्षा, विरोध और आक्रमण का सामना करना पड़ा, लेकिन संगठन कभी नहीं झुका और निरंतर आगे बढ़ता रहा।

संघ प्रमुख ने कहा कि संगठन भले ही बड़ा हो, लेकिन लक्ष्य देश के हर व्यक्ति को जोड़ना है। संविधान पढ़ने पर जोर देते हुए कहा कि यह हमारे पूर्वजों, प्राचीन संस्कृति और परंपराओं की चेतना को जीवित रखता है। भाषा, पहनावा, खान-पान और आराध्य देव भले अलग हों, लेकिन संस्कृति और परंपरा के आधार पर सभी सनातनी हिंदू हैं। समाज और व्यवस्था निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण जरूरी है। जब-जब देश पर संकट आया है, तब-तब समाज जागृत हुआ है। इस अवसर पर सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर, उत्तर बंगाल प्रांत संघचालक हृषिकेश साहा समेत संघ के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान सरसंघचालक ने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए। कार्यक्रम आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा था।

बंक करने पर बच्चों को बेरहमी से पीटने वाला अध्यापक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

- फरीदाबाद पुलिस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में अन्य विद्यार्थियों से की पूछताछ
- पहले भी छात्रों पर बरसा चुका है डंडे, अध्यापक का खंगाला जा रहा रिकार्ड

स्कूल बंक करने पर विद्यार्थी के तलवों पर बेरहमी से अंधाधुंध डंडे बरसाने वाले अध्यापक नरेंद्र राठी को गुरुवार सुबह सारन थाना पुलिस ने स्कूल से गिरफ्तार कर लिया। वह अक्सर बच्चों की इसी तरह पिटाई करता था। पूर्व में कई विद्यार्थियों को पीट चुका है। पुलिस अध्यापक का पुराना रिकार्ड खंगाल रही है। अध्यापक इससे पहले जिस स्कूल में रहा है, वहां के स्टाफ व बच्चों से भी पूछताछ की जा सकती है।

सारन स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल के अध्यापक ने मंगलवार को नौवीं के विद्यार्थियों को डंडों से पीटा था। दोनों विद्यार्थी एक दिन पहले स्कूल से बिना बताए घर चले गए थे। अध्यापक इसी बात से नाराज था। अध्यापक नरेंद्र राठी ने कक्षा में प्रवेश करते ही दोनों विद्यार्थियों को यह कहकर बाहर भेज दिया कि तुम दोनों को पढ़ना ही नहीं है, बाहर बैठो। आधे घंटे तक ठंड में दोनों बाहर ही बैठे रहे। इसके बाद अध्यापक ने उन पर डंडे बरसाए।

इसका वीडियो कक्षा के ही एक अन्य विद्यार्थी ने छिपकर रिकार्ड कर लिया था। बाल कल्याण समिति द्वारा विद्यार्थियों के बयान किए गए।

विद्यार्थी बोले- अध्यापक ऐसे ही करते हैं पिटाई: विद्यार्थियों ने बताया कि अध्यापक कक्षा में अनुशासन और पढ़ाई के लिए इस तरह से पिटाई करते हैं। अध्यापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वजन ने कहा कि अध्यापक को बचाने के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से अलग-अलग बयान दिए जा रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि बच्चों की इस कदर पिटाई हुई है। सीडब्ल्यूसी के पूर्व चेयरमैन श्रीपाल कराहना ने कहा कि बच्चों को बर्बरता से पीटना, उपेक्षित करना और कक्षा के बाहर अनावश्यक खड़ा रखने पर जेजे एक्ट के तहत अध्यापक पर कार्रवाई की जाती है।

'सर तन से जुदा' नारा देश की संप्रभुता को चुनौती

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज

- बरेली में सितंबर में हुई हिंसा के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज करते हुए की महत्वपूर्ण टिप्पणी

इलाहाबाद हाई कोर्ट। फाइल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि किसी व्यक्ति या भीड़ का लगाया नारा 'गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा...सर तन से जुदा, सर तन से जुदा' कानून के अधिकार के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि यह लोगों को हथियारबंद विद्रोह के लिए उकसाता है। इसलिए यह न केवल बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय होगा, बल्कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। उक्त टिप्पणी के साथ एकलपीठ ने बरेली में सितंबर 2025 में हुई हिंसा में मौलाना तौकीर रजा के सहयोगी रेहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

अभियुक्त के खिलाफ बरेली कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है। उसके अधिवक्ता का कहना था कि गलत तरीके से फंसाया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार इत्तेफाक मिन्नत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा व नदीम खान ने मुस्लिम समुदाय को इस्लामिया इंटर कालेज मैदान में इकट्ठा होकर राज्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। निषेधाज्ञा के बावजूद 26 सितंबर 2025 को नमाज के बाद वहां इकट्ठा हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नदीम खान के घर से भीड़ निकली और सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिसमें 'गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा' नारा भी लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। उनकी वर्दी फाड़ दी और पेट्रोल बम चलाने के साथ ही गोलीबारी और पत्थरबाजी की। इससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई पुलिस तथा निजी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके से सात लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें रेहान भी है। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न धर्मों में नारों और घोषणाओं की बात है। आमतौर पर लोग अपने धर्म के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इसे उपयोग में लाते हैं। मुस्लिम समुदाय में 'नारा-ए-तकबीर' के बाद 'अल्लाहु अकबर' है, जिसका अर्थ है कि भगवान सबसे महान हैं और इसमें कोई विवाद नहीं है। इसी तरह, सिख धर्म में 'जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' कहते हैं। यह नारा गुरु गोबिंद सिंह ने लगाया था। यह भगवान को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करता है। हिंदू धर्म में भी 'जय श्रीराम' या 'हर हर महादेव' जैसे नारे खुशी और आनंद के अवसरों पर उपयोग किए जाते हैं। इन नारों का उपयोग तब तक अपराध नहीं है, जब तक कि वे दूसरे धर्मों के लोगों को डराने या धमकाने के लिए उपयोग नहीं किए जाते। हालांकि, 'गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा' नारा कुरान या अन्य मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों में नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी कई मुस्लिम लोग इसका उपयोग करते हैं बिना इसके सही अर्थ और प्रभाव को जाने हुए।

गौ सेवकों पर रील बनाना युवक को पड़ा भारी, मारपीट कर गांव में घुमाया

जासं, जयपुर : राजस्थान के जयपुर जिले में इंटरनेट मीडिया पर गौ सेवकों पर रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। रील सामने आने के बाद रील बनाने वाले युवक के साथ लोगों ने मारपीट की। मारपीट के बाद कस्बे में गिरेबान पकड़कर पूरे गांव में घुमाया गया। बनवारी को जो लोग कस्बे में घुमा रहे थे उनकी टी शर्ट के पीछे गौरक्षक लिखा हुआ था। तूंगा पुलिस थाना अधिकारी राम मीणा ने बताया कि घटना 17 दिसंबर की है। बनवारी की तूंगा में फुटवेयर की दुकान है। घटना के दिन गौरव शर्मा और उसके दो दर्जन साथी बनवारी की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकान पर पहुंचते ही बनवारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस संबंध में बनवारी ने 17 दिसंबर को ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दरअसल, पूरे विवाद का कारण यह है कि बनवारी ने रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की थी। रील में बनवारी ने गौ रक्षकों को लेकर अपशब्द बोलते हुए कहा था कि पहले माता-पिता को रोटी दो। माता-पिता रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में मतांतरित के शव दफनाने पर विवाद, गुस्साई भीड़ ने प्रार्थना घर फूंका

नईदुनिया न्यूज, कांकेर

- कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के गांव में पिछले तीन दिनों से तनावपूर्ण स्थिति
- मतांतरित सरपंच के घर में भी आग लगाई, ग्रामीण व पुलिसकर्मी भी घायल

कांकेर जिले के बड़ेतेवड़ा गांव में आक्रोशित लोगों ने फूंका प्रार्थना घर। नईदुनिया

छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के बड़ेतेवड़ा गांव में पिछले तीन दिनों से मतांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारी विरोध के चलते प्रशासन ने गुरुवार को स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए शव को कब्र से बाहर निकालकर सुरक्षित रखा। इसके बावजूद आक्रोशित भीड़ ने एक प्रार्थना घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। गुस्साई भीड़ ने सरपंच के घर में भी तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी।

बता दें कि जिले में मतांतरण बड़ा मुद्दा है। पिछले पांच महीने में यहां 14 गांवों में ग्रामीणों ने पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीते रविवार को बड़ेतेवड़ा गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता 70 वर्षीय चमराराम सलाम की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। सरपंच ने पिता का शव गांव में ही दफनाया। इस सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव दफनाने का विरोध किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। गुरुवार को फिर से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को कब्र से निकालकर दूसरे स्थान पर अंतिम संस्कार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांकेर के एडिशनल एसपी दिनेश कुमार सिन्हा ने बताया कि शव को दफनाने में दो पक्षों में विवाद हुआ था और स्थिति नियंत्रण में है।

आदिवासी समाज दो धड़ों में बंट चुका है। एक ओर मूल आदिवासी हैं, जो मतांतरित व्यक्ति के अंतिम संस्कार का विरोध कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर ईसाई परिवार है, जो अपने खेत में दफनाए गए शव को निकालने नहीं दे रहे थे।

बिहार में चाइनीज पिस्टल व एके-47 की गोलियों के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार

जासं, बिहारशरीफ: नालंदा पुलिस ने बिहार एसटीएफ (विशेष कार्य बल) के साथ सोहनकुआं मुहल्ले में छापेमारी कर अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। मौके से मुंगेर और झारखंड के पांच तस्करों को भारी मात्रा में हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में तीन तस्कर सगे भाई है और झारखंड के रहने वाले हैं। उनके पास से मेड इन चाइना लिखी पांच पिस्टल, एके-47 के 153 कारतूस, 11 मैगजीन और 24 हजार नकदी बरामद हुई। स्कार्पियो भी जब्त की गई है।

गुरुवार को एसपी भारत सोनी ने प्रेसवार्ता में बताया कि जिस फ्लैट से हथियार बरामद हुए, उसे मुंगेर निवासी सौरव झा ने किराए पर लिया था। वह बिचौलिया था, उसी ने परवेज और झारखंड के तस्करों के बीच संपर्क कराया था। परवेज को वर्ष 2013 में भी पुलिस ने छह सौ कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जबकि, झारखंड के तीनों भाई हत्या समेत अन्य संगीन मामलों में जेल जा चुके हैं।

बिहार के गोलालगंज में थावे दुर्गा मंदिर से एक करोड़ के आभूषण के साथ लाकर की चोरी

जासं, थावे (गोपालगंज)

- सीढ़ी-रस्सी के सहारे गर्भगृह तक पहुंचे दो चोर, टीओपी प्रभारी निलंबित
- सैप जवानों को सेवामुक्त करने की सिफारिश, एक लाख इनाम घोषित

प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में विराजी मां के इसी स्वर्ण मुकुट व छत्र की चोरी हुई। फाइल फोटो

बिहार के गोपालगंज जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने बुधवार की देर रात ताला काटकर लगभग एक करोड़ के आभूषण के साथ लाकर की चोरी कर ली। चोरी गए सामान में मां के सोने का मुकुट, सोने का हार, सोने की छतरी, चांदी का हार व लाकर शामिल हैं। दो चोर सीढ़ी व रस्सी के सहारे गर्भगृह तक पहुंचे और मात्र 21 मिनट में चोरी कर भाग निकले। चोरी की जानकारी गुरुवार की सुबह मंदिर में आरती करने पहुंचे तीन पुजारियों व एक सैप जवान को हुई। मंदिर के गर्भगृह का तीन ताला टूटा हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना पर सारण डीआइजी नीलेश कुमार व एसपी अवधेश दीक्षित पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में दो चोरों की करतूत सामने आई। एसपी ने घटना के राजफाश के लिए एसआइटी का गठन कर दिया है। मंदिर टीओपी के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, वहीं चार सैप जवानों को सेवामुक्त करने की सिफारिश कर दी गई है। पुलिस ने पहचान करने वाले को एक लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है। मौके पर डाग स्क्वायड व फोरेंसिक टीम ने भी जांच की है। लाकर मंदिर से लगभग डेढ़ किमी दूर वनक्षेत्र में टूटा हुआ मिला है। जांच में सामने आया है कि चोर मंदिर की सुरक्षा से पूरी तरह अवगत थे। सीसीटीवी में रात 11.53 बजे से चोरों की करतूत कैद हुई है। मंदिर के पीछे दक्षिणी दिशा में मां चौका व प्रशासनिक भवन के निर्माण स्थल पर रखी सीढ़ी का इस्तेमाल कर दोनों चोर भवन पर चढ़े। रस्सी के सहारे मंदिर के अंदर उतरे।

तीन मंदिरों से एक ही रात चोरी

घने कोहरे का लाभ उठाकर चोरों ने बुधवार की रात केवल थावे मंदिर ही नहीं, बल्कि छपरा के ख्यात धर्मनाथ धनी मंदिर, वैशाली के तिसिऔता थाना परिसर स्थित शिव शक्ति धाम एवं महथी धर्मचंद बाबा विशंभर नाथ मंदिर से कीमती आभूषण व दानपात्र से नकद चोरी कर ली।

महाठग को रिमांड पर लेने की तैयारी, सोनू सूद के जवाब पर भरोसा नहीं

जागरण संवाददाता, कानपुर

- पुलिस ने अभिनेता सोनू के ई-मेल से भेजे जवाब को माना नाकाफी, कहा- शहर आकर दें 244 सवालों के उत्तर

भारत, यूएई, जापान व अमेरिका समेत 10 देशों के 1000 लोगों से 970 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अब महाठग रवींद्रनाथ सोनी को रिमांड पर लेने की तैयारी है, जबकि अभिनेता सोनू सूद के जवाब पर पुलिस को भरोसा नहीं है। उनके अधिवक्ता की ओर से ई-मेल से भेजे गए जवाब को पुलिस ने नाकाफी बताया है। कहा कि विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने 244 प्रश्न तैयार किए हैं, जिनका उत्तर देने के लिए उन्हें शहर आना होगा। सामने उपस्थित होकर दिए गए उत्तर ही स्वीकार किए जाएंगे। वहीं, रेसलर खली को भेजे गई तीन नोटिसों के जवाब का पुलिस अभी इंतजार कर रही है। महाठग के देहरादून वाले घर से बरामद मोबाइल फोन, लैपटाप, हार्डडिस्क व अन्य साक्ष्यों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है।

दिल्ली के मालवीय नगर निवासी महाठग रवींद्रनाथ सोनी व उसके साथियों के विरुद्ध अब तक 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दो मुकदमों में उसका साझेदार अभिनेता सूरज जुमानी भी आरोपित है। एसआइटी को रवींद्रनाथ के साथ अभिनेता सोनू सूद, रेसलर खली, कई पूर्व क्रिकेटर, महिला खिलाड़ी, राजनेताओं समेत चर्चित हस्तियों के वीडियो व फोटो मिले थे। सोनू सूद पर आरोप लगे थे, जिसके बाद एसआइटी ने उनको और खली को तीन नोटिस भेजीं। सोनू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ई-मेल से भेजे जवाब में कहा कि वह दो बार कंपनी के कार्यक्रम में दुबई गए थे।

मुगल और अंग्रेजों के बाद अब राज्य सरकारें कर रहीं मंदिरों के धन का दुरुपयोग

जागरण संवाददाता, मेरठ

- विहिप की केंद्रीय प्रन्यासी मंडल बैठक के तीसरे दिन मंदिरों के धन के दुरुपयोग पर हुई चर्चा
- हिंदू मंदिरों का पैसा हिंदू समाज व मंदिर के हित पर खर्च करने की उठाई गई मांग

हस्तिनापुर में कार्यक्रम में मासिक पत्रिका गऊ संपदा का विमोचन करते विहिप के पदाधिकारी। सौ विहिप

विहिप की पांच दिवसीय केंद्रीय प्रन्यासी मंडल बैठक के तीसरे दिन गुरुवार को मंदिरों के धन के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा हुई। केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने कहा कि मुगल शासनकाल में मंदिरों को नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयत्न लंबे समय तक चला। अंग्रेजों ने कानून बनाकर मंदिरों के धन का दुरुपयोग करने का मार्ग खोला था। अब राज्य सरकारें भी मंदिरों के धन का दुरुपयोग कर रही हैं, यह उचित नहीं है।

बांगड़ा ने कहा कि जब तक मंदिर अपनी मूल भूमिका के साथ सक्रिय थे तब तक देश, समाज और परिवार संस्था भी सुरक्षित और संस्कारित थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि मंदिरों का चढ़ावा और धन भगवान की संपत्ति है। इसे केवल मंदिर के हित में ही उपयोग किया जाए। देशभर में मंदिरों के लिए एक समान कानून होना आवश्यक है, मंदिर सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना भी आवश्यक है। बैठक में धर्मांतरण को रोकने और घर वापसी को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए भी एक कार्ययोजना बनाई गई। इन विषयों पर एक पुस्तक घर वापसी -क्यों और कैसे के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का भी विमोचन किया गया गया। गोरक्षा व गऊ संवर्धन के लिए मासिक पत्रिका गऊ संपदा का भी विमोचन हुआ। बैठक में वंदे मातरम् के 150 वर्ष होने पर उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कर्नाटक में कालेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार

- प्रेमी ने निजी क्षणों का वीडियो बनाकर पीड़िता को किया ब्लैकमेल

बेंगलुरु, आइएएनएस : कर्नाटक में पुलिस ने रामनगर जिले से रिपोर्ट किए गए कालेज की एक छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पीड़िता का प्रेमी भी शामिल है। यह गिरफ्तारी 19 वर्षीय पीड़िता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद की गई।

आरोपितों में से एक पीड़िता का प्रेमी है जिसने उससे शारीरिक संबंध बनाए। उनके निजी क्षणों को रिकार्ड किया और बाद में उस वीडियो का उपयोग करके उसे ब्लैकमेल किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान विकास, पीड़िता के प्रेमी और उसके दोस्तों प्रशांत और चेतन के रूप में की गई है। विकास और प्रशांत बेंगलुरु के एक निजी कालेज के छात्र हैं, जबकि चेतन मैगडी शहर में एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करता है। विकास ने लगभग सात महीने तक पीड़िता का पीछा किया और बार-बार उससे अपनी भावनाओं का प्रतिकार करने की गुहार लगाई। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने उसे अपने दोस्त चेतन के घर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और मोबाइल फोन पर गुप्त रूप से रिकार्ड किया।

विकास ने बाद में वीडियो पीड़िता को भेजा और उसे ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि यदि उसने उसकी मांगों का पालन नहीं किया तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देगा। उस पर यह आरोप है कि उसने पीड़िता को जब भी मिलने के लिए कहा और मजबूर किया। पुलिस ने कहा कि विकास ने फिर से पीड़िता को चेतन के घर ले जाकर, जहां सभी तीन आरोपितों ने पीड़िता से दुष्कर्म किया।

****

500 से अधिक माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं शीर्ष माओवादी नेताओं सहित पिछले दो वर्षों में। लगभग ढाई हजार माओवादी हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौट चुके हैं।

न्यूज गैलरी

छुट्टी से लौटे बीएसएफ जवान ने खुद को गोली मार दी जान

नारायणपुर : छत्तीसगढ़ के माओवादी हिंसा प्रभावित नारायणपुर जिले में बुधवार शाम को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिंगोली निवासी बीएसएफ जवान सचिन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

सचिन कुमार

घटना सोनपुर थाना क्षेत्र के होरादी स्थित बीएसएफ कैंप की है, जहां जवान माओवादी मोर्चे पर तैनात था। वह तीन दिन पहले ही छुट्टी पर घर जाकर लौटा था। इसके बाद उसने यह कदम उठा लिया। पुलिस अधीक्षक राबिंसन गुड़िया ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में किसी साजिश या बाहरी कारण के संकेत नहीं मिले हैं। मृत जवान सचिन कुमार लंबे समय से माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात था। पुलिस के साथ बीएसएफ की आंतरिक जांच टीम मामले की पड़ताल कर रही है। (नईदुनिया न्यूज)

अमृतपाल की संसद में हिस्सा लेने की याचिका निरस्त

चंडीगढ़ : असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब वह शुक्रवार को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले पाएगा। पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में ही यह सवाल उठाया कि यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई आदेश पारित भी कर दिया जाए, तो उसे कैसे लागू किया जाएगा। अमृतपाल इस समय असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद है और उन्हें दिल्ली लाने में कम से कम 10 घंटे या उससे अधिक समय लगेगा, वह भी तब जब हेलीकाप्टर जैसी विशेष व्यवस्था की जाए। ऐसे में सत्र के अंतिम दिन तक उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना संभव नहीं है। (राज्य ब्यूरो)

सुकमा में 12 लाख के इनामी तीन माओवादी ढेर

सुकमा : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोलापल्ली थाना क्षेत्र के जंगल-पहाड़ी में चल रहे माओवादी विरोधी अभियान में गुरुवार को पुलिस ने मुठभेड़ में तीन माओवादियों को ढेर कर दिया। उनकी पहचान पांच-पांच लाख के इनामी माड़वी जोगा, सोढ़ी बंडी व दो लाख की इनामी नुप्पो बजनी के रूप में हुई। तीनों किस्टाराम एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। मौके से हथियार भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) टीम ने गुरुवार सुबह सर्च आपरेशन शुरू किया था। जैसे ही पुलिस टीम जंगल-पहाड़ी पर पहुंची, माओवादियों ने घात लगाकर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इसके बाद मुठभेड़ स्थल से तीन माओवादियों के शव व हथियार मिले। पिछले दो वर्ष में माओवादियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। शीर्ष माओवादी नेताओं सहित 500 से अधिक माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। लगभग ढाई हजार माओवादी हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौट चुके हैं। नईदुनिया)

सोना गायब मामले में एनआरआइ का बयान दर्ज

तिरुअनंतपुरम : सबरीमाला मंदिर से सोना गायब होने के मामले की जांच कर रही एसआइटी ने गुरुवार को एक एनआरआइ व्यवसायी का बयान दर्ज किया। दुबई स्थित व्यवसायी का बयान कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला के बयान के बाद दर्ज किया गया। चेन्निथला ने बताया था कि व्यवसायी ने उन्हें सबरीमाला से सोना गायब होने में एक अंतरराष्ट्रीय एंटीक रैकेट की कथित संलिप्तता के बारे में जानकारी दी थी। इसके आधार पर एसआइटी ने व्यवसायी से संपर्क किया और बुधवार को तिरुअनंतपुरम में बयान दर्ज किया। व्यवसायी ने उन अन्य व्यक्तियों के संपर्क नंबर सौंपे जिनके पास एंटीक कारोबार के बारे में अधिक जानकारी हो सकती है। (प्रेट्र)

आवारा कुत्तों के मामले में हम वीडियो दिखाएंगे, आपसे पूछेंगे कि इंसानियत क्या है : सुप्रीम कोर्ट

एमसीडी की ओर से बनाए गए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की टिप्पणी

नई दिल्ली, प्रेट्र : आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में एक वीडियो दिखाया जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि मानवता क्या है? याचिका में कहा गया है कुत्तों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि एक तीन सदस्यीय विशेष पीठ, जोकि इस मामले की सुनवाई के लिए आज एकत्र होने वाली थी, उसे रद कर दिया गया है। सिब्बल ने कहा- "समस्या यह है कि एमसीडी ने इस बीच कुछ नियम बनाए हैं जो पूरी तरह से विपरीत हैं।" जब पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर सात जनवरी को विचार करेगी तो सिब्बल ने कहा कि अधिकारी दिसंबर में ही नियमों को लागू करेंगे और आवारा कुत्तों को हटा देंगे। इस पर जस्टिस नाथ ने कहा, "यह ठीक है श्री सिब्बल। उन्हें करने दें, हम विचार करेंगे।" सिब्बल ने कहा कि जो किया जा रहा है, वह बहुत ही अमानवीय है। न्यायाधीश मेहता ने कहा- "अगली तारीख पर हम आपके लाभ के लिए एक वीडियो दिखाएंगे और हम आपसे पूछेंगे कि मानवता क्या है?"

▸ सुप्रीम कोर्ट ने सात नवंबर को आवारा कुत्तों को निर्धारित आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था

कोर्ट ने सात नवंबर को आवारा कुत्तों को निर्धारित आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था ताकि उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जा सके। साथ ही कहा था कि जो आवारा कुत्ते उठाए जाएंगे, उन्हें वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। पीठ ने अधिकारियों को राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे से सभी मवेशियों और अन्य आवारा जानवरों को हटाने का निर्देश दिया था। यह मामला 28 जुलाई को आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था, जो राजधानी में विशेष रूप से बच्चों में रैबिज का कारण बन रहा था।

बोतल बंद पानी के मानकों की मांग संबंधी याचिका पर विचार से इन्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बोतल बंद पानी के अंतरराष्ट्रीय मानकों को लेकर दायर याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यहां लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में बोतल बंद पानी की गुणवत्ता को लेकर याचिका दायर करना लग्जरी मुकदमेबाजी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप गरीब क्षेत्रों में जाकर देखेंगी कि वहां पेयजल की उपलब्धता कैसी है, तब आपको वास्तविकता का पता चलेगा।

पीठ ने गुरुवार को सारंग वामन यदवाडकर की याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए दिए उक्त टिप्पणी कीं। कोर्ट ने कहा कि आज भी देश के बड़े हिस्से में लोग पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में बोतलबंद पानी के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बहस प्राथमिकता का मुद्दा नहीं हो सकती। याचिका पर बहस कर रहीं वरिष्ठ वकील अनीता शेनाय ने कहा कि नागरिकों को कम से कम स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिलने की गारंटी तो होनी चाहिए, यह सीधे तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा-18 का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अथारिटी का वैधानिक दायित्व है। लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि यह शहर केंद्रित सोच है। ग्रामीण इलाकों में लोग मुख्यतः भूजल पीते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। अगर याचिका उन गांवों से संबंधित होती जहां आज भी पेयजल की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो कोर्ट इसे अधिक गंभीरता से लेता। पानी की बोतल में यह होना चाहिए वो होना चाहिए, ये सब लग्जरी मुकदमेबाजी है। जब वकील ने इसे स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से जोड़ते हुए दलील दी और विदेशों के मानकों का हवाला दिया तो पीठ ने कहा कि क्या आपको लगता है कि हम अमेरिका, जापान या यूरोप के दिशानिर्देश यहां लागू कर सकते हैं।

आइआइटी मुंबई में 'जेन जी डाकघर' की शुरुआत

▸ डाकघर के हरेभरे परिसर में आउट डोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हुई शुरुआत

▸ कैरम और शतरंज खेलने की है व्यवस्था, पूरा डाकघर परिसर में वाईफाई की सुविधा

आइआइटी के जेन जी डाकघर में पहले दिन काउंटर पर लोग। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, मुंबई : पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय और मनी आर्डर का दौर तो बीते दिनों की बात हो गई। अब भारतीय डाक विभाग नए जमाने से कदमताल कर रहा है। इसी कड़ी में डाक विभाग ने आइआइटी मुंबई में जेन जी पोस्ट आफिस की शुरुआत की है। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में होने वाले आइआइटी मुंबई के वार्षिकोत्सव 'मूड इंडिगो' का मूड आज तब और जम गया, जब महाराष्ट्र एवं गोवा क्षेत्र के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अमिताभ सिंह ने आइआइटी परिसर में 1960 से चल रहे डाकघर में कई ऐसी सुविधाएं शुरू कीं, जो सामान्यतः किसी और डाकघर में नहीं मिलेंगी।

अंदर जाते ही पूरा डाकघर वाईफाई कनेक्शन की रेंज में है, जहां कोई भी छात्र या सामान्य नागरिक जाकर वाईफाई सुविधा का लाभ ले सकता है। अंदर एक तरफ सितार सहित कुछ और वाद्य यंत्र रखे हैं तो दूसरी ओर पुस्तकों की एक रेक सजाई गई है। आइआइटी मुंबई के डायरेक्टर श्रीश केदारे कहते हैं कि डाकघर द्वारा शुरू की गई ये सुविधाएं आइआइटी के छात्रों को डाकघर की ओर आने के लिए आकर्षित करेंगी, क्योंकि यह डाकघर अब नई पीढ़ी का डाकघर बन चुका है।

इस जेन जी डाकघर का लाभ आइआइटी के अलावा डाकघर के निकट ही स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र भी उठा सकेंगे, क्योंकि छात्रों के लिए यहां स्पीड पोस्ट जैसी डाक सेवाओं में भी रियायत दी जा रही है। आइआइटी मुंबई के छात्रसंघ महासचिव एवं बीटेक केमिकल के छात्र अभय प्रताप सिंह कहते हैं कि पहले डाकघर में आने पर लंबी-लंबी लाइनें छात्रों का स्वागत करती थीं। जिससे ऊबकर छात्र पोस्ट आफिस से लौट जाया करते थे। अब उन्हें 'एंगेज' करने के लिए यहां इतने साधन बना दिए गए हैं कि किसी के वापस लौटने की नौबत नहीं आएगी।

डिजिटल गिरफ्तारी का भय दिखाकर सेवानिवृत्त कर्मी से 99 लाख की ठगी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

कोलकाता के बागुइआटी में डिजिटल गिरफ्तारी का भय दिखाकर एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से 99 लाख रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित गौतम कुमार राय ने बिधाननगर कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई है।

बागुइआटी के अश्विनीनगर के निवासी राय ने जांचकर्ताओं को बताया कि ठगों ने 29 नवंबर को फोन और वाट्सएप मैसेज के जरिए उनसे संपर्क किया था। जालसाजों ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया और कहा कि उनके नाम पर एक मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल मुंबई के व्यापारियों से फिरौती मांगने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के लिए किया जा रहा है। ठगों ने राय को बताया कि सिम का इस्तेमाल पापुलर फ्रंट आफ इंडिया से जुड़े एक कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा था, जो एक प्रतिबंधित संगठन है। यह भी बताया गया कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस तरह ठगों ने उन्हें चार दिनों तक डिजिटल रूप से बंधक बनाए रखा। इस दौरान उन्हें दो फिक्स्ड डिपाजिट समय से पहले बंद करने और पूरी राशि उन्हें ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।

▸ जालसाजों ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर चार दिनों तक बंधक बनाए रखा

उन्हें बताया गया था कि रिजर्व बैंक उनके बैंक खातों की जांच कर रहा है। अगर वे अपनी सारी रकम दे देंगे तो उनका पैसा सुरक्षित रहेगा।

लव मैरिज से नाराज स्वजन ने लड़के के बड़े भाई की काट दी नाक

जासं, बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर में लव मैरिज से नाराज लड़की वालों ने लड़के के बड़े भाई पर हमला कर उसकी धारदार हथियार से नाक काट दी, इसके बाद घटना के जवाब में लड़के वालों ने भी लड़की के घर पहुंच चाचा का पैर काट दिया। मामला राजस्थान के बाड़मेर के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र का है। हमला करने के बाद दोनों परिवारों के आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है। लव मैरिज करने वाला श्रवण सिंह पत्नी के साथ गुजरात में रहता है।

बाड़मेर निवासी श्रवण सिंह ने ढाई साल पहले पड़ोस में रहने वाली लड़की से लव मैरिज की थी। इसके बाद दोनों परिवारों में विवाद हो गया था। नाराज लड़की के घर वाले लव मैरिज का बदला लेने की फिराक में थे। मौका पाकर बुधवार शाम को श्रवण के बड़े भाई उक सिंह की खेत से लौटने के दौरान पड़ोसी धर्मसिंह और उसके साथियों ने हमला कर नाक काट दी।

नौकरशाहों के लिए 'माननीय' शब्द सही नहीं : हाई कोर्ट

जासं, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नौकरशाहों के लिए 'माननीय' शब्द के उपयोग पर सवाल उठाते हुए राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि किस कानून के तहत इस शब्द का इस्तेमाल सही है।

कोर्ट ने कहा, 'यह संविधानिक पदाधिकारियों और अदालतों का दर्जा कम करने का सूक्ष्म, लेकिन निश्चित तरीका है। हाल ही में ऐसा चलन शुरू हुआ है, जहां राज्य के विभिन्न अधिकारियों के सबसे निचले से लेकर उच्चतम स्तर तक के पदों के नाम के आगे पत्राचार और आदेशों में माननीय लगाया जा रहा है।' 'यह शब्द केवल मंत्रियों और अन्य संप्रभु पदाधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए', यह कहते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की- यह (माननीय) नौकरशाहों या राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए सही नहीं है।

कोर्ट का कहना था- 'यह अदालत अक्सर देखती है कि आधिकारिक पत्राचार में राज्य के विभिन्न अधिकारियों के पदों के नाम के साथ नियमित रूप से 'माननीय' शब्द जोड़ा जाता है।

▸ उठाया सवाल, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

प्रकरण में इटावा के कलेक्टर ने कानपुर के संभागीय आयुक्त को माननीय आयुक्त के रूप में संबोधित किया है।

प्रधान सचिव को कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि वह यह बताएं कि क्या राज्य के ऐसे अधिकारियों के बारे में कोई प्रोटोकाल है, जो इस शब्द के हकदार हैं या जिनके पदनाम या नाम के साथ माननीय शब्द जोड़ा जाता है। याची के खिलाफ बरेली के बिथरी चैनपुर थाने में बीएनएस के तहत केस दर्ज है।

यूपीएससी ने इंजीनियरिंग परीक्षा के परिणाम घोषित किए

नई दिल्ली, प्रेट्र : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने इंजीनियरिंग सेवाओं की परीक्षा (ईएसई) 2025 के अंतिम परिणाम गुरुवार को घोषित किए। विभिन्न इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए 458 उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। यह परिणाम अगस्त में आयोजित लिखित परीक्षा और अक्टूबर-नवंबर में आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण पर आधारित हैं।

सिविल इंजीनियरिंग के 202 उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। इलेक्ट्रानिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के 116, इलेक्ट्रिकल के 79 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 61 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है।

ईएसई के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग सेवा, केंद्रीय इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा, सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा जैसी विभिन्न तकनीकी सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। ईएसई का परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देखा जा सकता है।

मेसी के कार्यक्रम में तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

▸ आगामी 22 दिसंबर तक राज्य सरकार को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश, दायर हुई हैं तीन जनहित याचिकाएं

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गत शनिवार को साल्टलेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई तोड़फोड़ की घटना पर बंगाल सरकार से 22 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति सुजय पाल व न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने सरकार को यह निर्देश दिया है। उसी दिन इस मामले पर सुनवाई भी होगी। मालूम हो कि घटना को लेकर हाई कोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं। एक भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी एवं अन्य दो बिलवादल भट्टाचार्य व सब्यसाची चट्टोपाध्याय नामक अधिवक्ताओं की ओर से दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में कार्यक्रम के टिकटों की बिक्री में वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया है।

एसआइटी ने शुरू की जांच

राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना वाले दिन का स्टेडियम का वीडियो फुटेज खंगाला जा रहा है। जांच दल यह पता करने की कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड पर पानी की बोतलें फेंकने की शुरुआत दर्शक दीर्घा के किस हिस्से से हुई थी। आरंभिक जांच के आधार पर अनुमान है कि सबसे पहले स्टेडियम के लोअर टियर से बोतलें फेंकी गई थीं।

मेसी के कार्यक्रम के कुप्रबंधन मामले में सरकार की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस का खेल विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिन्हा, राज्य पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार व बिधाननगर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त मुकेश कुमार ने जवाब दे दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खेल सचिव ने कहा है कि कार्यक्रम के जिस तरह से आयोजन की बात कही गई थी, आयोजकों ने उस तरह से कुछ नहीं किया। सारा कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक किया।

मप्र में 200 फीट गहरी खाई में 30 घंटे फंसा रहा ट्रक चालक, जीपीएस से बची जान

नईदुनिया प्रतिनिधि ● छिंदवाड़ा

मौत को मात देने वाली एक घटना मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के सिल्लेवानी घाटी में सामने आई है। यहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट नीचे गिरकर पलट गया। ट्रक के नीचे चालक का पैर फंस गया। इस पूरे मामले में जीपीएस का अहम योगदान रहा, जिसके आधार पर ट्रक की तलाश करते हुए मौके तक पहुंचकर 30 घंटे से फंसे चालक की जान बचाई जा सकी।

बताया जाता है कि मक्के से भरा यह ट्रक मंगलवार दोपहर चौरई तहसील के ग्राम चांद से औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव (पांढुर्णा) के लिए रवाना हुआ था। ग्राम चांद से लगभग 130 किलोमीटर दूर मंगलवार रात करीब तीन बजे सिल्लेवानी घाट में यह हादसा हो गया। जब बुधवार तक ट्रक बोरगांव नहीं पहुंचा और चालक का मोबाइल बंद मिला, तो ट्रक मालिक रवि बघेल की चिंता हुई। उन्होंने इसके लिए जीपीएस सिस्टम की मदद ली। पता चला कि ट्रक सिल्लेवानी घाटी में एक मोड़ पर स्थिर है। गुरुवार सुबह करीब नौ बजे मौके पर पहुंचने पर पता चला कि ट्रक बेकाबू होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिरा है। बचाव दल ने देखा कि ट्रक चालक का पैर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। वह लगभग 30 घंटे तक उसी स्थिति में दर्द बर्दाश्त करता रहा। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उमरानाला चौकीप्रभारी ने बताया कि चालक सुरक्षित है और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है।

▸ मप्र में छिंदवाड़ा जिले की सिल्लेवानी घाटी में गिर गया था ट्रक

▸ तय स्थान पर ट्रक नहीं पहुंचने पर जीपीएस से लगाया गया पता

ट्रक के नीचे फंसे ड्राइवर को निकालने का प्रयास करते रेस्क्यू टीम के सदस्य। सौ.इंटरनेट मीडिया

जेद्दा से कोझिकोड़ जा रहे विमान को एहतियात के तौर पर कोचीन उतारा

कोच्चि, प्रेट्र : सऊदी अरब के जेद्दा से 160 यात्रियों को लेकर केरल के कोझिकोड जा रहे विमान को टायर में खराबी आने के कारण गुरुवार को 'एहतियात के तौर पर' कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जेद्दा-कोझिकोड उड़ान को कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़कर विमान के टायर में संभावित खराबी के कारण एहतियाती तौर पर उतार लिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि जेद्दा हवाई अड्डे के रनवे पर किसी वस्तु के कारण टायर में खराबी आने की आशंका है। प्रवक्ता के अनुसार, विमान कोच्चि में सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। सभी यात्रियों को सड़क मार्ग से कोझिकोड भेजा जा रहा है। उन्हें होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। हम दोहराते हैं कि संचालन गतिविधियों में सुरक्षा हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि केवल टायर फटे थे और लैंडिंग गियर में कोई समस्या नहीं थी। यह आपात लैंडिंग भी नहीं थी।

जागरण विशेष

दुर्गम व पहाड़ी स्थलों पर सैनिकों का सहयोगी बनेगा 'हनुमंता'

आइआइटी दिल्ली के बनाए उपकरण से जवान के पीठ पर लदे बैग का 80 प्रतिशत तक कम महसूस होगा वजन

नंदकिशोर भारद्वाज ● जागरण

सोनीपत : सेना के जवान विषम परिस्थितियों में भारी-भरकम हथियार और सामान से भरे वजनी बैग लेकर घंटों तक रेगिस्तान, बर्फीली पहाड़ियों और दुर्गम जंगलों में गश्त करते हैं। इस दौरान भारी वजन के बैग और हथियारों को उठाने के कारण जवानों के घुटनों और पीठ में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आइआइटी दिल्ली के छात्र गौरव राय ने उच्च तकनीक से 'हनुमंता एक्जो-1' तैयार किया है, जिसके कारण सैनिकों के कंधों पर लदा वजन 80-90 प्रतिशत तक कम महसूस होगा। यानी 60 किलो वजन मात्र 10 किलो का रहेगा।

गौरव राय के अनुसार, 'हनुमंता एक्जो-1' उपकरण को गांधीनगर स्थित भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय और सोनीपत स्थित आइआइटी दिल्ली के एडवांस इमेजिंग सेंटर (एआइसी) के सहयोग से दो वर्षों में विकसित किया गया है। यह गर्दन, पीठ से लेकर जूतों तक पहना जाने वाला उपकरण है, जो डेल्टा स्प्रिंग सिस्टम के आधार पर काम करता है, जो भार को अर्थिंग प्रक्रिया के तहत नीचे पीठ की ओर से जमीन की ओर भेजता है। जैसे ही सैनिक इस उपकरण को पहनकर चलते हैं, यह पीठ पर लदे भार को जूतों के जरिए घटाकर जमीन की ओर भेज देता है। स्प्रिंग सिस्टम को इस तरह बनाया गया है कि यह उपकरण मानव शरीर के मसल्स सिस्टम की तरह कार्य करता है। चलने के दौरान पैरों की मूवमेंट के साथ एडजस्ट होकर यह वजन घटाने में सहायक होता है। मूल रूप से राजस्थान के कोटा के रहने वाले गौरव बताते हैं कि वर्ष 2023 में सोनीपत स्थित कैंपस में इस पर कार्य शुरू हुआ था, जो अब तैयार हो चुका है। गांधीनगर स्थित भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के जरिये सेना और डीआरडीओ के समक्ष इसकी प्रस्तुति हो चुकी है। सेना ने इसे न केवल उपयोगी बताया, बल्कि एआइ से जोड़ने का सुझाव भी दिया है। गौरव के मुताबिक, एआइ से जोड़कर इसे और उन्नत बनाने पर काम हो रहा है।

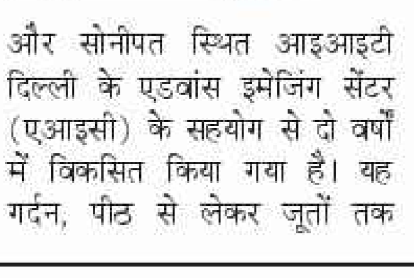

सोनीपत में एआइसी में हनुमंता एक्जो-1 को दिखाते गौरव राय ● जागरण

सेना से सेवानिवृत्त पिता की सलाह पर किया काम

गौरव राय बताते हैं कि उनके पिता सतेंद्र राय सेना में अधिकारी थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लंबे समय तक भारी बैग लादकर गश्त करने के कारण उन्हें भी पीठ और घुटनों में दर्द की समस्या रहती है। पिता ने ही उन्हें बताया कि यह बड़ी समस्या है और अन्य जवानों को भी इसका सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 'हनुमंता एक्जो-1' का निर्माण करने का विचार किया। पेटेंट की प्रक्रिया अगले माह 15 जनवरी के बाद शुरू होगी।

"आइआइटी, दिल्ली के सोनीपत स्थित कैंपस (एआइसी) में ऐसे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है, जिनका मानव जीवन से सीधा जुड़ाव हो और जो लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम स्टार्टअप को फंड, गाइडेंस और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। शोधार्थियों के यूनीक आइडिया को एक प्रोडक्ट बनाने तक हम मदद करते हैं।"

आलोक पांडेय, सीईओ, एआइसी आइआइटी दिल्ली

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर 252 किमी की रफ्तार से दौड़ाई लैंबोर्गिनी, कार जब्त

▸ सी लिंक पर कारों के लिए गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा है

▸ वीडियो सामने आने के बाद चालक के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई, प्रेट्र : बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंबोर्गिनी कार चलाने पर पुलिस ने कार जब्त कर ली है। यह घटना 12 दिसंबर को हुई थी और बुधवार को एक वीडियो सामने आने के बाद चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, चालक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।

एक अधिकारी ने बताया, "कार के अंदर शूट किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि जब कार सी लिंक के दक्षिणी छोर की ओर जा रही थी और अन्य वाहनों को ओवरटेक कर रही थी, तब उसका स्पीडोमीटर 252 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गया था।" उन्होंने आगे बताया कि पुलिस अधिकारियों ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि इसी कार ने कई बार गति सीमा का उल्लंघन किया था और इसके खिलाफ कई चालान जारी किए गए थे। पुलिस ने कहा कि सी लिंक पर कारों के लिए गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा है।

नागालैंड में बुजुर्ग ने रेलवे ट्रैक पर एसयूवी चलाई, गिरफ्तार : नागालैंड के दीमापुर में रेलवे ट्रैक पर एसयूवी चलाने के आरोप में 65 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। घटना मंगलवार देर रात की है। सिग्नल अंगामी निवासी बुजुर्ग गाड़ी लेकर ट्रैक पर चढ़ गया। दीमापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के पास लाइन नंबर एक पर गाड़ी फंस गई। वाहन को सुरक्षित रूप से ट्रैक से हटाया गया।

****

दैनिक जागरण
जिजीविषा ही जीवन को जीवंत बनाती है

सुप्रीम कोर्ट की चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करके अपनी अप्रसन्नता प्रकट करने के साथ न्यायपालिका की एक और विसंगति की ओर ही संकेत किया कि सेवानिवृत्ति से ठीक पहले न्यायाधीशों का अनेक आदेश पारित करना अंतिम ओवर में छक्के मारने जैसा है, लेकिन केवल इतने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। यह कोई नई बात नहीं कि सेवानिवृत्ति से ठीक पहले न्यायाधीशों द्वारा कई आदेश पारित करने का चलन लंबे समय से कायम है। इस पर कई बार प्रश्न उठे हैं। बीते दिनों यह प्रश्न एक याचिका की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया, लेकिन प्रश्न यह है कि उसने जिस प्रवृत्ति की ओर चिंता जताई, उसका समाधान निकाला जाएगा या नहीं? इसका औचित्य नहीं कि न्यायपालिका की विसंगतियों पर चिंता तो जताई जाए, लेकिन उनका समाधान न निकाला जाए। यह एक तथ्य है कि न्यायपालिका में वैसे सुधार नहीं हो रहे हैं, जैसे अनिवार्य हो गए हैं। जो छोटे-मोटे सुधार हो भी रहे हैं, वे मूल समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। सुगम तरीके से और समय पर न्याय मिलना पहले की ही तरह कठिन बना हुआ है। लंबित मुकदमों का बोझ भी कम होता नहीं दिख रहा है। उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों का भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है।

अन्य अनेक समस्याओं के साथ न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह कुछ नहीं किया जा पा रहा है, इसका ताजा उदाहरण है भ्रष्टाचार के चलते महाभियोग का सामना कर रहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा का इस शिकायत के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कि उनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित जांच कमेटी नियम विरुद्ध है। इस शिकायत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव से जवाब भी मांग लिया। इस याचिका पर अंतिम निर्णय जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह गंभीर आरोपों से घिरने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। हाल-फिलहाल उनके मामले का निपटारा होने के कोई आसार नहीं। यह ध्यान रहे कि कदाचार के आरोपों से घिरे उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को महाभियोग के जरिये ही हटाया जा सकता है और अभी तक किसी जज के मामले में वह सफल नहीं हो सका है। इसका यह मतलब नहीं कि न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, उनमें कोई सत्यता नहीं थी। न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट को यह समझना होगा कि यदि ठोस न्यायिक सुधारों की दिशा में आगे नहीं बढ़ा गया तो न्यायिक तंत्र को लेकर उठने वाली चिंताएं बढ़ती ही रहेंगी।

जिम्मेदारी किसकी

विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। अतिरिक्त खर्चों के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग होगी। दूसरी ओर कई विभागों में मूल बजट के सापेक्ष खर्च की स्थिति अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बजट का आकार बढ़कर आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक जरूर हो गया है, पर खर्च की गति तो संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में सिर्फ योजनाओं के लिए ही लगभग 3.88 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था थी, पर वित्तीय वर्ष के आठ माह में सिर्फ 1.28 लाख करोड़ रुपये ही खर्च हुए। यह मूल योजना का मात्र 33 प्रतिशत है। नवंबर तक दो-तिहाई वित्तीय वर्ष गुजरने पर योजनाओं को एक-तिहाई धनराशि भी खर्च होना योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहा है। अब जब चार माह से भी कम समय शेष है तो बची हुई 67 प्रतिशत धनराशि का खर्च होना बहुत संभव नहीं दिख रहा। जन सुविधा से जुड़े ग्राम्य विकास और नगर विकास विभाग में बजट मद का लगभग 23 प्रतिशत ही अब तक व्यय हो सका है। स्वास्थ्य विभाग में भी 60 प्रतिशत राशि अभी खर्च होनी बाकी है। भारी भरकम बजट बना लेने मात्र से प्रदेश का भला नहीं हो सकता। भलाई तो तब है जब बजट राशि का समयबद्ध सदुपयोग हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो सका है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

> उत्तर प्रदेश में बजट का आकार बढ़कर आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक जरूर हो गया है, पर खर्च की गति तो संतोषजनक नहीं कही जा सकती है

चीन की दुखती रग दबाने का समय

विजय क्रांति

चीनी आक्रामकता और धमकियों का सही जवाब यही होगा कि भारत सरकार तिब्बत पर चीन के अनैतिक कब्जे को चुनौती दे

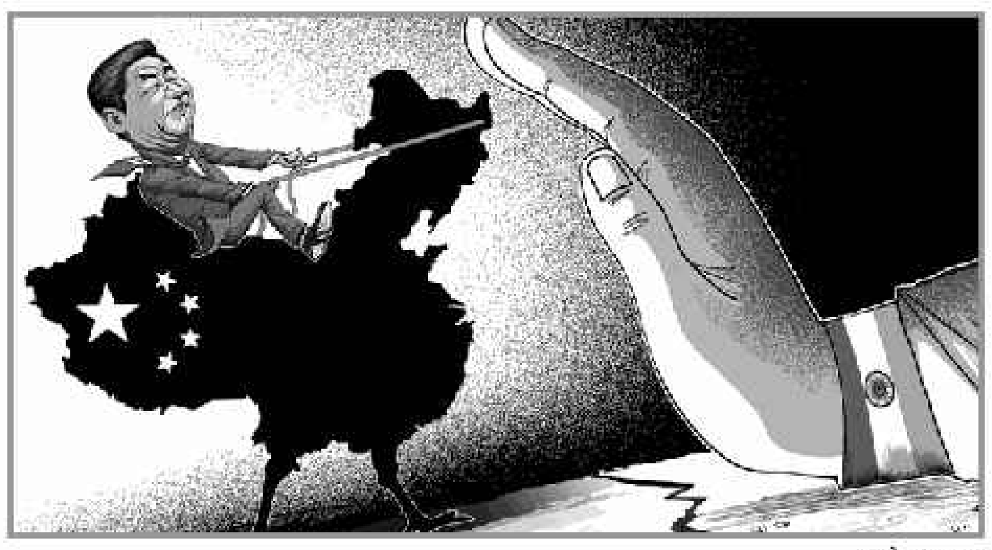

अवधेश राजपूत

कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग में छठे दलाई लामा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में भागीदारी का निमंत्रण मिलने पर मैंने कई पत्रकार और राजनयिक मित्रों से कहा था कि वे चीन सरकार के गुस्से और तिलमिलाहट भरे बयान सुनने के लिए तैयार रहें। यह बात मैंने किसी भविष्यवक्ता होने के नाते नहीं, बल्कि तिब्बत और भारत के बारे में चीनी रवैये और नीतियों पर अपने पांच दशकों के अध्ययन के आधार पर कही थी। हुआ भी वैसा ही। तीन से छह दिसंबर तक चली इस कांफ्रेंस के तीन दिन बाद ही चीन सरकार ने तिब्बत के बारे में अपनी नीति बताने वाली वेबसाइट पर भारत सरकार, अरुणाचल के मुख्यमंत्री और इस कांफ्रेंस के खिलाफ जिस तरह की जहरीली प्रतिक्रिया व्यक्त की वह चीन सरकार के गुस्से, तिलमिलाहट और आक्रामकता की ही अभिव्यक्ति थी कि उसे सही जगह चोट पहुंची है।

चीनी सरकार के एक टिप्पणीकार के बयान में अरुणाचल के लिए न केवल चीनी नाम 'झांगनान' और तिब्बत के लिए 'शीझांग' का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इस क्षेत्र को 'दक्षिणी तिब्बत' बताते हुए कांफ्रेंस को 'दक्षिण-पूर्वी चीन' के हिस्से पर भारत सरकार की ओर से किया गया 'सांस्कृतिक अतिक्रमण' तक बता दिया। हालांकि भारत पर ऐसे आरोप लगाते हुए चीन सरकार इस सच्चाई को पूरी तरह निगल गई कि अरुणाचल प्रदेश को 'दक्षिणी तिब्बत' बताकर उस पर अपना अधिकार जताने के पीछे उसकी एकमात्र दलील केवल यही है कि चीन 1951 से तिब्बत पर गैर-कानूनी और औपनिवेशिक कब्जा जमाए बैठा है। दुर्भाग्य से नेहरू काल से लेकर आज तक अरुणाचल प्रदेश और देश की हिमालयी सीमा पर चीनी आक्रामकता सहता आ रहा है। किसी भी सरकार ने यह साहस नहीं दिखाया कि वह तिब्बत पर चीन सरकार के गैरकानूनी कब्जे को चुनौती देकर इस विवाद की असली जड़ पर हमला करे।

हाल में आयोजित कांफ्रेंस के आयोजन के पीछे मूल कारण छठे दलाई लामा ग्यालवा त्सांगयांग ग्यात्सो के ऐतिहासिक महत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करना था। छठे दलाई लामा इस मायने में अनूठे थे कि उनका जन्म एक मार्च, 1683 के दिन तिब्बत से बाहर भारत के तवांग क्षेत्र (अरुणाचल) में हुआ था। संयोग से तिब्बत पर 1951 के चीनी कब्जे और बाद में 1959 में चीनी सेना के हाथों पकड़े जाने या हत्या किए जाने के डर से भागे हुए 14वें दलाई लामा ने जब भारत में शरण ली तब तवांग के रास्ते ही भारत में प्रवेश किया था। इसलिए तिब्बत के दो दलाई लामाओं के साथ गहरे संबंध के कारण ही तवांग का विशेष महत्व है। कांफ्रेंस को तवांग में आयोजित किए जाने का भी यही कारण रहा। चीन इससे परेशान है कि इस कांफ्रेंस में भारत और तिब्बत के अलावा अमेरिका, जापान, मंगोलिया, इजरायल, कनाडा समेत कई देशों के नामी गिरामी तिब्बत-विशेषज्ञों, चीनी मामलों के जानकार और बौद्ध धर्म के विद्वानों ने हिस्सा लिया। चीन सरकार के लिए हताशा और तिलमिलाहट का एक कारण यह भी था कि इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन (आइबीसी) ने अरुणाचल सरकार के कार्मिक एवं आध्यात्मिक विभाग के माध्यम से किया।

आइबीसी को लेकर चीन सरकार की सबसे बड़ी छटपटाहट यह है कि भारत के इस संस्थान ने दो दशकों से चल रहे उन चीनी प्रयासों पर पानी फेर दिया है, जिनका लक्ष्य तिब्बत में अपनी उपस्थिति को आधार बनाकर चीन को 'वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम' (डब्ल्यूबीएफ) के माध्यम से चीन को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध जगत का सर्वोच्च और एकमात्र प्रतिनिधि स्थापित करना है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सत्ता में आने के बाद ही इस अभियान को लेकर अपनी साख दांव पर लगा दी। चीन को वैश्विक बौद्ध समाज का एकमात्र नेतृत्वकर्ता स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति शी भारत में रहने वाले दलाई लामा को दरकिनार कर चीन के कठपुतली पंचेन लामा ग्यालसेन नोरबू को दुनिया का सर्वोच्च बौद्ध नेता स्थापित करने की पुरजोर कोशिशें करते आए हैं। यह बात अलग है कि स्वयं तिब्बती जनता द्वारा ठुकरा दिए गए नोरबू को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्मगुरुओं और विद्वानों के बीच मान्यता नहीं मिल पाई है। दूसरी ओर भारत के आइबीसी ने अपने कई प्रभावशाली आयोजनों के माध्यम से दुनिया भर के वरिष्ठ बौद्ध धर्मगुरुओं को संगठित करने और उन्हें एक मंच पर लाकर भारत को वैश्विक बौद्ध नेतृत्व के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पिछले कई वर्षों से अगले दलाई लामा के अवतार का चुनाव करने पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार के प्रयासों को इस साल जुलाई में आइबीसी के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में दुनिया भर से आए बौद्ध धर्मगुरुओं ने सिरे से ठुकरा दिया था।

तवांग कांफ्रेंस के खिलाफ अपने इस तल्खी भरे बयान से एक पखवाड़ा पहले ही चीन ने अरुणाचल की एक भारतीय महिला यात्री को एक चीनी हवाई अड्डे पर महज इस आधार पर अपमानित और परेशान किया था कि उनका पासपोर्ट भारतीय है। चीन का कहना था कि अरुणाचल पर चीनी दावे के हिसाब से उनके पास 'चीनी पासपोर्ट' होना चाहिए था। उससे भी पहले दर्जनों बार चीन सरकार अरुणाचल के खिलाड़ियों को चीनी वीजा देने से इन्कार कर चुकी है। उसने भारतीय राष्ट्रपति से लेकर दलाई लामा की अरुणाचल यात्राओं का भी विरोध किया है। इस बार भी चीनी टिप्पणी में बार-बार छठे दलाई लामा का जन्मस्थान होने के आधार पर अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताने का प्रयास किया गया है। ऐसे में चीन की आक्रामकता और धमकियों का सही जवाब यही होगा कि भारत सरकार तिब्बत पर चीन के गैरकानूनी और अनैतिक कब्जे को चुनौती देकर चीन की खुराफातों की दुखती रग को दबाने का काम करे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो चीन को गलत संदेश जाएगा।

(लेखक तिब्बत-चीन मामलों के विशेषज्ञ और सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

राहुल की सीमाएं, प्रियंका की संभावनाएं

राज कुमार सिंह

वंदेमातरम् पर चर्चा के दौरान प्रियंका ने दिखाया कि वह राहुल गांधी की तुलना में अधिक प्रभावी वक्ता हैं

वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर संसद में हुई चर्चा में दो भाषणों की बड़ी चर्चा हुई। एक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का, जिन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। दूसरा, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का। प्रियंका ने मोदी और भाजपा को निशाने पर रखा, पर उसका असर कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में भी दिखने लगा है। सदन के नेता के नाते प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम् पर चर्चा की शुरुआत की। अपेक्षित तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से था, मगर कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला प्रियंका ने। ऐसा क्यों हुआ, यह तो कांग्रेस ही बता सकती है, पर मोदी की भाषण कला की प्रशंसा करते हुए भी प्रियंका हास-परिहास के बीच ही तर्कों और तथ्यों के साथ सत्तापक्ष पर कटाक्षों से सदन को प्रभावित करने में सफल दिखीं। राहुल गांधी भी बोले, मगर चुनाव सुधार पर चर्चा में। उन्होंने मुख्यतः वोट चोरी के अपने वही आरोप ही दोहराए, जो वह पहले भी लगाते रहे हैं। उनके भाषण में न तो नए तथ्य-तर्क दिखे और न ही प्रियंका की तरह आक्रामक हुए बिना सत्तापक्ष को कठघरे में खड़ा करने की कला।

राहुल वोट चोरी के पुराने आरोप दोहरा भर रहे थे, जबकि प्रियंका वंदे मातरम् विवाद के सभी पहलुओं पर तैयारी करके आई थीं। तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात कहना ही संसदीय चर्चा की प्रभावी शैली है। प्रियंका ने इसी प्रभावी शैली का परिचय दिया। शायद इसलिए भी खुद कांग्रेस के अंदर राहुल से तुलना करते हुए प्रियंका को बड़ी राजनीतिक भूमिका देने की चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी है। ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम ने उम्र के हवाले से मल्लिकार्जुन खरगे को हटाकर प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने की मांग की। उन्होंने राहुल गांधी पर भी अप्रत्यक्ष निशाना साधा। कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। टीम राहुल और टीम प्रियंका में कथित टकराव की चर्चाओं को भाजपा द्वारा हवा देने के राजनीतिक निहितार्थ खोजे जा सकते हैं, पर इससे इनकार नहीं कि दोनों की अपनी-अपनी टीम है और देश-प्रदेश में अपने-अपने पसंदीदा नेता भी।

कई प्रसंग बताते हैं कि राहुल और प्रियंका, कांग्रेस में दो सत्ता केंद्र बन गए हैं। माना जाता है कि राहुल को उत्तराधिकारी बनाने तथा पार्टी में दो सत्ता केंद्रों से बचने के मकसद से ही सोनिया ने प्रियंका को पर्दे के पीछे की भूमिका में रखा। सोनिया और राहुल के चुनाव क्षेत्रों में प्रचार और प्रबंधन संभालती रहीं प्रियंका को राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।

अपनी छाप छोड़ने में सफल प्रियंका गांधी। फाइल

बेशक 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' के नारे के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्यादा महिला उम्मीदवारों पर प्रियंका का दांव नहीं चला। इसके बावजूद पिछले साल रायबरेली से भी निर्वाचित राहुल द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में प्रियंका को उम्मीदवार बनाने से उनकी भी जरूरत का संकेत गया। अर्थ निकाला गया कि प्रियंका अपेक्षाकृत अनुकूल दक्षिण भारत में कांग्रेस संभालेंगी, जबकि अध्यक्ष पद से पहले ही मुक्त हो चुके राहुल शेष देश में भाजपा से मोर्चा लेंगे, लेकिन वांछित परिणाम दिखे नहीं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। विपक्षी गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ भी कांग्रेस के रिश्ते सहज नहीं हैं। तीन लोकसभा और कई विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद संगठन कांग्रेस की प्राथमिकताओं में नजर नहीं आता। खरगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर अहम फैसले राहुल ही ले रहे हैं। हरियाणा में पिछले नेता प्रतिपक्ष को ही पुनः चुनने में लगभग पूरा साल लग गया। दरअसल मां सोनिया गांधी की कांग्रेस को राहुल अपना नहीं पा रहे और अपनी पसंद की कांग्रेस बनाने का साहस जुटा नहीं पा रहे, जिसका परिणाम नेताओं के पलायन के रूप में भी सामने आ रहा है।

पदयात्रा से राहुल की छवि बेहतर हुई थी, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के चलते उसका ज्यादा चुनावी लाभ मिला नहीं। राहुल की छवि मोदी पर तल्ख हमले करते हुए टकराव की राजनीति करने वाले नेता की बन गई है। उनकी राजनीति और मुद्दों में निरंतरता का अभाव भी है। लोकसभा चुनाव तक ईवीएम पर निशाना साधते हुए संविधान और आरक्षण को खतरा मुद्दा था तो अब वोट चोरी का नारा बुलंद किया जा रहा है। बीच-बीच में राहुल जिस तरह विदेश चले जाते हैं, उससे भाजपा को उनकी अगंभीर राजनेता की छवि बनाने का मौका मिलता है। राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी राहुल से मुलाकात आसान नहीं। इसका असर कांग्रेसियों में पार्टी और अपने भविष्य की चिंता के रूप में सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी में उन्हें बेहतर संभावनाएं दिखती हैं। इंदिरा गांधी की झलक के अलावा राजनीतिक समझ, संवाद और प्रभावी भाषण शैली में प्रियंका, राहुल से बेहतर मानी जाती हैं। इसलिए भी वंदे मातरम् पर संसद में प्रभावशाली भाषण के बाद उन्हें बड़ी राजनीतिक भूमिका की चर्चा जोर पकड़ रही है। प्रियंका का एक ही नकारात्मक पहलू है-पति राबर्ट वाड्रा के विरुद्ध दर्ज मुकदमे। अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खरगे का कार्यकाल 2027 तक है। जाहिर है, प्रियंका की किसी भी नई भूमिका का फैसला सोनिया ही करेंगी, लेकिन वह कब और क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

दायित्वबोध

मानव जीवन के क्षितिज में अधिकार और कर्तव्य ऐसे ध्रुवतारे हैं, जो उसके पथ को आलोकित एवं अनुशासित करते हैं। अधिकार की अभिलाषा तभी पूर्ण और सार्थक होती है, जब व्यक्ति स्वयं को कर्मयोग की अग्नि में तपाकर लोक में प्रतिष्ठित करता है। जो मनुष्य अपने नियत कर्तव्यों की वेदी पर समर्पण नहीं करता, वह अधिकार के प्रसाद की आकांक्षा भी नहीं कर सकता। योग्यता का बीज, तपःपूत कर्म और पुरुषार्थ के मार्ग की वह सीढ़ी है, जिनसे मनुष्य अपनी सदाकांक्षाओं के सुंदर शिखर का दर्शन करता है। इस धरातल पर कोई भी आत्मा जन्म से अधिपति नहीं होती। समष्टि सदैव उसी को नेतृत्व का आशीष प्रदान करती है, जो योग्य, विनीत और लोकहित में प्रतिबद्ध हो।

अधिकार का मोह यदि कर्तव्य-विहीन हो जाए, तो वह अहंकार का बोझ बन जाता है। जो व्यक्ति दायित्वों के निर्वहन के बिना शासक की उपाधि चाहता है, वह ज्ञान के प्रकाश से दूर और भ्रम की गहन गुहा में भटक रहा होता है। ज्ञानी पुरुष भलीभांति समझता है कि परिवार, समाज और समस्त विश्व का संतुलन केवल कर्तव्य-निष्ठा की दृढ़ भूमि पर ही टिका है। अहंकार के कुहासे में डूबा संसार तभी दिव्यता का रूप धारण करता है, जब सत्य, ज्ञान और विवेक का पारस-स्पर्श उसे आलोकित करता है। जैसे ही अहं का आवरण हटता है, वैसे ही समूचा जगत एक विराट परिवार की अनुभूति कराता है, जहां 'मैं और तू' का भेद मिटकर केवल आत्मा का एकत्व ही शेष रह जाता है। निष्कामता, विशुद्ध प्रेम और सरलता, ये वे दिव्य शक्तियां हैं, जो माया के अंधकार को छिन्न-भिन्न कर जीवन में शाश्वत प्रकाश और आनंद भर देती हैं। यही मोक्ष का पावन मार्ग है, जहां कर्तव्य कर्मयोग बनता है तथा प्रेम-स्नेह अधिकार के सारे भ्रमों का भंजन करके आत्मा को उसके सर्वोच्च सत्य की ओर ले जाते हैं।

आचार्य नारायण दास

भारतीय सनातन मूल्यों का सम्मान

योगेंद्र माथुर

दीपावली को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जाना भारतीयों के लिए गौरव का विषय है

प्रकाश पर्व दीपावली को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जाना भारत के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यह भारत की युग-युगीन पर्व परंपराओं, मानवता के कल्याण की कामना और प्रार्थना से जुड़े अनुष्ठानों तथा दुनिया के एक बड़े वर्ग की आस्था, श्रद्धा और विश्वास के सम्मान का क्षण है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्वभर में मानवता के लिए असाधारण महत्व की मानी जाने वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की पहचान, संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। यह उद्देश्य विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण संबंधी सम्मेलन नामक अंतरराष्ट्रीय संधि में निहित है, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 1972 में अपनाया था। विश्व धरोहर की अवधारणा को असाधारण बनाने वाली बात इसका सार्वभौमिक अनुप्रयोग है। विश्व धरोहर स्थल दुनिया के सभी लोगों के होते हैं, चाहे वे किसी भी भूभाग पर स्थित हों। यूनेस्को की परिभाषा के अनुसार सांस्कृतिक विरासत में वे प्रथाएं, ज्ञान, अभिव्यक्तियां, वस्तुएं और स्थान शामिल हैं, जिन्हें समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानते हैं। इस दृष्टि से दीपावली दुनिया के एक बड़े वर्ग की आस्था, श्रद्धा और विश्वास की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पर्व है।

अब तक भारत की 15 प्राचीन परंपराएं, कलाएं और सांस्कृतिक आयोजन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। इस सूची में कुंभ मेला, रामलीला, योग, नवरोज, कूडियाट्टम, कालबेलिया नृत्य, चौहाऊ छऊ नृत्य, बौद्ध चैत्य नृत्य, वैद्यकीय परंपराएं-आयुर्वेदिक ज्ञान, रंजीतगढ़ ढोल, गरबा, सैंध लोक नाट्य परंपरा, मुदियेत्तु, छऊ मुखौटा कला और दुर्गा पूजा उत्सव शामिल हैं। दीपावली के शामिल होने के साथ अब यह संख्या 16 हो गई है। हालांकि भारत की प्राचीनता, ऐतिहासिकता और समृद्ध धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से मात्र 16 परंपराओं और सांस्कृतिक आयोजनों का यूनेस्को की सूची में शामिल होना ''ऊंट के मुंह में जीरे'' के समान है।

वर्तमान में 140 करोड़ आबादी वाले विशाल देश भारत की तुलना में मात्र छह करोड़ की आबादी वाला देश इटली इस सूची में 61 विरासतों के साथ पहले स्थान पर है। हमारी आबादी के ही समतुल्य हमारा पड़ोसी देश चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। किसी भी सांस्कृतिक धरोहर के यूनेस्को की सूची में शामिल होने का अर्थ उसे वैश्विक पहचान मिलना और उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होना है। इससे संबंधित देशों में पर्यटन बढ़ता है और उनके अर्थतंत्र को भी खासा लाभ मिलता है। भारत के लिए यह चिंता और चिंतन का विषय है कि उसकी अन्य समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को भी इस सूची में शामिल कराए जाने के प्रयास किए जाएं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

चिंताओं को न किया जाए अनदेखा

'बढ़ाया जाए सुधारों का दायरा' शीर्षक से लिखे आलेख में जीएन वाजपेयी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राह सुझाई है। इसी संदर्भ में उन्होंने अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था के दमदार प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला है। इसके लिए तमाम जानकार केंद्र सरकार के आर्थिक सुधारों और उसकी सकारात्मक पहल को श्रेय दे रहे हैं। यह अच्छी बात है कि जब तमाम देश वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके बावजूद कुछ बातें परेशान करने वाली भी हैं। जैसे डालर के मुकाबले रुपये का लगातार कमजोर होते जाना। डालर के मुकाबले रुपया 90 का आंकड़ा पार कर गया है। कई महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए आयात पर आश्रित रहने वाली अर्थव्यवस्था के लिए यह शुभ संकेत नहीं। इसके लिए रिजर्व बैंक और सरकार को अपनी तैयारी रखनी होगी। निजी क्षेत्र के निवेश में भी अपेक्षित तेजी नहीं आ रही है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए उपाय आवश्यक हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि संभावनाओं से भरी भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस तेजी में चिंताओं को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

विपक्ष के निशाने पर न्यायपालिका

तमिलनाडु की प्राचीन हिंदू परंपरा कर्तिगाई दीपम के पक्ष में मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले के विरुद्ध जिस प्रकार विपक्ष के 120 सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है, वह सीधे-सीधे न्यायपालिका पर दबाव बनाने का विपक्ष का कुटिल प्रयास है। इस महाभियोग प्रस्ताव से स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने तो मानो हिंदी और हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ने और बोलने को अपना प्रमुख एजेंडा बना लिया है, जबकि तमिलनाडु में हिंदू सनातन धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। न्यायपालिका पर दबाव बनाने के इंडी गठबंधन के इस प्रयास का पुरजोर विरोध होना चाहिए। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को इस महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करते हुए जस्टिस स्वामीनाथन के पक्ष में देशभर में माहौल बनाना चाहिए और इस प्रस्ताव को संसद में भारी मतों से रद करना चाहिए, ताकि दोबारा न्यायपालिका को दबाव में लाने का कोई और कुटिल प्रयास करने का साहस न कर सके।

राजीव वार्ष्णेय, पुरानी पैंठ, चंदौसी

मेलबाक्स

जानलेवा वायु प्रदूषण

सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर तक पहुंच जाना अब एक वार्षिक त्रासदी बन चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हर वर्ष हालात बिगड़ने के बाद ही प्रशासन की कुंभकर्णी निद्रा टूटती है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी पूरी तरह जायज है, क्योंकि यह समस्या तात्कालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और गंभीर बन चुकी है। वायु प्रदूषण की चुनौती अब केवल दिल्ली और एनसीआर तक सीमित नहीं रही। पूरे उत्तर भारत में यह एक व्यापक संकट का रूप ले चुकी है। प्रदूषण के प्रमुख कारणों में धुआं और धूल सबसे आगे हैं। ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों की धीमी गति से निकलने वाला जहरीला धुआं वातावरण को विषाक्त बना रहा है। वहीं लकड़ी, कोयला और उपलों के जलने से निकलने वाला धुआं भी हवा की गुणवत्ता को और खराब कर रहा है। निर्माण कार्यों से उड़ती धूल इस संकट को और गहरा कर रही है। ठंड के मौसम में स्वच्छ हवा अब कुछ गिने-चुने क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गई है। वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। इसके समाधान के लिए केवल प्रशासनिक कदम पर्याप्त नहीं होंगे। सरकार के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व्यवहार से ही इस गंभीर संकट से निपटा जा सकता है।

himanshushekhar.mca@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे सरकार के तीसरे स्तर के रूप में जाना जाता है।

डा. सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन आफ पालिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देहरादून

आजकल

समावेशी विकास की ओर कदम

विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी जी-राम-जी विधेयक ग्रामीण रोजगार नीति को एक नए सोच के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है। यह मनरेगा की मूल भावना से प्रेरणा लेते हुए रोजगार को अवसंरचना निर्माण, आजीविका सृजन और दीर्घकालिक विकास से जोड़ता है। यदि इसे संवेदनशीलता, पारदर्शिता और केंद्र-राज्य सहयोग की भावना के साथ लागू किया जाता है, तो यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है

ग्रामीण भारत को सशक्त बनाए बिना संभव नहीं विकसित भारत का निर्माण। फाइल

करीब एक अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत रोजगार और आजीविका के मामले में संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। जब बात ग्रामीण परिवेश की होती है तो यही संघर्ष कई गुना बढ़ा हुआ नजर आता है। 20 वर्षों से चल रही मनरेगा योजना के स्थान पर केंद्र सरकार नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बना रही है, जिसका नाम है विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी जी-राम-जी बिल। इसमें विकसित भारत-2047 का राष्ट्रीय विजन निहित है। जब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत हुआ तो भारत के समक्ष दो मूल मुद्दे थे-राष्ट्र निर्माण और सामाजिक-आर्थिक प्रगति। इसी पृष्ठभूमि में विकास प्रशासन की अवधारणा सामने आई और समाज के बहुमुखी तथा नियोजित विकास पर बल दिया जाने लगा। आवासविहीन, जड़विहीन और भविष्यविहीन विकास को तभी रोका जा सकता है, जब इसके लिए सुनियोजित और दूरदर्शी कदम निरंतर उठाए जाएं। इसी क्रम में समावेशी विकास की परिकल्पना सामने आती है, जिसमें रोजगार के अवसर निहित होते हैं और गरीबी उन्मूलन को एक केंद्रीय लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। अवसर की समानता, शिक्षा और कौशल के माध्यम से लोगों को सशक्त करना भी इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। बुनियादी सुविधाएं-जैसे आवास, भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना तथा आजीविका के साधनों को निरंतर सुदृढ़ बनाना समावेशी विकास की लक्ष्यभिमुख अवधारणा को स्पष्ट करता है।

उल्लेखनीय है कि देश अनेक ढांचों और उनमें निहित विकास की परतों से युक्त है, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी आयाम शामिल हैं। इसी क्रम में 21वीं सदी के पहले दशक के मध्य में समावेशी विकास को मजबूती देने के उद्देश्य से फरवरी 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में इसे नरेगा अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा गया और दो अक्टूबर, 2009 से महात्मा गांधी का नाम जोड़ते हुए इसे मनरेगा का स्वरूप दिया गया। इसका मूल उद्देश्य देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना था। इस योजना से अब तक करोड़ों नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से एक क्रांतिकारी पहल रही है। इसने समावेशी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ पलायन, गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुशासन की कसौटी पर देखें तो मनरेगा लोक सशक्तीकरण के साथ कदमताल करती हुई आजीविका आधारित बुनियादी विकास की एक प्रभावी व्यवस्था के रूप में सामने आती है।

इसके स्थान पर आ रही जी-राम-जी बिल एक ऐसी ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दिए जाने का प्रविधान है। ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण, मौसम की मार को कम करने के लिए विशेष कार्य, आजीविका से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर और जल से जुड़े कार्य इस नए बिल के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसे पीएम गति शक्ति प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, आय में वृद्धि होगी और सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी तथा बाजार तक पहुंच बेहतर होगी। गांवों में कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी और भंडारण, बाजार एवं उत्पाद के माध्यम से आजीविका के अवसर विस्तारित होंगे। जी-राम-जी बिल के विभिन्न पहलुओं पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो इसमें रोजगार, पारदर्शिता, आजीविका, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अनेक तत्व शामिल हैं, जो ग्रामीण जीवन की दिशा और दशा को बेहतर बना सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का है और इसे हासिल करने के लिए योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन या नई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक होगा। हालांकि भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की चुनौतियां देश में हमेशा से रही हैं। यदि जवाबदेही सुदृढ़ नहीं हुई तो योजना चाहे जितनी भी महत्वाकांक्षी क्यों न हो, अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगी।

आर्थिक सुधारों के संदर्भ में 24 जुलाई, 1991 का उदारीकरण एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसके बाद 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन, जिसे सरकार के तीसरे स्तर के रूप में जाना जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक मजबूत आधार बना। पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि लोकतांत्रिक ढांचा किस प्रकार सशक्त हुआ है। इन्हीं संस्थाओं को मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था और मनरेगा ने मिलकर समावेशी विकास की अवधारणा को मजबूती प्रदान की है। मनरेगा की तरह जी-राम-जी भी मूलतः अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल निर्माण को पर्याप्त बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक स्थायी रोजगार की संभावनाएं सीमित ही रहेंगी।

भारत गांवों का देश है, जहां कई पंचायतें और गांव अब भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में जी-राम-जी योजना एक सशक्त माध्यम बन सकती है। हालांकि मनरेगा भी भ्रष्टाचार और सोशल आडिट जैसी चुनौतियों से जूझती रही है। यही सावधानी जी-राम-जी के संदर्भ में भी आवश्यक होगी कि निगरानी, पारदर्शिता और मूल्यांकन प्रभावी हों, ताकि योजना कागज से निकलकर जमीन पर उतर सके। यह स्पष्ट है कि गांव मजबूत होंगे, तभी देश मजबूत होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार, आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और समावेशन को प्राथमिकता दिए बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। योजनाओं का सही और ईमानदार क्रियान्वयन ही सफलता की कुंजी है। यदि जी-राम-जी योजना इस कसौटी पर खरी उतरती है, तो निस्संदेह यह ग्रामीण आजीविका और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

मनरेगा से आगे : ग्रामीण रोजगार की नई दिशा

देवेंद्रराज सुथार

विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक ग्रामीण भारत के विकास को नए दृष्टिकोण से देखने का संकेत देता है। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को सामने रखकर यह विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केवल मजदूरी आधारित राहत से आगे ले जाकर स्थायी आजीविका और मजबूत अवसंरचना से जोड़ने की मंशा को दर्शाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू गारंटीकृत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करना है। यह कदम सीधे तौर पर ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को मजबूत करता है। बढ़े हुए रोजगार दिवस का अर्थ है अधिक काम के अवसर, अधिक मजदूरी और स्थानीय अर्थव्यवस्था में अधिक नकदी का प्रवाह। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मौसमी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, वहां अतिरिक्त रोजगार दिवस ग्रामीण जीवन में स्थिरता लाने में सहायक हो सकते हैं। यदि इस प्रविधान को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह ग्रामीण गरीबी घटाने और पलायन रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मजदूरी भुगतान का बोझ केंद्र और राज्यों के बीच साझा करने का प्रस्ताव संघीय ढांचे की भावना को मजबूत करता है। इससे राज्य सरकारों की भागीदारी और जवाबदेही बढ़ सकती है। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का अनुपात यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय असमानताओं और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लचीला दृष्टिकोण अपना रही है। अन्य राज्यों के लिए 60:40 का अनुपात राज्यों को योजना के साथ अधिक गहराई से जुड़ने का अवसर देता है। इस साझा जिम्मेदारी से राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कामों की योजना बनाने और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा मिल सकती है।

नए विधेयक में श्रम बजट की मांग-आधारित व्यवस्था के स्थान पर ''मानक आवंटन'' प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भी बेहतर नियोजन की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। वार्षिक आवंटन पहले से तय होने से राज्यों को योजना बनाने में स्पष्टता मिलेगी और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा। इससे परियोजनाओं में अनुशासन आ सकता है और कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिल सकती है। कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों के लिए रोजगार योजना को स्थगित करने का प्रविधान कृषि और ग्रामीण रोजगार नीति के बीच संतुलन स्थापित करने के सोच को दर्शाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बोआई और कटाई जैसे महत्वपूर्ण समय में किसानों को पर्याप्त श्रमिक मिल सकें।

ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड की शुरुआत भी इस विधेयक का एक सराहनीय पहलू है। तीन वर्ष की वैधता वाले इन कार्डों से लाभार्थियों की पहचान और रिकार्ड प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकता है। एकल महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, मुक्त बंधुआ मजदूरों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग रंग के कार्ड जारी करने का प्रस्ताव सामाजिक समावेशन की भावना को मजबूत करता है। इससे इन वर्गों तक योजना का लाभ पहुंचाने में सहूलियत हो सकती है और उनकी विशेष जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है।

(शोधार्थी)

खरी-खरी

डीलिंग का सुख

रोहित कौशिक

अक्सर कस्बों और छोटे शहरों में जो कुछ नहीं करता है, वह प्रोपर्टी डीलिंग का धंधा करने लगता है। हमारे देश में डीलिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आम आदमी से लेकर विशेष आदमी तक और राजनेता से लेकर साहित्यकार तक, सब डीलिंग के माध्यम से ही अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आम आदमी कब विशेष आदमी बन जाता है और विशेष आदमी कब आम आदमी बन जाता है, पता ही नहीं चलता। इसी तरह राजनेता कब साहित्यकार बन जाता है और साहित्यकार कब राजनेता बन जाता है, पता ही नहीं चलता। यह जरूर है कि लोगों को कुछ डीलिंग का पता चल जाता है और कुछ डीलिंग का ताउम्र पता ही नहीं चलता है। असली डीलिंग तो वही है जिसका ताउम्र पता ही न चले।

इस दौर में लगभग हर विभाग में डीलिंग कराने वाले डीलिंग दूत बैठे हुए हैं। इन डीलिंग दूतों से काम कराने वाला भी खुश है और अधिकारी भी खुश हैं। कार्यालय में बैठा हुआ अधिकारी भले ही पत्नी की घर से आई हुई काल न उठाए, लेकिन इन डीलिंग दूतों की काल जरूर उठाता है। हाल में जब स्वयं को ज्यादा समझदार मानने वाले एक ज्यादा पढ़े-खिले इंसान ने डीलिंग दूत को दलाल कहकर संबोधित कर दिया तो डीलिंग दूत ने इस समझदार इंसान पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। डीलिंग दूत का कहना है कि डीलिंग के धंधे की भी अपनी गरिमा होती है। इसलिए यह काम करने वाले लोगों को गरिमा के अनुरूप सम्मानजनक तरीके से ही संबोधित किया जाना चाहिए।

जो लोग डीलिंग दूत को दलाल कहते हैं उन्हें यह भी समझना चाहिए कि बड़ी-बड़ी कंपनियां डीलिंग के लिए प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करती हैं, ताकि वे कंपनी का व्यापार बढ़ाने के लिए बेहतर तरीके से डील कर सकें। कई बार तो राजनेताओं के टिकट भी डील के आधार पर ही तय होते हैं।

इसका अर्थ यह है कि राजनीति के क्षेत्र में भी बड़े-बड़े डीलर बैठे हुए हैं। इसलिए छोटे डीलर को दलाल कहना तो नाइंसाफी है। दलाल तो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

पोस्ट

नेटफ्लिक्स ने 'धुरंधर' की ओटीटी पर जल्द रिलीज के संकेत दिए हैं। इसके बाद भी सिनेमाघरों में भीड़ कम नहीं हो रही है। यह दर्शाता है कि ओटीटी फिल्मों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं। अगर किसी फिल्म में दम होगा तो दर्शक उसे देखने के लिए जरूर उमड़ेंगे।
डा. गौरव गर्ग@DrGauravGarg4

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि भारत को इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं और सैनिकों को किसी अन्य उपयोगी कार्य में लगाया जाए। भारत के अपने पड़ोसियों से पांच प्रत्यक्ष और कई अप्रत्यक्ष युद्ध हो चुके हैं। ऐसे खतरनाक पड़ोसियों के बीच सेना की उपयोगिता पर चर्चा बेमानी है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी घटनाक्रम से किसी को हैरानी हो रही है तो समझिए कि उसने लंबे अर्से से आंखें मूंद रखी थीं। यह तो घटित होना ही था। अगर जमात बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हो गई तो यह स्थिति और विकट हो जाएगी।
हिंदोल सेनगुप्ता@HindolSengupta

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर जाता दिख रहा है?

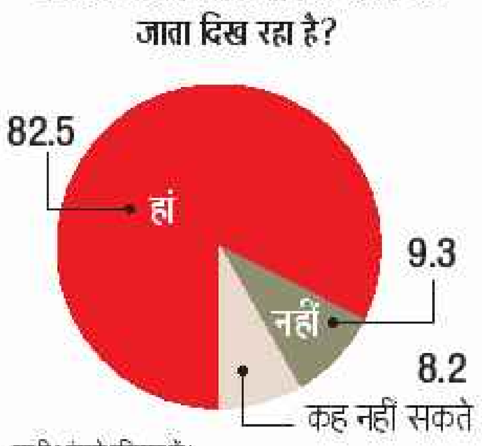

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या वर्तमान परिस्थितियों में भारत को बांग्लादेश में अपना उच्चायोग बंद कर देना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सारे मुस्लिम राष्ट्र का प्रगतिशील परिदृश्य,
केवल भारतवर्ष में 'अल्फलाह' का दृश्य!
'अल्फलाह' का दृश्य पल रहे कट्टरपंथी,
रहो पिलाते दूध न जाए पर विष ग्रंथी।
जन-जन में विष घोल रहे मजहबी इदारे,
तभी हुए बर्बाद दिखें सारे के सारे!!
- ओमप्रकाश तिवारी

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

बकाया भुगतान के लिए केंद्र पर दबाव

झारखंड की सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। विकास के कार्यों पर भी इसका असर पड़ रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, तो झारखंड में तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि झामुमो और कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश करार देते हुए स्पष्ट किया कि उनका गठबंधन अभी मजबूत है और भाजपा के साथ झामुमो के जाने की बातें अफवाह हैं। इस बीच झारखंड सरकार ने एक बार फिर विभिन्न मदों के बकाया भुगतान को लेकर केंद्र पर दबाव बनाया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सदन में कहा था कि केंद्र के मंत्री झारखंड की मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वे बकाया भुगतान करने की तो बात दूर, हम लोगों को मिलने का भी समय नहीं दे रहे हैं। इस बयान के बाद राज्य से लेकर केंद्र तक सरगर्मी बढ़ी हुई दिखाई दी। झारखंड में विपक्षी दल की भूमिका निभा रही भाजपा के नेताओं ने इसे राज्य सरकार की विफलता बताया और कहा कि राज्य की ओर से केंद्र से राशि लेने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

पिछले एक हफ्ते से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर अलग-अलग मदों की राशि जारी करने को लेकर दबाव बढ़ाया है। झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों का कहना है कि ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, पेयजल, आवास और रोजगार से जुड़ी कई केंद्रीय योजनाओं की राशि लंबे समय से अटकी हुई है। केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। 15वें वित्त आयोग की राशि अब तक नहीं मिल सकी है, जबकि कल्याण विभाग को राशि नहीं मिलने के कारण छात्रों की छात्रवृत्ति फंसी हुई है। कई महीनों से गरीब छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति को लेकर परेशान हैं। इधर झारखंड में राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सम्मान राशि देने वाली मंईयां योजना सहित कई ऐसी योजनाएं चला रही है, जिनमें हर महीने अच्छा-खासा बजट खर्च हो रहा है। मंईयां योजना के लिए ही हर महीने डेढ़ हजार करोड़ रुपये की जरूरत होती है। इससे वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में झारखंड सरकार की योजनाएं हो रहीं प्रभावित। फाइल

झारखंड सरकार ने पिछले दिनों राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर कई योजनाएं लांच कीं। इन योजनाओं के लिए भी फंड की आवश्यकता है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तो सदन में विपक्ष के नेता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से यहां तक कह दिया कि हम हार गए, अब आग्रह है कि आप ही केंद्र से बात करके पैसे दिला दीजिए। केंद्र से राशि की मांग को लेकर कई मंत्री दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। पिछले दिनों राज्य की मंत्री दीपिका पांडेय और चमरा लिंडा ने केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात कर बकाया राशि की मांग की। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से 15वें वित्त आयोग की राशि जारी करने का आग्रह किया। वहीं चमरा लिंडा ने केंद्रीय राज्य मंत्री डा. रामदास अठावले से भेंट कर पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार से राशि दिलाने की मांग की।

भाजपा के नेता बता रहे हैं कि राज्य सरकार को फंड नहीं मिलने के पीछे तकनीकी खामियां हैं, जिनकी ओर वे लगातार इशारा कर रहे हैं। उधर राज्य सरकार का कहना है कि जरूरी दस्तावेज और उपयोगिता प्रमाण पत्र समेत सभी शर्तें और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि की पहली किस्त के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इससे बड़ी राहत मिलेगी। दीपिका पांडेय ने इसके लिए आभार भी जताया है।

झारखंड सरकार की केंद्र से बकाये को लेकर पहले भी खींचतान रही है। हेमंत सरकार लंबे समय से खनिज रायल्टी मद में एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये के बकाये की मांग केंद्र से जोर-शोर से करती रही है। चुनावों के समय भी यह बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि केंद्र सरकार राज्य सरकार के इस दावे को खारिज करती आ रही है। इन सबके बीच केंद्र और राज्य, दोनों को समन्वय से काम करना होगा, ताकि विकास कार्यों में रुकावट न आए। बकाया और भुगतान से जुड़ी औपचारिकताएं भी ईमानदारी से पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि केवल हंगामे से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होने वाला। अब देखना यह है कि केंद्र क्या कदम उठाता है और राज्य सरकार इस संकट से कैसे बाहर निकलती है।

गोवा मुक्ति दिवस

अभिषेक रंजन सिंह
अध्यक्ष, डा. राममनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन, दिल्ली

गोवा स्वतंत्रता संग्राम की अनदेखी

गोवा को आजाद हुए छह दशक से अधिक समय बीत चुका है, किंतु यह मुक्ति पर्व आज भी मुख्यतः गोवा तक ही सीमित रह गया है। यह दिन पूरे भारत का उत्सव होना चाहिए

आज गोवा मुक्ति दिवस की 64वीं वर्षगांठ है। यह दिन न केवल गोवा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है। साढ़े चार सौ वर्षों के पुर्तगाली शासन के बाद 19 दिसंबर, 1961 को गोवा, दमन और दीव यूरोपीय उपनिवेशवाद से मुक्त हुए। यह दिन गोवा मुक्ति आंदोलन के महानायक डा. राममनोहर लोहिया के अदम्य साहस और ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करने का भी अवसर है। 18 जून, 1946 जिसे गोवा में 'क्रांति दिवस' के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है-कोई सामान्य तिथि नहीं है। इसी दिन डा. राममनोहर लोहिया ने गोवा में नागरिक अधिकारों का प्रश्न उठाकर औपनिवेशिक शासन को खुली चुनौती दी थी। उस दौर में गोवा में स्थिति इतनी दयनीय थी कि लोगों को विवाह के निमंत्रण-पत्र छापने तक की अनुमति नहीं थी, सार्वजनिक सभा करना भी प्रतिबंधित था।

भारत की आजादी के चौदह वर्ष बाद गोवा स्वतंत्र हुआ। यह प्रश्न आज भी उठता है कि आजाद भारत के भीतर रहते हुए भी गोवावासियों को लगभग डेढ़ दशक तक पुर्तगाली शासन क्यों झेलना पड़ा? तत्कालीन सरकार की विवशताएं क्या थीं? इन प्रश्नों पर बहस होती रही है। किंतु दोषारोपण में उलझने के बजाय यह अधिक प्रासंगिक है कि हम आज गोवा मुक्ति आंदोलन के नायकों को किस रूप में स्मरण कर रहे हैं। गोवा साढ़े चार सौ वर्षों तक पुर्तगाली दासता में रहा। यह कोई छोटा कालखंड नहीं है, किंतु दुर्भाग्यवश गोवा मुक्ति संग्राम और उसके स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास लेखन में वह स्थान नहीं मिला, जिसके वे अधिकारी थे। परिणामस्वरूप आज देश के छात्रों और युवाओं में इस आंदोलन के प्रति पर्याप्त जानकारी का अभाव है। गोवा की आजादी केवल गोवावासियों की नहीं, बल्कि पूरे भारत की आजादी का अभिन्न हिस्सा है। आजादी को न तो छोटा-बड़ा कहा जा सकता है और न ही इसे समय-सीमा के आधार पर आंका जाना चाहिए। आज गोवा की पहचान प्रायः पर्यटन स्थल के रूप में बन गई है, जबकि डा. राममनोहर लोहिया ने 1946 में अपनी पुस्तक 'एक्शन इन गोवा' में इसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य की दूरदर्शी कल्पना प्रस्तुत की थी।

गोवा की आजादी में डा. लोहिया के साथ-साथ टीबी कुन्हा, मनोहर राय सरदेसाई और बालकृष्ण भगवंत बोरकर जैसे मराठी और कोंकणी साहित्य के महान रचनाकारों का भी अमूल्य योगदान रहा। 18 जून, 1946 की ऐतिहासिक घटना के बाद गोवा मुक्ति आंदोलन में देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों लोग शामिल हुए और अनेक ने अपने जीवन का बलिदान दिया। डा. लोहिया ने इस आंदोलन को क्षेत्रीय न रखकर राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया। यही कारण था कि 1954-55 के दौरान त्रिदीब चौधुरी, मधु लिमये, जगन्नाथ राव जोशी और जमुना प्रसाद शास्त्री जैसे नेताओं ने गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और महीनों जेल की यातनाएं सहीं।

19 दिसंबर, 1961 को गोवा की स्वतंत्रता ने विश्व के अनेक देशों को प्रेरणा दी। पुर्तगाली उपनिवेशवाद की समाप्ति ने अंगोला, मोजाम्बिक, गिनी-बिसाऊ, केपवर्डे, साओ टोमे और प्रिंसिपे जैसे अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों को नई दिशा दी, जिन्हें 1970 के दशक के मध्य में आजादी मिली। गोवा की मुक्ति ने यह सिद्ध किया कि लंबे समय से चले आ रहे औपनिवेशिक शासन को समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एशिया और अफ्रीका में घाना (1957), मलेशिया (1957), तंजानिया (1961), अल्जीरिया (1962), सिंगापुर (1965), जांबिया (1964) और मालदीव (1965) जैसे देशों के राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी इससे प्रेरणा मिली। घाना जैसे नवस्वतंत्र देशों के नेताओं ने गोवा की आजादी को उपनिवेशवाद के खिलाफ एक निर्णायक झटका माना। पुर्तगाली भारत के पतन ने वैश्विक 'डी-कोलोनाइजेशन' की प्रक्रिया को गति दी और यह स्पष्ट कर दिया कि यूरोपीय साम्राज्यों का अंत निकट है।

भारत की आजादी के आंदोलन की तरह इतिहास में प्रमुखता से शामिल हो गोवा मुक्ति संग्राम। फाइल

गोवा को आजाद हुए छह दशक से अधिक समय बीत चुका है, किंतु यह मुक्ति पर्व आज भी मुख्यतः गोवा तक ही सीमित रह गया है। यह दिन पूरे भारत का उत्सव होना चाहिए। माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों में गोवा मुक्ति संग्राम और उसके महानायकों का समुचित उल्लेख होना आवश्यक है। सरकार को इस दिशा में गंभीर पहल करनी चाहिए। गोवा मुक्ति आंदोलन कोई साधारण घटना नहीं थी। साढ़े चार सौ वर्षों की दासता ने गोवा की सभ्यता और संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई। इसलिए देश की युवा पीढ़ी को इस गौरवशाली संघर्ष से परिचित कराना समय की आवश्यकता है।

****

भारत में तीन नए माडल लांच करेगी निसान

नई दिल्ली: जापानी कार निर्माता निसान ने गुरुवार को कहा है कि वह भारत में विस्तार की योजना बना रही है और अगले 14-16 महीनों के दौरान यहां तीन नए माडल लांच किए जाएंगे। कंपनी ने गुरुवार को अपनी आगामी सात सीट वाली गाड़ी 'ग्रेवाइट' का नाम की भी घोषणा की। ग्रेवाइट 2026 की शुरुआत में लांच की जाएगी। 2026 के मध्य में एसयूवी टेक्टन और 2027 की शुरुआत में एक और सात सीट वाली गाडी लांच की जाएगी। (प्रेट्र)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन पेशेवरों की नौकरी के लिए जोखिम बन रहा है जो सोचने-समझने की स्किल्स पर निर्भर हैं। यह पिछले तकनीकी बदलावों से एक बड़ा बदलाव है।

— एस. कृष्णन, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सेंसेक्स	84,481.81	▼ 77.84	
निफ्टी	25,815.55	▼ 3.0	
सोना प्रति दस ग्राम	₹1,36,500	बदलाव नहीं	
चांदी प्रति किलोग्राम	₹2,07,600	▲ ₹1,800	
डालर	₹90.20	▼ ₹0.18	
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$59.93		

एक नजर में

दो प्रतिशत तक महंगे होंगे जेएसडब्ल्यू एमजी के वाहन

नई दिल्ली: जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने गुरुवार को कहा कि एक जनवरी 2026 से उसके वाहन दो प्रतिशत तक महंगे हो जाएंगे। कंपनी ने कहा कि बढ़ती इनपुट लागत के असर को कम करने के लिए वाहनों के मूल्य में बढ़ोतरी की जा रही है। कीमत में बढ़ोतरी माडल और वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग होगी। इससे पहले लक्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज इंडिया और बीएमडब्ल्यू भी अगले महीने से अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी की योजना की घोषणा कर चुकी हैं। (प्रेट्र)

टेक स्टार्टअप ने 2025 में 10.5 अरब डालर जुटाए

नई दिल्ली: देश के टेक स्टार्टअप ने इस साल अब तक 10.5 अरब डालर जुटाए हैं। 2024 में तकनीकी कंपनियों ने 12.7 अरब डालर जुटाए थे। फंडिंग जुटाने के मामले में भारत चीन और जर्मनी से आगे है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन से पीछे है। बेंगलुरु और मुंबई सबसे ज्यादा फंडिंग जुटाने वाले शहर बनकर उभरे। मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफार्म ट्रैक्शन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मंदी के बावजूद भारत दुनियाभर में तीसरा सबसे ज्यादा फंडिंग जुटाने वाले टेक इकोसिस्टम के तौर पर उभरा है। फंडिंग के रुझान अलग-अलग चरणों में अलग-अलग रहे हैं। (प्रेट्र)

आइसीआइसीआइ बैंक से 238 करोड़ जीएसटी मांगा

नई दिल्ली: आइसीआइसीआइ बैंक ने गुरुवार को कहा कि कर अधिकारियों ने कथित तौर पर जीएसटी का कम भुगतान करने के लिए उसे 238 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है। बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि महाराष्ट्र के जीएसटी अधिकारियों की ओर से 17 दिसंबर को भेजे गए नोटिस में 216.17 करोड़ रुपये के टैक्स और 21.62 करोड़ रुपये के जुर्माने की मांग की गई है। हालांकि, बैंक पहले उठाए गए इस तरह के मामलों को पहले भी चुनौती दे चुका है। ताजा मामले को भी निर्धारित समय सीमा में चुनौती दी जाएगी। (प्रेट्र)

रुपये में गिरावट को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं

पीएम-ईएसी के सदस्य ने कहा- तेज आर्थिक विकास के दौरान चीन और जापान की मुद्राएं भी गिरी थीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम-ईएसी) के सदस्य संजीव सान्याल ने गुरुवार को कहा कि उन्हें डालर के मुकाबले रुपये की गिरावट को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि तेज आर्थिक विकास दर के दौरान चीन और जापान की मुद्राओं में गिरावट दर्ज की गई थी।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सान्याल ने कहा कि पिछली सदी के नौवें दशक से रुपये का अपना स्तर खुद तय करने की अनुमति दी गई है। हालांकि अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए आरबीआइ अपने भंडार का उपयोग करता है। सान्याल ने कहा कि रुपये और उसकी मौजूदा कमजोरी को जरूरी नहीं कि किसी आर्थिक चिंता से जोड़ा जाए, क्योंकि यदि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो पाएंगे कि जो अर्थव्यवस्थाएं अपने उच्च विकास चरण में होती हैं, वे अक्सर विनिमय दर में कमजोरी के दौर से गुजरती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जब जापानी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो उसकी विनिमय दर काफी कमजोर रखी गई थी। इसी तरह चीनियों ने 90 और 2000 के दशक में ऐसा किया था जब तक कि उन्होंने युआन को मजबूत होने की अनुमति नहीं दी।

अमेरिका ने दो अप्रैल, 2025 को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का एलान किया था। उस समय से लेकर अब तक भारतीय मुद्रा डालर के मुकाबले 5.6 प्रतिशत कमजोर हुई है। विभिन्न देशों की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।

- अमेरिका के टैरिफ एलान के बाद से अब तक भारतीय मुद्रा 5.6 प्रतिशत कमजोर हुई
- विभिन्न देशों की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई

नई दिल्ली में गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते पीएम-ईएसी के सदस्य संजीव सान्याल • वीडियोग्रैब

भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जो अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुके

भारत-अमेरिका व्यापार सौदे पर एक सवाल का जवाब देते हुए सान्याल ने कहा, 'भारत यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका के साथ बहुत आक्रामक तरीके से व्यापार वार्ता कर रहा है। हालांकि जैसे-जैसे इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ऐसे फैसले लेने होंगे जहां कुछ समझौते करने होंगे। हालांकि हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी समझौता हो, वह राष्ट्रीय हित में हो। जहां तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात है तो हमने कोई रियायत नहीं दी है। सच में भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जो अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुके हैं। भारत और अमेरिका अपने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के 'बहुत करीब' हैं।

रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 90.20 पर पहुंचा

नई दिल्ली, प्रेट्र: रुपया गुरुवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 18 पैसे मजबूत होकर 90.20 प्रति डालर पर बंद हुआ। आरबीआइ के संभावित हस्तक्षेप से विदेशी बाजार में डालर की व्यापक मजबूती के बावजूद घरेलू मुद्रा बढ़त में रही। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि ब्रेंट क्रूड की कीमत 59 डालर प्रति बैरल के आसपास बनी रहने से घरेलू मुद्रा को निचले स्तर पर समर्थन मिला। हालांकि, डालर सूचकांक में सुधार और घरेलू बाजारों की कमजोरी ने तेज बढ़त को सीमित कर दिया। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डालर के मुकाबले 90.35 पर खुला। फिर कुछ हद तक उबरकर 90.04 प्रति डालर के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 34 पैसे की बढ़त दर्शाता है। अंत में यह 90.20 प्रति डालर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 18 पैसे अधिक है। रुपया बुधवार को 90.38 प्रति डालर पर बंद हुआ था। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि आरबीआइ के डालर की बिक्री से रुपये में मजबूती आई है।

देश में 71 करोड़ से ज्यादा यूपीआइ क्यूआर कोड सक्रिय

मुंबई, प्रेट्र: जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) के जरिये लेनदेन का आकार साल-दर-साल 33.5 प्रतिशत बढ़कर 59.33 अरब पहुंच गया। वहीं लेनदेन का आकार 21 प्रतिशत बढ़कर 74.84 लाख करोड़ रुपये हो गया। देश में लगभग 71 करोड़ सक्रिय यूपीआइ क्यूआर कोड हो गए हैं जो जुलाई, 2024 के मुकाबले 21 प्रतिशत ज्यादा हैं। वर्ल्डलाइन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, किराना स्टोर, फार्मेसी, ट्रांसपोर्ट हब और ग्रामीण बाजारों में क्यूआर की व्यापक स्वीकृति ने स्कैन-एंड-पे को देशभर में डिफाल्ट पेमेंट मोड बना दिया है।

व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेन व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) लेनदेन से ज्यादा रहा और यह रोजमर्रा के रिटेल पेमेंट में यूपीआइ के दबदबे को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पी2एम लेनदेन 35 प्रतिशत बढ़कर 37.46 अरब लेनदेन हो गए जबकि पी2पी लेनदेन 29 प्रतिशत बढ़कर 21.65 अरब लेनदेन हो गए।

- जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान यूपीआइ से 59.33 अरब लेनदेन
- इस दौरान यूपीआइ से 74.84 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन

औसत लेनदेन का आकार घटकर 1,262 रुपये (1,363 रुपये से) हो गया, जो मोबिलिटी, भोजन, स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीजों और हाइपरलोकल कामर्स जैसे छोटे लेनदेन के लिए बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। जुलाई, 2024 से जुलाई, 2025 के दौरान पाइंट आफ सेल (पीओएस) टर्मिनल से ट्रांजेक्शन 35 प्रतिशत बढ़कर 1.21 करोड़ हो गए। क्रेडिट कार्ड की संख्या आठ प्रतिशत बढ़कर 11.33 करोड़ हो गई है।

सावधानी से भरें 3बी रिटर्न, नहीं कर सकेंगे संशोधित

जागरण संवाददाता, कानपुर : जीएसटी में नवंबर से 3बी रिटर्न को संशोधित करने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसलिए उद्यमियों व व्यापारियों को जीएसटीआर-1 रिटर्न भरने में अब और अधिक सावधान रहना होगा। इसमें पिछले माह की बिक्री व टैक्स की गणना ठीक से करनी होगी।

जीएसटीआर-1 की बिक्री के हिसाब से ही जीएसटीएन पोर्टल में प्रत्येक माह की 20 तारीख को भरे जाने वाले 3बी रिटर्न में टैक्स देना होता है। ऐसे में, अब बिक्री की गलत जानकारी को 3बी रिटर्न में संशोधित नहीं किया जा सकेगा और उस पर टैक्स देना होगा। हालांकि, जीएसटीएन पोर्टल में एक राहत भी दी गई है। पोर्टल पर 11 तारीख तक जीएसटीआर-1 रिटर्न भर देते हैं और गलती हुई है तो उसे सही करने के लिए जीएसटीआर 1-ए फार्म उपलब्ध है। बस इस फार्म को व्यापारियों को 20 तारीख को 3बी रिटर्न दाखिल करने से पहले भरना होगा। इसके बाद संशोधित फार्म के मुताबिक ही टैक्स आएगा।

जीएसटीआर-1 रिटर्न भरने में कोई भी गलती की तो उसका उठाना पड़ सकता है नुकसान, जीएसटीआर 1-ए देगा राहत

मर्चेंट्स चैंबर आफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष संतोष गुप्ता के मुताबिक, 3बी रिटर्न को संशोधित करने की सुविधा खत्म तो हुई है, लेकिन जीएसटीआर 1-ए उद्यमियों व व्यापारियों के लिए मददगार बनेगा। करदाता 20 तारीख को 3बी रिटर्न फाइल करने से पहले जीएसटीआर 1-ए के जरिये जीएसटीआर-1 को संशोधित कर देते हैं तो उन्हें संशोधित रिटर्न के आंकड़ों के आधार पर 3बी रिटर्न मिलेगा और उसी के आधार पर टैक्स जमा करना होगा।

इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरटन ने हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदी

नई दिल्ली, प्रेट्र: ग्लोबल कंज्यूमर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरटन ने देश के प्रमुख स्नैक और फूड ब्रांड हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदी है। लगभग 39 अरब डालर की इक्विटी कैपिटल को प्रबंधित करने वाली एल कैटरटन ने यह नहीं बताया है कि उसने कितने वैल्यूएशन पर हिस्सेदारी हासिल की है। एल कैटरटन ने एक बयान में कहा है, 'इस सहयोग का मकसद हल्दीराम की मजबूत बुनियाद, ब्रांड इक्विटी और विकास क्षमता के दम पर उसकी मार्केट लीडरशिप को मजबूत करना और उसके अंतरराष्ट्रीय विस्तार को तेज करना है।'

इस साल की शुरुआत में हल्दीराम ने तीन रणनीतिक निवेशकों सिंगापुर स्थित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म टेमसेक, अल्फा वेव ग्लोबल और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (आइएचसी) को हिस्सेदारी बेची थी। उस समय भी सौदे की रकम की जानकारी नहीं दी गई थी।

चीनी का एमएसपी बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार चीनी उद्योग की वित्तीय स्थिति और गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) की वार्षिक आम बैठक के मौके पर खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार को उद्योग की चिंताओं का पूरा अंदाजा है और अगले एक से डेढ़ महीने में इस दिशा में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य अतिरिक्त चीनी स्टाक को संभालना और किसान हितों की रक्षा करना है।

इसके पहले चीनी उद्योग ने सरकार को आगाह किया था कि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही गन्ना बकाया तेजी से बढ़ना शुरू हो सकता है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। इस स्थिति से बचने के लिए इस्मा ने मांग की है कि चीनी का एमएसपी मौजूदा 33 रुपये किलो से बढ़ाकर कम से कम 41.66 रुपये प्रति किलो किया जाए, ताकि उत्पादन लागत निकल सके और मिलों की नकदी स्थिति सुधरे। बैठक में गौतम गोयल की जगह नीरज शिरगांवकर को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष और माधव बंशीधर श्रीराम को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। खाद्य सचिव ने आश्वस्त किया कि सरकार इसका अहसास है और समय-सीमा को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, ताकि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

- खाद्य सचिव बोले-चीनी उद्योग की चिंताओं का पूरा अंदाजा है
- एक से डेढ़ महीने में अहम फैसले ले सकती है केंद्र सरकार

महाराष्ट्र में गन्ना बकाया दो हजार करोड़ के स्तर पर पहुंचा

इस्मा के अनुसार, 30 नवंबर तक सिर्फ महाराष्ट्र में गन्ना बकाया करीब दो हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश के आंकड़े अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन्हीं दोनों राज्यों से आता है। ऐसे में इन राज्यों में बकाया बढ़ना बड़ी चिंता का विषय माना जा रहा है।

उद्योग का कहना है कि चीनी मिलों पर दबाव कई वजहों से बढ़ा है। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट आई है, उत्पादन लागत ऊंची बनी हुई है और वैश्विक स्तर पर भी चीनी की अधिक उपलब्धता का असर पड़ रहा है। चीनी से एथेनाल बनाने की हिस्सेदारी इस सत्र में घटकर 28 प्रतिशत रह गई है, जिससे मिलों की आय पर असर पड़ा है।

चीनी उत्पादन 343 लाख टन होने का अनुमान

खाद्य सचिव ने बताया कि 2025-26 सत्र में एथनाल डायवर्जन के बाद देश में चीनी उत्पादन लगभग 343 लाख टन का अनुमान है। सरकार निर्यात समता (एक्सपोर्ट पैरिटी), बफर स्टाक और निर्यात जैसे विकल्पों पर भी नजर बनाए हुए है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सीजन के अंत तक चीनी का स्टाक संतुलित स्तर पर रहे, ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

अब एआइ से मिलेगी असीमित स्वच्छ ऊर्जा

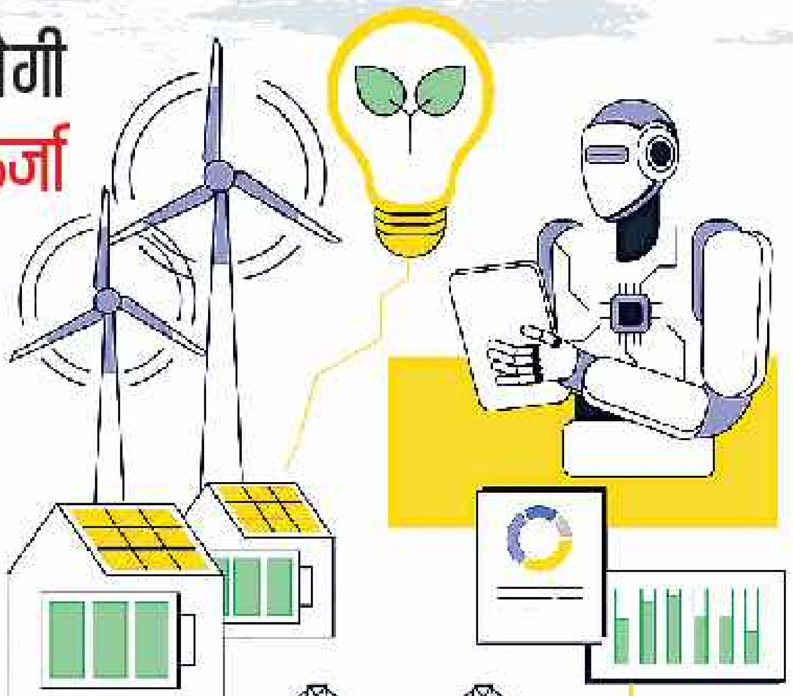

न्यूक्लियर फ्यूजन में विज्ञानियों को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिससे दुनिया असीमित स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने की दिशा में और करीब पहुंच गई है। ब्रिटेन और आस्ट्रिया के विज्ञानियों ने एक नया एआइ उपकरण गाइरोस्विन विकसित किया है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को सिमुलेट कर सकता है। यह उपकरण उन गणनाओं को कुछ ही सेकेंड में पूरा कर लेता है, जिन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटरों को भी पूरा करने में कई दिन लगते हैं।

अनिश्चित काल तक फ्यूजन बनाए रखने में मिलेगी मदद

समस्या यह है कि फ्यूजन रिएक्टरों में अत्यधिक गर्म प्लाज्मा टरबुलेंस नामक प्रक्रिया में उछलता रहता है। टरबुलेंस के कारण प्लाज्मा अपने चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, जिससे फ्यूजन प्रतिक्रिया की क्षमता कम हो जाती है। वर्तमान में फ्यूजन प्रतिक्रिया का रिकार्ड वेंडेलस्टीन 7-एक्स फ्यूजन उपकरण के पास है, जिसने 43 सेकेंड तक फ्यूजन बनाए रखा। फ्यूजन प्रतिक्रिया को अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए, विज्ञानियों को विभिन्न परिस्थितियों में टरबुलेंस के निर्माण की अत्यंत सटीक सिमुलेशन की आवश्यकता होती है। गाइरोस्विन रिएक्टरों को अनिश्चित काल तक फ्यूजन बनाए रखने में मदद कर सकता है।

सूर्य की नकल करते हैं फ्यूजन रिएक्टर

न्यूक्लियर फ्यूजन में स्वच्छ ऊर्जा का लगभग अनंत स्रोत बनाने की क्षमता है। इसमें केवल दो प्रकार के हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम की आवश्यकता होती है, जबकि एकमात्र उप-उत्पाद हीलियम है। इसका मतलब है कि इससे न तो लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी कचरे के ढेर बनेंगे और न ही ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होगा जिससे पृथ्वी को नुकसान पहुंचे। फ्यूजन रिएक्टर सूर्य के केंद्र में होने वाली प्रक्रियाओं की नकल करते हैं, जहां हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं। हालांकि, पृथ्वी पर एक लघु तारा बनाने के लिए प्लाज्मा को लगभग 10 करोड़ सेंटीग्रेड तक गर्म करना और फ्यूजन के लिए इसे पर्याप्त गर्म और सघन बनाए रखना आवश्यक है। चूंकि कोई भी पदार्थ इतने अधिक तापमान को सहन नहीं कर सकता, इसलिए विज्ञानी टोकामाक नामक अंगूठी के आकार के उपकरण का उपयोग करके प्लाज्मा को चुंबकीय पिंजरे में फंसा लेते हैं। हालांकि, प्लाज्मा अशांत होने के कारण समय के साथ पिंजरे से बाहर निकलने लगता है। गाइरोस्विन के सिमुलेशन की मदद से, इंजीनियर इन चुंबकीय क्षेत्रों को सटीक रूप से समायोजित करके एक स्थिर फ्यूजन प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकेंगे।

दिनों में नहीं, सेकेंडों में होगी गणना

वर्तमान में सर्वोत्तम सिमुलेशन प्लाज्मा के कणों को सुपरकंप्यूटरों पर पांच आयामों में ट्रैक करते हैं, लेकिन इन सिमुलेशन को पूरा होने में कई दिन लगते हैं। गाइरोस्विन सिमुलेशन के परिणाम के बारे में दिनों के बजाय सेकेंडों में बता सकता है। विज्ञानियों ने कहा कि इस प्रकार के 'एआइ सरोगेट माडल' नए नहीं हैं, लेकिन गाइरोस्विन की सबसे रोमांचक बात इसकी सटीकता है। यह पहला माडल है जो वास्तव में प्लाज्मा टरबुलेंस पर माडल करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि माडल पहले से ही प्लाज्मा टरबुलेंस की अंतर्निहित भौतिकी को समझने के संकेत दिखाने लगा है। हालांकि गाइरोस्विन को अपने प्रशिक्षण में सुधार जारी रखने के लिए कुछ पारंपरिक सिमुलेशन की आवश्यकता होगी। इसके बाद यह कार्यशील परमाणु रिएक्टरों के उत्पादन में तेजी ला सकता है जिससे असीमित स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी।

जागरण रिसर्च

सट्टेबाजी में ईडी ने यूट्यूबर अनुराग व परिवार के बैंक खाते सीज कराए, चार लग्जरी कारें जब्त

जागरण संवाददाता, उन्नाव

आनलाइन फैंटसी क्रिकेट गेमिंग एप ड्रीम-11 का प्रमोशन करने वाले यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के यहां उन्नाव और लखनऊ में बुधवार सुबह शुरू हुई ईडी की कार्रवाई 18 घंटे तक चली। ईडी के अनुसार अनुराग ने अवैध आनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्म को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। हवाला आपरेटरों, फर्जी खातों व बिचौलियों के माध्यम से बड़े स्तर पर अवैध भुगतान प्राप्त किए गए और दुबई में रियल एस्टेट में निवेश किया। उनकी कंपनियों के बैंक खातों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में बड़ी रकम मिली है, जो किसी वैध व्यवसाय से अर्जित नहीं लगती है। ऐसे सभी बैंक खातों को सीज किए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नवाबगंज में जिन बैंकों में खाते हैं, सभी को सीज भी कर दिया गया है। टीम ने उनकी 4.18 करोड़ रुपये कीमत की लैंबोर्गिनी उरुस के साथ ही मर्सिडीज समेत चार लग्जरी कारें भी जब्त कर ली हैं।

ईडी के अनुसार अनुराग पर बंगाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध सट्टेबाजी सामने आने के बाद ईडी ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज सहित कुछ अन्य लोग सिलीगुड़ी से एक आनलाइन सट्टेबाजी का पैनल चला रहे थे। आनलाइन सट्टेबाजी और जुआ की गतिविधियों को चलाने के लिए फर्जी बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और अन्य डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी मामले में ईडी की 16 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह छह बजे 10 वाहनों से नवाबगंज क्षेत्र में अनुराग के गांव भितरेपार खजूर पहुंची। टीम ने उनके पिता पूर्व प्रधान लक्ष्मी नाथ द्विवेदी से पूछताछ की और चाचा पप्पू द्विवेदी के यहां छानबीन की। रात करीब 12 बजे टीम लौट गई। टीम ने जमीनों से जुड़े दस्तावेज देखे। जमीन की खरीदफरोख्त के बारे में जानकारी ली और सभी दस्तावेज कब्जे में ले लिए। एक पैन ड्राइव भी टीम अपने साथ ले गई। टीम ने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र की कार की भी तलाशी ली। उसमें मिले कुछ कागजात साथ ले गई है।

ईडी के अनुसार अवैध तरीके से मोटी रकम इकट्ठा करने के बाद अनुराग द्विवेदी भारत छोड़कर दुबई चले गए और वहीं रह रहे हैं। उन्हें अब तक कई समन जारी किए गए पर वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद बुधवार को यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी और भारत में सट्टेबाजी एप के इन्फ्लुएंसर से जुड़े नौ स्थानों पर तलाशी ली गई।

- 18 घंटे की जांच के बाद लौटी टीम, आय से जुड़े 500 पेज से अधिक दस्तावेज व हार्ड डिस्क ले गई
- अनुराग के पास लैंबोर्गिनी-मर्सिडीज जैसी कारें, हवाला के जरिये दुबई में रियल एस्टेट में निवेश का आरोप

अनुराग द्विवेदी अपनी लग्जरी कार के साथ। फाइल

'परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उपयोग तभी, जब वह दोषी होने की ओर संकेत करे'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी आपराधिक मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का इस्तेमाल अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए केवल तभी किया जा सकता है, यदि वह इस प्रकार का हो जो केवल उसके दोषी होने की ओर संकेत करे। जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने 2004 के एक हत्या मामले में आरोपित की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को रद करते हुए इस कानूनी सिद्धांत को दोहराया कि केवल "अंतिम बार साथ देखे जाने" का नियम उन मामलों में दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए अपर्याप्त है, जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं।

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस मिश्र ने कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र में यह एक स्थापित नियम है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने का आधार तभी बनाया जा सकता है जब वह केवल उसके अपराध की पुष्टि करता हो। प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव वाले मामले में परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जो अभियुक्त के निर्दोष होने की सभी संभावनाओं को खारिज कर दें। यदि किसी विशेष मामले में परिस्थितियां आरोपित को निर्दोष बताने वाला हो, तो उसे संदेह का लाभ दिया जाएगा। पीठ ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में महत्वपूर्ण कमियां पाईं और याचिकाकर्ता मनोज उर्फ मुन्ना को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

- शीर्ष अदालत ने आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया

बैंक ठगी में भगोड़ा घोषित अपराधी को सीबीआइ ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने 2013 के 17 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित एक भगोड़े को गोवा से गिरफ्तार कर किया है। सीबीआइ के एक बयान में कहा गया है कि पुणे के इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित आशुतोष पंडित ने जांचकर्ताओं से बचने के लिए अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट बदल दिए थे और यतिन शर्मा की फर्जी पहचान से रह रहा था।

जांच के दौरान और 2013 में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद आरोपित का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। हालांकि, वह लापता रहा। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आशुतोष पंडित को अप्रैल 2018 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया।

वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक नया लोगो किया जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक नया लोगो गुरुवार को जारी किया। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 'एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' के सिद्धांत पर, 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण किया है, जो एक मई 2025 से प्रभावी हो गया। वर्तमान में 28 आरआरबी 700 से अधिक जिलों में 22,000 से अधिक शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे हैं। गहरा नीला रंग वित्त और विश्वास का प्रतीक है जबकि हरा रंग जीवन एवं विकास का प्रतीक है जो ग्रामीण भारत की सेवा करने के उनके मिशन को प्रतिबिंबित करता है।

नए साल से दूसरे राज्यों के निजी वाहनों को उत्तराखंड में देना होगा ग्रीन सेस

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून: उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों से एक जनवरी से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जा रहा है। अब इसमें निजी वाहनों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके तहत हल्के मोटर वाहन यानी कारों और हल्के माल वाहक वाहनों से 80 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। 12 सीट से अधिक क्षमता वाली बस से 140 रुपये लिए जाएंगे। सेवन एक्सेल वाले भारी वाहनों से 700 सेस वसूल होगा। इसके तहत 20 दिनों का एकमुश्त सेस जमा करने पर तीन माह तक सेस जमा कराने की छूट और 60 दिन का एकमुश्त सेस जमा करने पर वर्ष भर सेस जमा करने की छूट मिलेगी।

****

65 कनाडा के सांसदों ने फालुन गोंग अनुयायियों का विश्वभर में दमन करने के लिए चीन की निंदा की है। सांसदों का कहना है कि बीजिंग द्वारा फालुन गोंग अनुयायियों पर हो रहे दमन को रोकना होगा और कम्युनिस्ट सरकार को चीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद करना होगा।

चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' रणनीति के खिलाफ जरूरी है ओमान का सहयोग

भारत-ओमान ने सामुद्रिक सहयोग के लिए दृष्टि प्रपत्र को दी मंजूरी, मोदी व सुल्तान हैथम के बीच द्विपक्षीय वार्ता में बनी सहमति

जयप्रकाश रंजन • जागरण

नई दिल्ली : गुरुवार को भारत और ओमान के बीच सामुद्रिक क्षेत्र में सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए एक दृष्टि प्रपत्र पर सहमति बनी है। इसे हिंद महासागर व खाड़ी के क्षेत्र में भारत के ऊर्जा व रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उक्त सहमति पीएम नरेन्द्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बनी, जिसकी घोषणा बाद में दोनों देशों की तरफ से की गई। वैसे भी चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' के खिलाफ ओमान का सहयोग जरूरी है। मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार शाम को ओमान पहुंचे थे।

मोदी की यह ओमान यात्रा भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। उन्होंने सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर बात की। बैठक में मोदी और सुल्तान ने भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने को द्विपक्षीय साझेदारी में एक मील का पत्थर बताया। गुरुवार को ही भारत-ओमान के बीच कांप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) पर हस्ताक्षर किए गए। मोदी ने इस कारोबारी समझौते को दोनों देशों के साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। आशा है कि भारत-ओमान मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होती रहेगी।

पीएम मोदी व सुल्तान हैथम के बीच बैठक में मैरीटाइम सहयोग के लिए एक दृष्टिपत्र पर भी सहमति बनी है। यह प्रपत्र दोनों देशों की समुद्री पड़ोसी के रूप में सदियों पुरानी साझेदारी को मजबूत करते हुए क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनामी और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग की प्रतिबद्धता को बताता है। इस समझौते के जरिए ओमान के पास स्थिति होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भारत अपने हितों की सुरक्षा करना चाहता है। इस स्ट्रेट से विश्व का 20-30 प्रतिशत तेल व्यापार गुजरता है। भारत आने वाले कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा यहां से आता है। भारत को पहले से ओमान के दुक्म पोर्ट में सैन्य और लाजिस्टिक उपयोग की सुविधा मिली हुई है। नया समझौता इस सहयोग को और गहरा करेगा। यह भारतीय नौसेना को पश्चिमी हिंद महासागर में मजबूत आधार प्रदान करता है। दुक्म पोर्ट भारत के लिए एक वैकल्पिक रणनीतिक ठिकाना है। यह चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' रणनीति (जिसमें पाक के ग्वादर पोर्ट आदि शामिल हैं) का मुकाबला करने में मदद करता है। ओमान गल्फ क्षेत्र का एकमात्र देश है जहां भारतीय सेना की तीनों शाखाएं नियमित संयुक्त अभ्यास करती हैं।

मस्कट में गुरुवार को पीएम नरेन्द्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सौंपते पीएम सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद। आइएएनएस

ओमान ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान

प्रथम पृष्ठ से आगे

ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द फर्स्ट क्लास आफ द आर्डर आफ ओमान' प्रदान किया। यह सम्मान मोदी को भारत-ओमान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। इस सम्मान के साथ पीएम मोदी विरले वैश्विक नेता बन गए हैं जिन्हें 29 राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ओमान का ये सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी से पहले नेल्सन मंडेला, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जापान के सम्राट अकिहितो और जार्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय जैसे वैश्विक नेताओं को प्रदान किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पीएम मोदी की वैश्विक नेतृत्व क्षमता और राजनेता के रूप में स्वीकार्यता का बड़ा प्रमाण बताया है। तीन देशों की इस चार दिवसीय यात्रा के दौरान मोदी को इथियोपिया सरकार ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान' ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से नवाजा था।

पिछले 11 सालों में भारत ने अपना आर्थिक डीएनए बदल दिया : मोदी: एएनआइ के अनुसार, मोदी ने भारत-ओमान बिजनेस समिट को भी संबोधित किया। उन्होंने पिछले 11 सालों में भारत द्वारा शुरू किए गए कई सुधारों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने इसे दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी बाजारों में से एक बना दिया है। मोदी ने कहा- "पिछले 11 सालों में भारत ने न सिर्फ नीतियां बदली हैं, बल्कि अपना आर्थिक डीएनए भी बदल दिया है।" उन्होंने इंसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और जीएसटी जैसी कई पहलों को जिक्र करते हुए कहा कि इनसे विकास की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। उन्होंने ओमानी कंपनियों को भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने का न्योता दिया।

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के बाद स्वदेश रवाना: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की यात्रा के बाद गुरुवार को ओमान से स्वदेश रवाना हुए। मोदी को ओमान के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मामलों के मंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने 'नमस्ते' करते हुए विदाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यात्रा को दिलों को छूने वाली व संबंधों को मजबूत करने वाली बताया। उन्होंने लिखा कि चर्चाओं व समझौतों के बाद मोदी जार्डन, इथियोपिया व ओमान की यात्रा के बाद भारत प्रस्थान कर रहे हैं।"

प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे खुले, आइटी व हेल्थ सर्विस निर्यात में भी होगी बढ़ोतरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ओमान के साथ कंप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) पर अमल होते ही इंजीनियरिंग, मेडिकल, आइटी, शिक्षा व निर्माण से जुड़े भारतीय प्रोफेशनल्स अब ओमान में आसानी से अपनी सेवा दे सकेंगे। अब अनुबंध सेवा के तहत वे चार साल तक ओमान में रह सकेंगे। वैसे कोई भी प्रोफेशनल्स 180 दिनों तक ओमान में रहकर स्वतंत्र रूप से सेवा दे सकेगा। बिजनेस के नाम पर भी ओमान भारतीय को 90 दिनों का वीजा देगा। ओमान में चलने वाली भारतीय कंपनियों में अब 50 प्रतिशत तक भारतीय काम कर सकेंगे। पहले यह सीमा 20 प्रतिशत थी। सीपा होने से आइटी, हेल्थ, शिक्षा, अनुसंधान, आडियो-वीडियो व टूरिज्म जैसे सर्विस सेक्टर के निर्यात में इजाफा होगा। सर्विस सेक्टर में ओमान सालाना 12.52 अरब डालर का आयात करता है, इनमें भारत की हिस्सेदारी 5.31 प्रतिशत है।

मध्य पूर्व व अफ्रीकी देशों में निर्यात बढ़ाने का मिलेगा मौका: फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष एससी रल्हन ने बताया कि गल्फ को-आपरेशन काउंसिल (जीसीसी) का सदस्य देश होने व अफ्रीका के पास होने से मध्य पूर्व व अफ्रीका में भारत को अपना निर्यात बढ़ाने में मौका मिलेगा। भारतीय निर्यातक ओमान में अपना केंद्र खोलकर वैल्यू एडीशन करके वहां से मध्य पूर्व व अफ्रीकी देशों में निर्यात कर सकेंगे।

निर्यात की भरपाई में भी मिलेगी मदद: ओमान के साथ सीपा होने से अमेरिकी शुल्क से प्रभावित होने वाले निर्यात की भरपाई में मदद मिलेगी। अमेरिका की तरफ से 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के बाद टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद, लेदर, जेम्स व ज्वैलरी जैसे आइटम के निर्यात की बढ़ोतरी दर प्रभावित हुई है। ओमान इन वस्तुओं का बड़ा आयातक देश है।

भारत व ओमान के संबंधों के लिए सीपा ऐतिहासिक कदम है जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले दशकों में दिखेंगे। सीपा से व्यापार, निवेश एवं नए अवसर मिलेंगे व युवाओं को लाभ मिलेगा।
- नरेन्द्र मोदी, पीएम।

ओमान के साथ सीपा से भारतीय निर्यातक व प्रोफेशनल्स को ओमान के बाजार में अवसर मिलेंगे। सीपा के तहत राष्ट्र हित का ध्यान रखा गया है, वहीं, इससे सरकार की प्रतिबद्धता के मुताबिक भारतीय किसान, कारीगर, एमएसएमई लाभान्वित होंगे। **- पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री**

चीन की चुनौतियों के बीच भारत की अफ्रीका नीति में नई ऊर्जा

जयप्रकाश रंजन • जागरण

- सालभर में इथियोपिया समेत छह अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी
- पांच वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार

नई दिल्ली: कई अफ्रीकी देशों में जब चीन के आक्रामक निवेश रवैये और बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर गहरी चिंताएं और संशय व्याप्त है तब भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप के साथ संपर्क और साझेदारी की प्रक्रिया को अभूतपूर्व गति प्रदान की है।

नवंबर, 2024 के बाद से अभी तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं छह अफ्रीकी देशों (नाइजीरिया, मारीशस, घाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया) की यात्रा कर चुके हैं। भारत ने अफ्रीकी देशों को विकास सहायता, अनुदान और रियायती दरों पर कर्ज के रूप में करीब 13 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक की राशि बतौर मदद देने की घोषणा की है या उसका वितरण किया है। पिछले तीन वर्षों में भारत ने अफ्रीका के एक दर्जन देशों से शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इकोनमी, कनेक्टिविटी और सैन्य क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने का समझौता किया है। जानकार मान रहे हैं कि पीएम मोदी के स्तर पर लगातार हो रहे दौरों ने पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के साथ संबंधों को एक नई ऊर्जा दी है।

भारत की इस आक्रामक कूटनीतिक का असर भी दिख रहा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार पिछले पांच वर्षों में लगभग दोगुना होकर 2024-25 में 100 अरब डालर से अधिक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025 में यह व्यापार 103 अरब डालर तक पहुंच गया, जिसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यह किसी भी महादेश के साथ भारत के होने वाले द्विपक्षीय कारोबार में सबसे तेज वृद्धि है। भारत सरकार की मंशा इस कारोबार को वर्ष 2030 तक बढ़ कर 150 अरब डालर करने की है।

भारतीय कंपनियों का अफ्रीका में कुल निवेश 75 अरब डालर से अधिक हो चुका है और अब भारत अफ्रीका के शीर्ष पांच निवेशकों में शामिल हो गया है। अफ्रीका के कई देशों में भारत की तरफ से किया जाने वाला निवेश व आर्थिक मदद चीन के निवेश से ज्यादा हो चुके हैं।

बुधवार को इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने कहा -'भारत इथियोपिया में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) करने वाला देश है और वहां 615 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं।' सबसे ज्यादा निवेश करने के बावजूद चीन के किसी विश्वविद्यालय ने वहां कोई अपनी पूर्ण शाखा नहीं खोली है जबकि भारत की प्रतिष्ठित आइआइटी ने तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोल दिया है। वर्ष 2023 में भारत केन्या का सबसे बड़ा एशियाई साझेदार देश बना, जो वहां चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। मारीशस भी एक ऐसा देश है जो आर्थिक साझेदारी में भारत को वरीयता देता है।

ये कह चुके हैं मोदी

'भारत अफ्रीका में प्रतिस्पर्धा करने नहीं, बल्कि साथ मिलकर निर्माण करने आया है।'
- नामीबियाई संसद में (जुलाई, 2025)

'अफ्रीका भारत की विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेगा।'
- युगांडा की संसद में (जुलाई, 2018)

भारत का उन अफ्रीकी देशों पर फोकस जहां संसदीय व्यवस्था

भारत ने चीन की आर्थिक प्रतिस्पर्धा को एक तरफ रखकर नई रणनीति बनाई है। इसमें अफ्रीका में उन देशों पर फोकस किया गया है जहां लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत हो रही है। पीएम मोदी ने उन्हीं अफ्रीकी देशों की यात्रा की है जहां संसदीय व्यवस्था है। कूटनीतिकारों का मानना है कि चीन की नीतियों से अफ्रीकी देशों में असंतोष है, उसे देखते हुए भारत की साफ्ट पावर (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व आइटी) में कारगर साबित होगी।

आस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर शूटर को पकड़ने में भारतवंशी ने की थी मदद

- अमनदीप सिंह ने कहा, वह हमलावर को मार गिराना चाहते थे
- रविवार को यहूदियों पर हुए हमले में 15 लोगों की गई थी जान

मेलबर्न, प्रेट्र: आस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर रविवार को हनुक्का उत्सव मनाने के दौरान यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ था। दो शूटरों में से एक को पकड़ने में मदद करने वाले भारतीय मूल के 34 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि वह एक हमलावर को मार गिराना चाहते थे और जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते थे।

बीते रविवार को पिता-पुत्र साजिद अकरम और नवीद अकरम ने बोंडी बीच पर यहूदियों पर हमला किया था। इसमें 15 लोगों की मौत हुई थी और 40 लोग घायल हुए, जिनमें भारतीय छात्र भी हैं। सिडनी निवासी 50 वर्षीय साजिद को मार गिराया गया था, जबकि आस्ट्रेलिया में जन्मा उसका 24 वर्षीय बेटा नवीद घायल हो गया। दोनों हमलावर इस्लामिक स्टेट (आइसिस) से प्रेरित थे। उन्होंने नवंबर में फिलीपींस की यात्रा भी की थी। साजिद ने भारत के पासपोर्ट पर और नवीद ने आस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर यह यात्रा की थी। एसबीएस न्यूज के अनुसार, भारतीय और न्यूजीलैंड मूल के माता-पिता के बेटे अमनदीप सिंह बोला ने साजिद को काबू करने में मदद की थी। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की मदद से उसे काबू किया था। उन्होंने कहा, 'मैं (शूटर पर) कूद पड़ा और उसके हाथ पकड़ लिए। पुलिस अधिकारी की मदद की और कहा कि उसे छोड़ना नहीं।' घटना के समय वह कबाब खा रहे थे। शुरू में गोलीबारी की आवाज को पटाखे की आवाज समझा था।

अमनदीप सिंह बोला। फाइल

नफरती भाषण से निपटने को नया कानून बनाएगा आस्ट्रेलिया: रायटर के अनुसार, यहूदियों पर हमले के बाद आस्ट्रेलियाई सरकार नफरती भाषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार को नफरती भाषण से निपटने के लिए नया कानून बनाने का वादा किया। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसा कानून बनाने का प्रयास करेगी, जिससे नफरती भाषण और हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ आरोप लगाना आसान हो जाएगा। ऐसे मामले में दंड बढ़ाने के साथ ही वीजा रद करना या अस्वीकार करना आसान किया जाएगा। उन संगठनों को निशाना बनाने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके नेता नफरती भाषण में लिप्त रहते हैं।

न्यूज गैलरी

वाशिंगटन में हेलीकाप्टर-विमान टक्कर में हुई लापरवाही

वाशिंगटन: सरकार ने बुधवार को स्वीकार किया कि जनवरी में राजधानी के पास एक विमान और ब्लैक हाक हेलीकाप्टर के बीच हुई टक्कर में संघीय विमानन प्रशासन और सेना की भूमिका थी। इसमें 67 लोग मारे गए थे। पीड़ितों के एक परिवार द्वारा दायर पहले मुकदमे के आधिकारिक जवाब में कहा गया है कि सरकार इस दुर्घटना के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि उस रात हवाई यातायात नियंत्रक ने नियमों का उल्लंघन किया था। (एपी)

रूस ने कर्ज चुकाने को मास्को टावर्स बेचने का दिया आदेश

मास्को: रूसी सरकार ने रेलवे को मध्य मास्को में स्थित 2.4 अरब डालर की 62 मंजिला गगनचुंबी इमारत बेचने का आदेश दिया है, ताकि रेलवे को 50 अरब डालर के कर्ज चुकाने में मदद मिल सके। सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे राजस्व में गिरावट का सामना कर रही है, जबकि दो दशकों में उच्चतम ब्याज दरों के कारण ऋण लागत में भारी वृद्धि हुई है। (रायटर)

बलूचिस्तान में निवेश पर चीन और पश्चिमी देशों को चेतावनी

बलूचिस्तान: पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे बागी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) के नेता अल्लाह नजर बलूच ने चीन, पश्चिमी देशों और पश्चिम एशिया के देशों को बलूचिस्तान में निवेश करने से रोकते हुए चेतावनी दी है। कहा कि नोककुंडी घटना को "स्पष्ट राष्ट्रीय संदेश" के रूप में देखा जाना चाहिए चूंकि पाकिस्तान के "जबरदस्ती के कब्जे" के तहत चलने वाले विदेशी प्रयासों को सहन नहीं किया जाएगा। (एएनआइ)

ओली तीसरी बार चुने गए सीपीएन-यूएमएल अध्यक्ष

काठमांडू: नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गुरुवार को सीपीएन-यूएमएल के फिर अध्यक्ष चुन लिए गए। वह लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए। गत सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन के चलते ओली सरकार का पतन हो गया था। तीन महीने बाद महाधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया। (प्रेट्र)

भारत को एआइ व आपूर्ति शृंखला के लिए रणनीतिक साझेदार मानता है अमेरिका

- अमेरिकी अधिकारी ने राजनीतिक तनाव के कारण भारत के वाशिंगटन में हुए पैक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने की बात को किया खारिज
- अमेरिकी आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा, वे फरवरी में होने वाले भारत एआइ इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका आर्टिफिशिय इंटेलिजेंस (एआइ) और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने के प्रयासों में भारत को महत्वपूर्ण संभावित भागीदार मानता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने यह बात कही है, साथ ही उन्होंने उन बातों को खारिज कर दिया है कि राजनीतिक तनाव के कारण भारत ने हाल ही में वाशिंगटन में हुए शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया।

अमेरिकी आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने घोषणा की कि वे फरवरी में होने वाले भारत एआइ इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वाशिंगटन में बुधवार को आयोजित पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में पत्रकारों से बात करते हुए हेलबर्ग ने इस सम्मेलन में भारत की अनुपस्थिति से संबंधित सवालों के जवाब दिए। इस सम्मेलन में तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने एआइ अवसंरचना और सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखलाओं पर रणनीति समन्वय स्थापित करने के लिए भाग लिया था। हेलबर्ग ने कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि व्यापार समझौतों से संबंधित अमेरिका और भारत के बीच की बातचीत आपूर्ति शृंखला सुरक्षा पर हमारी चर्चाओं से पूरी तरह से अलग और समानांतर है। हम इन दोनों को एक नहीं मान रहे हैं।" उन्होंने जोर दिया कि राजनयिक मतभेदों के कारण भारत को शिखर सम्मेलन से बाहर नहीं रखा गया है, बल्कि वर्तमान में वह बहुपक्षीय ढांचे के बजाय द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

ताइवान को 11 अरब डालर के हथियारों की बिक्री करेगा अमेरिका, चीन बौखलाया

- यह ताइवान के लिए अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार पैकेज
- चीन की चेतावनी, ताइवान की मदद कर अमेरिका मुसीबत मोल ले रहा

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका ने बुधवार को ताइवान को 11.1 अरब डालर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है। यह ताइवान के लिए अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार पैकेज है। यह घोषणा ताइवान के विदेश मंत्री लिन चिया-लंग की पिछले सप्ताह वाशिंगटन की अघोषित यात्रा के बाद हुई है, जहां उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की थी। ताइवान सरकार बीजिंग के संप्रभुता के दावों को खारिज करती है। इस मंजूरी के बाद चीन बौखला गया है। विदेश मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जताई है। मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि हथियारों से 'ताइवान की स्वतंत्रता' में सहायता करके अमेरिका अपने ऊपर ही मुसीबत मोल ले रहा। चीन को रोकने के लिए ताइवान का इस्तेमाल पूरी तरह से विफल होगा।

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित हथियार बिक्री में आठ वस्तुएं शामिल हैं। इनमें हिमर्स राकेट सिस्टम, हावित्जर, जैवलिन टैंक-रोधी मिसाइलें, अल्टियस लोइटरिंग मुनिशन ड्रोन और अन्य उपकरणों के पुर्जे शामिल हैं। पेंटागन ने हथियारों के सौदे के विवरण की घोषणा करते हुए कहा कि हथियारों की बिक्री ताइवान के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और विश्वसनीय रक्षात्मक क्षमता बनाए रखने के निरंतर प्रयासों का समर्थन करके अमेरिकी राष्ट्रीय, आर्थिक और सुरक्षा हितों की पूर्ति करती है।

यूएस-ताइवान बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष रूपर्ट हैमंड-चैम्बर्स ने कहा कि हिमर्स जैसे हथियार, जिनका यूक्रेन ने रूसी सेनाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, चीन की आक्रमणकारी सेना को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वाशिंगटन के बीजिंग के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध हैं, लेकिन ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध बनाए रखता है और द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपूर्तिकर्ता है।

लिन चिया-लंग। फाइल

देश-दुनिया की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

थाईलैंड ने कंबोडिया पर और किए हवाई हमले

नोम पेन्ह, एपी : कंबोडिया पर उसके पड़ोसी देश थाईलैंड ने गुरुवार को और हवाई हमले किए हैं। थाईलैंड के युद्धक विमानों ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां कंबोडियाई सेना ने अपने राकेटों को संग्रहित किया था। पिछले हफ्ते शुरू हुए इस सैन्य संघर्ष में इन राकेटों से ही कंबोडिया ने कहर ढाया था। थाईलैंड की सेना ने जेट फाइटरों ने एक गोदाम पर हमला किया, जहां कंबोडियाई सेना ने उन राकेटों को जमा कर रखा था। दोनों देशों के बीच सीमा पर उन क्षेत्रों को लेकर संघर्ष चल रहा है, जिनका दोनों ही दावा करते हैं। सीमावर्ती कई विवादित क्षेत्रों में सदियों प्राचीन शिव मंदिर समेत कई पुराने मंदिरों के अवशेष हैं, जो लड़ाई के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। थाईलैंड का कहना है कि कंबोडियाई बलों ने इन्हें अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया है। लड़ाई का दौर आठ दिसंबर को शुरू हुआ, जब एक सीमा संघर्ष में दो थाई सैनिक घायल हो गए। तब से कई मोर्चों पर लड़ाई छिड़ गई है।

बीजिंग में लौट आई धुंध, एक्यूआइ अत्यंत खराब स्तर पर पहुंचा

बीजिंग, प्रेट्र : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट के मद्देनजर चीन द्वारा प्रदूषण से निपटने के प्रयासों पर खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में चीनी सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों पर प्रकाश भी डाला।

इस बीच, धुंध (स्माग) ने गुरुवार को बीजिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) बढ़कर 215 के "अत्यंत खराब" स्तर पर पहुंच गया। प्रदूषण से लड़ने के लिए वर्षों से किए जा रहे प्रयासों के बाद राजधानी में प्रदूषण में यह एक अप्रत्याशित उछाल है। चीन की राष्ट्रीय वेधशाला ने देश के कुछ हिस्सों में भारी कोहरे के लिए यलो चेतावनी जारी की। इसमें कहा गया कि हेबेई, बीजिंग, तियानजिन, हेनान, अनहुई, जियांग्सू, हुबेई, सिचुआन बेसिन और चोंगकिंग के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की आशंका है। बीजिंग में इन दिनों प्रदूषण से भरी धुंध अप्रत्याशित है।

चिनाब के प्रवाह में 'बदलावों' पर पाक ने भारत से मांगा स्पष्टीकरण

- सिंधु जल संधि में निहित प्रक्रियाओं के अनुसार मामलों पर स्पष्टीकरण मांगने को लिखा पत्र
- चिनाब के प्रवाह में किसी भी प्रकार के एकतरफा बदलाव से परहेज करने का किया आह्वान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने गुरुवार को चिनाब नदी के प्रवाह में कथित बदलावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उसने इस बाबत स्पष्टीकरण मांगने के लिए भारत को पत्र लिखा है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, "हमारे सिंधु जल आयुक्त ने सिंधु जल संधि में निहित प्रक्रियाओं के अनुसार मामलों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए भारतीय समकक्ष को एक पत्र लिखा है।"

साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, "हम भारत से आह्वान करते हैं कि वह पाकिस्तानी सिंधु जल आयुक्त द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे, नदी के प्रवाह में किसी भी प्रकार के एकतरफा बदलाव से परहेज करे और सिंधु जल संधि के प्रविधानों के तहत अपने दायित्वों को अक्षरशः पूरा करे।" गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए। इनमें 1960 की सिंधु जल संधि को "स्थगित" करना भी शामिल था। विश्व बैंक की मध्यस्थता से संपन्न सिंधु जल संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के वितरण और उपयोग को नियंत्रित करती रही है।

बहरहाल, अंद्राबी ने कहा कि नदी के प्रवाह में छेड़छाड़, हमारे कृषि चक्र के महत्वपूर्ण समय में, नागरिकों के जीवन और आजीविका के साथ-साथ खाद्य और आर्थिक सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।" उन्होंने पाकिस्तान के इस रुख को दोहराया कि सिंधु जल समझौता एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का साधन रहा है।

अंतरराष्ट्रीय जल सीमा उल्लंघन में 35 बांग्लादेशी मछुआरे हिरासत में

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय जल सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में दो ट्रालरों (जहाजों) सहित उसपर सवार 35 बांग्लादेशी मछुआरों को हिरासत में लिया है। मछली पकड़ने वाले दोनों बांग्लादेशी जहाजों को भी जब्त कर लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि 16 दिसंबर को समुद्र में गश्त के दौरान तटरक्षक बल ने दो बांग्लादेशी जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा। दोनों जहाजों को दक्षिण 24 परगना के फ्रेजरगंज लाया गया। जहां भारतीय तटरक्षक बल ने जब्त जहाजों व गिरफ्तार मछुआरों को फ्रेजरगंज तटीय पुलिस थाने को सौंप दिया। गिरफ्तार सभी लोग बांग्लादेश के निवासी बताए जा रहे है। कार्रवाई के बाद घटनास्थल के आसपास के तटीय क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

अमेरिका ने ड्रग्स तस्करी से जुड़ी बोट उड़ाई, चार की मौत

वाशिंगटन, एपी : अमेरिकी सेना ने बुधवार को कहा कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स तस्करी में शामिल एक बोट पर हमला किया, जिसमें चार लोग मारे गए। यह घटना उसी दिन हुई जब अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ सैन्य बल प्रयोग करने की शक्ति को सीमित करने के प्रयासों को खारिज कर दिया।

अमेरिकी दक्षिणी कमान ने कहा कि यह नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आतंकियों द्वारा एक तस्करी मार्ग पर संचालित किया जा रहा था। सेना ने बोट को निशाना बनाने से पहले का वीडियो पोस्ट किया है। इस हमले के साथ अब तक बोट को निशाना बनाए जाने की संख्या 26 हो गई है। इसमें 99 लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने इन हमलों को अमेरिका में ड्रग्स के प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक कदम बताया है और दावा किया है कि अमेरिका ड्रग्स कार्टेल के साथ सशस्त्र संघर्ष में लगा हुआ है।

वेनेजुएला अमेरिकी कंपनियों से जब्त संपत्तियां लौटाए : ट्रंप

वाशिंगटन, एपी: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मांग की कि वेनेजुएला उन संपत्तियों को लौटाए, जिन्हें उसने वर्षों पहले अमेरिकी तेल कंपनियों से जब्त किया था। इसके साथ ही उन्होंने वेनेजुएला आने-जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों के खिलाफ नाकाबंदी की अपनी घोषणा को उचित ठहराया। ट्रंप ने निकोलस मादुरो के खिलाफ नवीनतम रणनीति के बारे में पूछे जाने पर वेनेजुएला में हुए अमेरिकी निवेशों के नुकसान का हवाला दिया। उन्होंने संकेत दिया कि कराकस में नेताओं का सामना करने के लिए उनके प्रशासन के कदम आंशिक रूप से तेल निवेशों पर विवादों और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों से प्रेरित हैं। कुछ प्रतिबंधित टैंकर पहले ही वेनेजुएला से रास्ता बदल रहे हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, जिसे अंदर नहीं आना चाहिए।

****

दैनिक जागरण

टी-20 VS SA CRICKET

अफ्रीकी चुनौती

शुक्रवार 19 दिसंबर, 2025 www.jagran.com

अहमदाबाद में जीत लो सीरीज

भारत-द. अफ्रीका के बीच पांचवां टी-20 मैच आज | सूर्य की फार्म चिंता का विषय

सूर्यकुमार यादव ● प्रेट्र

अहमदाबाद, प्रेट्र: लखनऊ में घने कोहरे के कारण मैच रद होने के बाद अब भारतीय टीम अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध शुक्रवार को होने वाले पांचवें व अंतिम टी-20 मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने उतरेगी। वहीं मेहमान टीम के पास भी अब सीरीज को बराबर कराने का मौका होगा। चयन को लेकर उठे सवालों और कुछ कमजोरियों के उजागर होने के बीच भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का सकारात्मक अंत करने की कोशिश करेगी।

टेस्ट सीरीज 0-2 से हारने के बाद भारत ने शानदार वापसी करते हुए वनडे सीरीज जीती। यह सुनिश्चित है कि भारत अब इस सीरीज को हार नहीं सकता है जो मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए राहत की बात होनी चाहिए क्योंकि टीम के दो प्रमुख खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव तथा टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। कुछ समय पहले तक विश्व के नंबर एक खिलाड़ी रहे सूर्यकुमार की फार्म भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने टी-20 में इस साल 20 मैचों में 18 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं बनाया। इस दौरान उन्होंने 14.20 के औसत से 213 रन बनाए। गिल का छोटे प्रारूप में नहीं चल पाना भी भारत के लिए अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले चिंता का विषय होगा। वह पिछले मैच में अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए थे जिससे उनका अंतिम मैच में खेलना संदिग्ध है। भारतीय टीम किसी तरह का जोखिम लेना उचित नहीं समझेगी क्योंकि उसके पास शीर्ष क्रम में संजू सैमसन के रूप में एक अच्छा विकल्प मौजूद है।

सैमसन निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए कभी भी सही विकल्प नहीं थे। उन्होंने आरंभिक बल्लेबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है जबकि मध्यक्रम में वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अपने तीनों टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक शीर्ष क्रम पर खेलते हुए बनाए हैं। अंतिम मैच में गिल की अनुपलब्धता की स्थिति में मौका मिलने पर केरल का यह विकेटकीपर बल्लेबाज इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा भारतीय टीम संतुलित नजर आती है क्योंकि दोनों आलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे अब तक खेले गए तीनों मैचों में अंतिम एकादश में शामिल रहे हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण में अर्शदीप सिंह अपनी लय में आ रहे हैं जबकि हर्षित राणा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बीच निजी कारणों से तीसरे टी-20 में नहीं खेल पाने वाले जसप्रीत बुमराह चौथे मैच से पहले टीम से जुड़ गए हैं। यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है जो इस सीरीज में भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के लिए चुनौती पेश करेगी।

जहां तक दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न है तो उसके बल्लेबाजों का प्रदर्शन उतार चढ़ाव वाला रहा है। अगर उसे सीरीज बराबर करनी है तो उसके बल्लेबाजों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम रीजा हेंड्रिक्स की जगह एडेन मार्करैम को शीर्ष क्रम में वापस लाने पर विचार कर सकती है। रीजा हेंड्रिक्स इस दौरे पर अपनी लय हासिल नहीं कर पाए हैं। दक्षिण अफ्रीका को इसके अलावा युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी जो अभी तक अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं।

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, शाहबाज अहमद, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकाक, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कार्बिन बाश, फरेरो, जेनसेन, जार्ज लिंडे, बार्टमैन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे, लूथो सिपामला।

कल हो सकती है टीम की घोषणा

नई दिल्ली: मुंबई में शनिवार को न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे और टी-20 टीम चुनने के लिए चयनकर्ताओं की बैठक हो सकती है। इसके साथ ही फरवरी में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा भी जा सकती है। टी-20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड से पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेली, जिसका पहला मैच नागपुर में 21 जनवरी को खेला जाएगा। ये सीरीज 31 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद भारतीय टीम सात फरवरी को यूएसए के विरुद्ध अपने टी-20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी।

लाथम-कान्वे की रिकार्ड साझेदारी से न्यूजीलैंड मजबूत

शतक के बाद जश्न मनाते टाम लाथम (बाएं), साथ में हैं डेवोन कान्वे ● एएफपी

माउंट माउंगानुई, एपी: कप्तान टाम लाथम और डेवोन कान्वे के बीच पहले विकेट के लिए रिकार्ड साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन गुरुवार को पहले विकेट पर 334 रन बना लिए। स्टंप्स से तीन ओवर पहले लाथम 137 रन बनाकर आउट हो गए।

दिन के अंत तक कान्वे 178 रन, जबकि नाइट वाचमैन जैकब डफी नौ रन बनाकर खेल रहे थे। लाथम और कान्वे ने पहले विकेट के लिए 323 रन जोड़े, जो न्यूजीलैंड की तरफ से पहले विकेट के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। यह 2025 में किसी भी टीम की तरफ से किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। लाथम ने 245 गेंदों का सामना किया और 15 चौके व एक छक्का लगाया। जबकि कान्वे ने 279 गेंदों का सामना किया और 25 चौके लगाए। न्यूजीलैंड के लिए आखिरी बार दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने 2019 में टेस्ट मैच में शतक बनाए थे। न्यूजीलैंड इस सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरा टेस्ट विंडीज ने ड्रा कराया था।

तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने 213 रन पर गंवाए आठ विकेट, संघर्ष जारी

नाथन लियोन ने मैक्ग्रा को पछाड़ा

टेस्ट क्रिकेट में 564 विकेट के साथ आस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बने लियोन, अब केवल शेन वार्न (708) उनसे आगे

तीसरा एशेज टेस्ट

एडिलेड, एपी: आस्ट्रेलिया के अनुभवी आफ स्पिनर नाथन लियोन ने तीसरे एशेज टेस्ट में दो विकेट लेकर महान ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ते हुए आस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बन गए। ओली पोप (3) और बेन डकेट (29) के विकेट के साथ नाथन लियोन ने मैक्ग्रा के 563 विकेटों की बराबरी की और फिर आगे निकल गए। अब उनसे ऊपर केवल शेन वार्न (708 विकेट) हैं। नाथन लियोन का यह प्रदर्शन खास रहा क्योंकि पर्थ टेस्ट में उन्हें सिर्फ दो ओवर फेंके थे और ब्रिस्बेन टेस्ट में उन्हें एकादश से बाहर रखा गया था।

वहीं चोट से उबरकर लौटे कप्तान पैट कमिंस ने भी सीरीज में अपने पहले विकेट चटकाए। घातक और अनुशासित गेंदबाजी के दम पर आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को लगातार दबाव में रखा। दूसरे दिन आस्ट्रेलिया ने आठ विकेट पर 362 रन से आगे खेलना शुरू किया और 371 रन पर सिमट गई। मिशेल स्टार्क ने अर्धशतक जमाया, जबकि जोफ्रा आर्चर ने निचले क्रम को समेटते हुए पांच विकेट लिए। यह टेस्ट करियर में उनका चौथा पांच विकेट हाल था।

जवाब में इंग्लैंड दिन का खेल समाप्त होने तक आठ विकेट पर 213 रन तक पहुंच गई और अभी 158 रन पीछे है। इंग्लैंड की शुरुआत ठीकठाक रही और पैट कमिंस के वार के बाद पतन शुरू हो गया। इसके बाद लियोन ने अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर 15 गेंदों में तीन झटके दिलाए और इंग्लैंड लड़खड़ा गया। कमिंस ने तीन और स्काट बोलैंड ने दो विकेट लिए। एडिलेड ओवल की पारंपरिक बल्लेबाजी अनुकूल परिस्थितियों और 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन लेंथ बनाए रखी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पर दबाव सबसे ज्यादा दिखा।

वह लगभग चार घंटे क्रीज पर टिके रहे, हेलमेट और शरीर पर गेंदें लगीं, ऐंठन से जूझते दिखे और डीआरएस के कुछ विवादास्पद निर्णयों से भी उनका मूड बिगड़ा। फिर भी स्टोक्स 151 गेंदों में नाबाद 45 रन बनाकर डटे रहे और नंबर 10 आर्चर (30) के साथ 45 रन की अटूट साझेदारी कर इंग्लैंड की पारी को अगले दिन तक खींच ले गए।

कैमरन ग्रीन ने तीसरी ही गेंद पर हैरी ब्रूक (45) को आउट कर 56 रन की साझेदारी तोड़ी। डीआरएस पर फिर बहस हुई, जब जैमी स्मिथ के कैच को नाटआउट दिया गया, तो दूसरी ओर कमिंस की गेंद पर हल्का किनारा मानते हुए स्मिथ को आउट करार दिया गया।

टेस्ट में सर्वाधिक विकेट

विकेट	गेंदबाज	देश
800	मुरलीधरन	श्रीलंका
708	शेन वार्न	आस्ट्रेलिया
704	जेम्स एंडरसन	इंग्लैंड
619	अनिल कुंबले	भारत
604	स्टुअर्ट ब्राड	इंग्लैंड
564*	नाथन लियोन	आस्ट्रेलिया
563	ग्लेन मैक्ग्रा	आस्ट्रेलिया

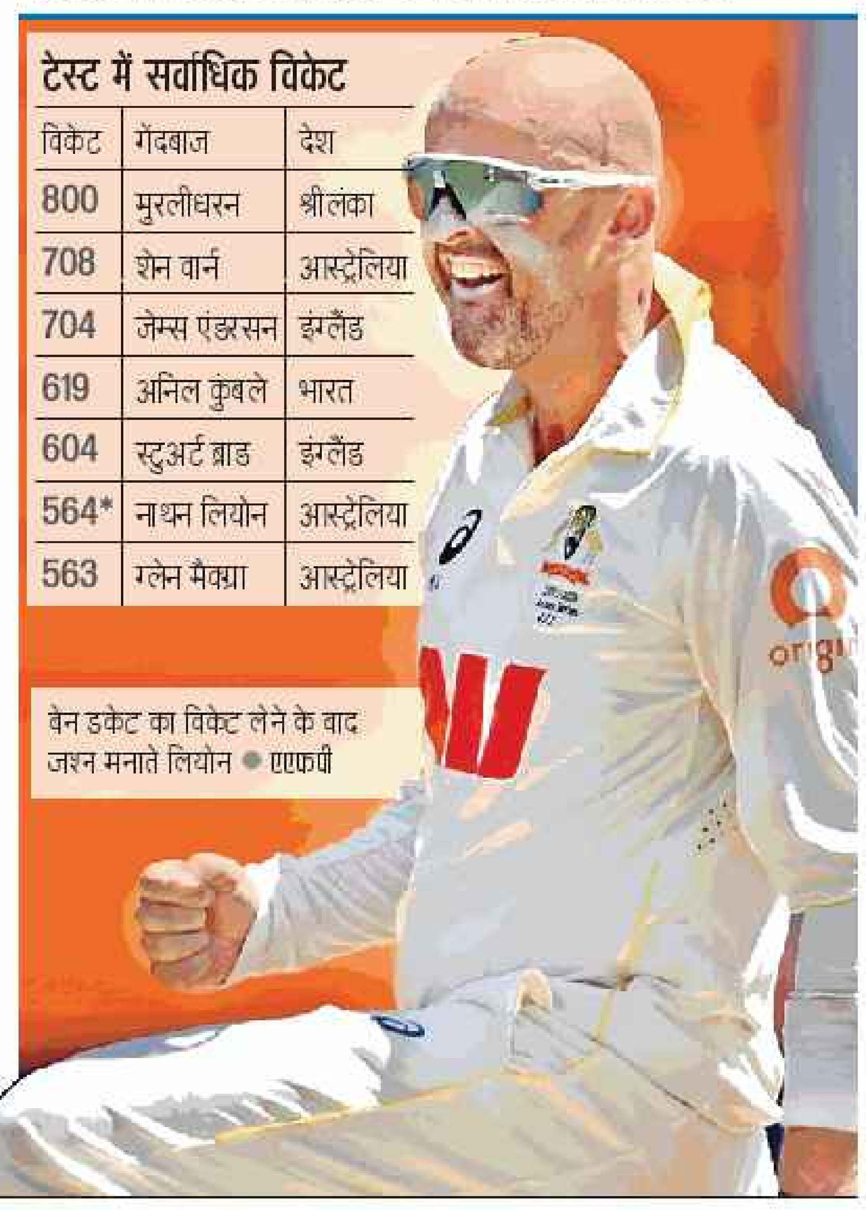

बेन डकेट का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते लियोन ● एएफपी

खेल डायरी

सात्विक-चिराग ने अल्फियान-फिक्री को हराया

हांगझोऊ, प्रेट्र: भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी गुरुवार को बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स में अपने ग्रुप बी के दूसरे मैच में इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मुहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराकर नाकआउट स्टेज के करीब पहुंच गए। पूर्व विश्व नंबर एक भारतीय जोड़ी ने अपने डिफेंस को मजबूत किया और मैच पर हावी रहते हुए विश्व नंबर आठ अल्फियान और फिक्री को एक घंटे तक चले पुरुष डबल्स मैच में 21-11, 16-21, 21-11 से हराया। दो मैचों में दो जीत के साथ, सात्विक और चिराग अब ग्रुप में सबसे आगे हैं अंकों के अंतर में काफी बढ़त बना ली है। तीसरी वरीयता प्राप्त सात्विक और चिराग शुक्रवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में दूसरी वरीयता प्राप्त आरोन चिया और सोह वूई यिक का सामना करेंगे। अपनी बेहतरीन फ्रंट-कोर्ट स्किल्स के लिए जानी जाने वाली जोड़ी का सामना करते हुए जिम्मेदारी चिराग पर थी, लेकिन उन्हें सात्विक का पूरा साथ मिला।

केतन ने मनु को हराकर जीता स्वर्ण पदक

नई दिल्ली, प्रेट्र: हरियाणा की केतन मलिक पेरिस ओलिंपिक में दो पदक जीतने वाली मनु भाकर जैसी दिग्गज को हराकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में राष्ट्रीय चैंपियन बन गईं। केतन ने 240 का स्कोर करके स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली की मीनू पाठक को रजत और सुरभि राव को कांस्य पदक मिला। जूनियर महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश की वंशिका चौधरी ने स्वर्ण, अंजलि शेखावत ने रजत और एशियाई खेल चैंपियन पलक गुलिया ने कांस्य पदक जीता। सेना निशानेबाजी ईकाई की लक्षिता बिश्नोई ने युवा वर्ग में खिताब जीता। रश्मिका सहगल को रजत मिला।

मेसी के साथ एक और सीजन खेलेंगे सुआरेज

फोर्ट लाडरडेल, एपी: इंटर मियामी में लियोन मेसी के साथ लुइस सुआरेज एक और सीजन खेलेंगे। उरुग्वे के स्ट्राइकर सुआरेज इस जनवरी में 39 साल के हो जाएंगे। उन्होंने मौजूदा एमएलएस चैंपियन इंटर मियामी के साथ 2026 सीजन खेलने के लिए करार किया किया है। इंटर मियामी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी, हालांकि इस समझौते की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया गया। यह इंटर मियामी के लिए सुआरेज का यह तीसरा सीजन होगा। सुआरेज ने अपने पिछले सीजन में सभी प्रतियोगिताओं में 50 मैचों में 17 गोल किए और 17 असिस्ट किए।

कोहरे के मौसम में उत्तर भारत में न कराएं मैच : शशि थरूर

राजीव शुक्ला व शशि थरूर ● एक्स

नई दिल्ली, प्रेट्र: लखनऊ में बुधवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी-20 मुकाबला घने कोहरे के चलते रद होने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि दिसंबर के मध्य से जनवरी के मध्य तक क्रिकेट मैच उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत में आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि इस दौरान उत्तर भारत में भारी कोहरा होता है। उन्होंने कहा कि मैच रद होने से क्रिकेट प्रेमियों को धोखा महसूस होता है।

थरूर गुरुवार सुबह संसद भवन में मीडिया से इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वहां से गुजर रहे बीसीसीआइ उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला को देखकर वह बोले 'आइए और इस समय दक्षिण भारत में खेलिए।'' इसके बाद उन्होंने राजीव शुक्ला से भी इस मामले पर हल्की-फुल्की बातचीत की। बुधवार को मैच से पहले ही इकाना स्टेडियम कोहरे की घनी चादर से ढक गया था। इससे बीसीसीआइ द्वारा सर्दियों के चरम मौसम में उत्तर भारत में मैच तय करने पर सवाल उठाए।

फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराया, इशान ने 49 गेंदों में खेली 101 रन की पारी

इशान के शतक से झारखंड पहली बार चैंपियन

सैयद मुश्ताक अली ट्राफी

इशान किशन ● एक्स

पुणे, प्रेट्र: भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने गुरुवार को ताबड़तोड़ शतक जड़ा, जिससे झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराकर पहला सैयद मुश्ताक अली ट्राफी का खिताब जीता। यह झारखंड का दूसरा घरेलू खिताब है। इससे पहले उसने 2010-2011 में विजय हजारे ट्राफी जीती थी।

फाइनल में किशन ने 49 गेंद में 10 छक्कों और छह चौकों से 101 रन बनाए जिससे झारखंड ने तीन विकेट पर 262 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। उन्होंने कुमार कुशाग्र (81) के साथ दूसरे विकेट के लिए 82 गेंद में 177 रन की साझेदारी भी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरे हरियाणा ने विकास सिंह (30 रन पर दो विकेट) के पारी के पहले ओवर में ही दो विकेट गंवा दिए जिससे टीम अंत तक नहीं उबर पाई और अंततः 18.3 ओवर में 193 रन पर सिमट गई। झारखंड की ओर से सुशांत मिश्रा ने 27 और बाल कृष्ण ने 38 रन देकर तीन-तीन विकेट चटकाए जबकि अनुकूल राय ने भी दो विकेट हासिल किए। हरियाणा की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज यशवर्धन दलाल ने सर्वाधिक 53 रन बनाए। सामंत जाखड़ (38) और निशांत सिंधू (31) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं। इस तरह झारखंड देश का प्रमुख टी-20 घरेलू टूर्नामेंट जीतने वाला 12वां राज्य बन गया।

किशन की तूफानी पारी : किशन ने अपनी पारी में 10 छक्के और छह चौके जड़ते हुए टूर्नामेंट में दूसरा शतक बनाया। यह 27 वर्षीय खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में शानदार फार्म में रहा और 10 पारियों में 197.32 के शानदार स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपना जलवा उस समय दिखाया है जब राष्ट्रीय चयनकर्ता जल्द ही न्यूजीलैंड के विरुद्ध सीरीज व टी-20 विश्व कप के लिए भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम चुनने के लिए बैठक करने वाले हैं। किशन ने हरियाणा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक हाथ से छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया।

डेंगू के कारण नहीं खेले युजवेंद्र चहल: हरियाणा के स्पिनर युजवेंद्र चहल डेंगू और चिकनगुनिया के कारण फाइनल में नहीं खेल पाए।

पहलवानों का राष्ट्रीय शिविर में भाग लेना जरूरी

विश्व कुश्ती महासंघ ने लागू की नई चयन नीति, व्यक्तिगत अभ्यास कर रहे पहलवानों को मिलेगी छूट

विनेश फोगाट

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय कुश्ती महासंघ ने नई चयन नीति लागू की है जिसके तहत राष्ट्रीय चयन के लिए राष्ट्रीय शिविरों में भागीदारी अनिवार्य है हालांकि व्यक्तिगत अभ्यास कर रहे पहलवानों को इससे छूट रहेगी। इसके साथ ही ओलिंपिक खेलों में कोटा जीतने वाले पहलवानों को एक दौर के अंतिम चयन ट्रायल में भाग लेना होगा। डब्ल्यूएफआइ की आम परिषद की हाल ही में अहमदाबाद में हुई बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। इसे फीडबैक और समीक्षा लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को भी दिया गया है। नीति में कहा गया है कि राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में भागीदारी सभी पहलवानों के लिए अनिवार्य होगी जिसमे एलीट और दिग्गज पहलवान शामिल हैं। शिविर में भाग लेने के लिए पहलवानों के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतना बहुत जरूरी है।

एक बार चुने जाने पर पहलवानों को राष्ट्रीय शिविर में अभ्यास करना होगा। किसी को दूसरे किसी स्थान पर व्यक्तिगत अभ्यास की अनुमति नहीं होगी। इसका अर्थ है कि हाल ही में संन्यास से वापसी का फैसला लेने वाली विनेश फोगाट को राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिये घरेलू स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। नीति में स्पष्ट है कि शिविर में भाग नहीं लेने पर पहलवान चयन ट्रायल में भाग नहीं ले सकेंगे। नीति में रिजर्व पहलवान रखने का भी प्रविधान है जो चयनित पहलवान के चोटिल होने पर खेल सकेंगे।

इसमे यह भी स्पष्ट किया गया है कि चयन ट्रायल में पिछला प्रदर्शन ध्यान नहीं रखा जाएगा। नीति में यह भी कहा गया है कि ओलिंपिक, एशियाई खेलों, उपमहाद्वीपीय चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल अनिवार्य होंगे।

निशानेबाज सम्राट का प्रदर्शन आइएसएसएफ के शीर्ष पांच में शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र: पिछले महीने काहिरा में विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पिस्टल निशानेबाज सम्राट राणा के प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आइएसएसएफ) ने वर्ष के शीर्ष पांच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शामिल किया है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले 20 वर्षीय निशानेबाज राणा ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। वह इस स्पर्धा में सीनियर वर्ग का व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने इसी प्रतियोगिता में ईशा सिंह के साथ मिक्स्ड टीम का रजत पदक भी जीता था।

भारत के लिए खेलने पर मुश्किल में पाकिस्तानी कबड्डी खिलाड़ी

उबैदुल्लाह राजपूत ● इंटरनेट मीडिया

कराची, प्रेट्र: पाकिस्तान के लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वह 16 दिसंबर को बहरीन में एक निजी टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए खेले थे। जीसीसी कप में भारतीय शर्ट पहने और भारतीय झंडा लहराते हुए उबैदुल्लाह के वीडियो और तस्वीरें प्रसारित होने के बाद वह बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं।

पाकिस्तान कबड्डी महासंघ (पीकेएफ) के सचिव राणा सरवर ने कहा कि पीकेएफ की एक आपात बैठक 27 दिसंबर को बुलाई गई है जिसमें इस मामले पर चर्चा की जाएगी और राजपूत तथा कुछ अन्य खिलाड़ियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

सरवर ने कहा यह एक निजी टूर्नामेंट था जिसमें आयोजकों द्वारा प्रतियोगिता में भारत, पाकिस्तान आदि नामों से निजी टीमें बनाई गई थीं लेकिन सभी टीमों में अपने-अपने देश के खिलाड़ी थे।

451 करोड़ रुपये फुटबाल विश्व कप विजेता को मिलेंगे

मैनचेस्टर, एपी: अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में होने वाले 2026 फुटबाल विश्व कप विजेता को रिकार्ड 50 मिलियन डालर (451 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिलेगी। विश्व कप की कुल इनामी राशि 655 मिलियन डालर (5912 करोड़ रुपये) है, यह 2022 में कतर में हुए फुटबाल विश्व कप की 440 मिलियन डालर से लगभग 49 प्रतिशत अधिक है। हालांकि यह इस साल क्लब विश्व कप जीतने पर चेल्सी को मिली कुल इनामी राशि से आधे से भी कम है। फुटबाल विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक होगा। यह न केवल खेल के लिहाज से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी फीफा के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है।

फीफा विश्व कप 2022 की विजेता ट्राफी के साथ अर्जेंटीना की टीम ● फाइल फोटो

48 टीमों में इस तरह होगा इनामी राशि का वितरण

ग्रुप स्टेज खेलने पर	9 मिलियन डालर (81 करोड़ रुपये)
राउंड आफ 32	11 मिलियन डालर (100 करोड़ रुपये)
राउंड आफ 16	15 मिलियन डालर (135 करोड़ रुपये)
क्वार्टर फाइनल	19 मिलियन डालर (171 करोड़ रुपये)
चौथा स्थान	27 मिलियन डालर (243 करोड़ रुपये)
तीसरा स्थान	29 मिलियन डालर (261 करोड़ रुपये)
उपविजेता	33 मिलियन डालर (297 करोड़ रुपये)
विजेता	50 मिलियन डालर (451 करोड़ रुपये)

पिछले दो विश्व कप विजेताओं को इतनी इनामी राशि

- 2022 : अर्जेंटीना, 42 मिलियन डालर (379 करोड़ रुपये)
- 2018 : फ्रांस, 38 मिलियन डालर (352 करोड़ रुपये)

महिला विश्व कप से छह गुना ज्यादा इनामी राशि

2026 विश्व कप की इनामी राशि 2023 महिला विश्व कप (110 मिलियन डालर) से लगभग छह गुना ज्यादा है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने पहले पुरुष और महिला विश्व कप में समान इनामी राशि का लक्ष्य तय किया था, जिसकी दिशा में अगला महिला विश्व कप 2027 में ब्राजील में होगा।

13 अरब डालर (1,17,334 करोड़ रुपये) है फीफा की अनुमानित आय (2023–26) है, जो पिछले चार वर्षों की आय से कहीं अधिक है

चेल्सी को क्लब विश्व कप जीतने पर मिले 1128 करोड़

क्लब फुटबाल विश्व कप की कुल इनामी राशि एक अरब डालर (9027 करोड़ रुपये) थी। चेल्सी को खिताब जीतने पर 125 मिलियन डालर (1128 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिली थी। फीफा के अनुसार, राष्ट्रीय टीम और क्लब टूर्नामेंटों के लिए इनामी राशि का वितरण माडल अलग-अलग है। क्लबों के खर्च, वेतन राष्ट्रीय टीमों की तुलना में अधिक होते हैं।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

पीएसजी बना इंटरकांटिनेंटल कप विजेता

फुटबाल डायरी

दोहा, एपी : मात्वेई सफोनोव ने पेनाल्टी शूटआउट में लगातार चार पेनाल्टी बचाईं जिससे पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने इंटरकांटिनेंटल कप फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल में फ्लेमेंगो को हराकर वर्ष 2025 में अपनी छठी ट्राफी जीती। निर्धारित और अतिरिक्त समय के बाद स्कोर 1-1 से बराबर था जिसके बाद पीएसजी ने पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से जीत हासिल की। मैच खत्म होते ही रूसी गोलकीपर सफोनोव को उनके साथियों ने हवा में उछाल दिया।

पीएसजी ने इस तरह से वर्ष 2025 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। उसने इससे पहले डेस चैंपियंस, फ्रेंच लीग, फ्रेंच कप, चैंपियंस लीग और यूएफा सुपर कप जीता था। खिवचा क्वारात्सखेलिया ने 38वें मिनट में पीएसजी को बढ़त दिलाई, जिसके बाद 62वें मिनट में जोर्जिन्हो ने पेनल्टी को गोल में बदलकर ब्राजील के क्लब फ्लेमेंगो को बराबरी दिलाई।

खिताब जीतने के बाद ट्राफी के साथ जश्न मनाती पीएसजी टीम ● एएफपी

एमबापे के दो गोल से मैड्रिड की रोमांचक जीत: रीयल मैड्रिड ने बुधवार रात कोपा डेल रे मुकाबले में स्टार काइलियन एमबापे के दो गोल की बदौलत तीसरे-डिवीजन क्लब तालावेरा को 3-2 से हरा दिया। एमबापे ने 41वें मिनट में पेनाल्टी को गोल में बदला और दूसरे हाफ के अंत में एरिया के बाहर से शाट लगाकर गोल करते हुए जीत पक्की की। तालावेरा के लिए 80वें मिनट में नहुएल अरोयो और दूसरे हाफ के स्टापेज टाइम में गोंजालो डि रेनजो के गोल ने मैड्रिड की बढ़त कम की।

****

दिल से

कलाकार होने के अपने फायदे

अभिनेता कुणाल खेमू के अनुसार नए साल के संकल्पों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जीवन की कई अन्य चीजें। इन दिनों वह नजर आ रहे हैं नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सिंगल पापा में...

साल 2025 खत्म होने को है, ऐसे में नए साल को लेकर कुछ लोगों के मन में कई उम्मीदें होती हैं। हालांकि अभिनेता कुणाल खेमू का सोच अलग है। उनका कहना है कि हर साल जीवन का एक अहम अध्याय होता है। मेरे लिए इतना काफी है कि मैं इस साल भी जिंदा हूं। अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है, नए तरह का काम मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो सिंगल पापा में मुख्य भूमिका में दिखे कुणाल आगे कहते हैं कि इस शो को करने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा है कि कुछ नया कर सकता हूं। कई बार कलाकारों के पास इतनी सहूलियत नहीं होती कि वे नया काम चुनें या जोखिम लें। वे एक जैसा काम करते रह जाते हैं। खैर, फिर भी आम लोगों के मुकाबले एक कलाकार की जिंदगी ऐसी होती है कि उन्हें कुछ न कुछ नया करने को मिलता है। कलाकार होने के अपने फायदे हैं। एक ही जिंदगी में, हम कई जिंदगियां जी लेते हैं।

कुणाल आगे कहते हैं कि सिंगल पापा इकलौता ऐसा कंटेंट है, जिसके पहले एपिसोड की कहानी सुनते ही मैंने हां कर दी थी। औपचारिकता पूरी करने के लिए मैंने बाकी स्क्रिप्ट बाद में पढ़ी, लेकिन मैं जानता था कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा। इस शो में पैरेंटिंग और गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में सरलता से बात की गई है। कई बार सीन देखने के बाद पता चलता था कि इतनी बड़ी बात कह दी है। निजी जीवन में पिता होने का अनुभव शो में उन्हें कितना काम आया? इस पर वह कहते हैं कि हम जैसे आज अपने बच्चे को परवरिश दे रहे हैं, उससे हमारी परवरिश अलग रही है। मैं यह नहीं कहूंगा कि समय बदल गया, तो हमें बदलने की जरूरत है। शो में जेंटल पैरेंटिंग (बच्चे को प्यार से पालना-पोसना) की बात की गई है। पैरेंटिंग निजी चीज होती है, जो तरीका आपके लिए काम करता है, जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी करे। इंटरनेट पर सलाह देने के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन आपको खुद देखना होगा कि आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है। जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते हैं, वे आपकी जिम्मेदारी हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि मेरी जेंटल पैरेंटिंग की वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया है।

प्रियंका सिंह

सवाल-जवाब

मन का काम कर सकें यही है असल ताकत

सस्पेंस, परतदार किरदार और यथार्थ की गहराई को लेकर गढ़ी गई फिल्म 'रात अकेली है' की रिलीज के करीब पांच वर्ष बाद निर्देशक हनी त्रेहन फिर दर्शकों को उसी अंधेरी और बेचैन दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हैं। 'रात अकेली है 2' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर जटिल यादव के रूप में लौट रहे हैं, इस बार उन्हें सुलझानी है बंसल परिवार की मर्डर मिस्ट्री। फिल्म में उनके साथ हैं चित्रांगदा सिंह। दोनों से स्मिता श्रीवास्तव की बातचीत के अंश:

नवाजुद्दीन सिद्दीकी

चित्रांगदा सिंह

● फोटो संजीव कुमार

डार्क रोल निभाना ज्यादा कठिन है या उससे निकलना ?

चित्रांगदा : नवाज तो डार्क रोल के मास्टर हैं। मुझे लगता है कि डार्क रोल में उतरना मुश्किल है। सेट पर आप हंस रहे हैं, बात कर रहे होते हैं। ऐसे में कैमरा आन होते ही पात्र की मानसिक गहराई में उतरना चुनौती होती है। हालांकि उससे निकलना थोड़ा आसान लगता है। नवाजुद्दीन : पात्र से निकलना भी मुश्किल होता है और उसे निभाना भी। मैंने डार्क से ज्यादा ग्रे किरदार किए हैं। कुछ किरदार साथ रह जाते हैं। निजी तौर पर रमन राघव 2.0 का पात्र थोड़ा भारी पड़ गया था, लेकिन फिल्म रात अकेली है की जब तक शूटिंग चली, मुझे जटिल के पात्र में रहना बहुत अच्छा लगा। दो-तीन महीने किसी पात्र की जिंदगी जीना बहुत खूबसूरत अनुभव होता है।

रात अकेली है 2 का पोस्टर

● इस साल की सबसे अच्छी बात क्या रही ?

चित्रांगदा : फिल्म रात अकेली है 2 में मीरा का जो पात्र मिला है वैसी भूमिकाएं निभाने का मौका अक्सर नहीं मिलता है। मीरा एक प्रभावशाली परिवार से है। सत्ता, संवेदनशीलता और व्यक्तिगत संघर्ष की झलक पात्र में दिखेगी। अब महिला को केंद्र में रखकर पात्र लिखे जाते हैं। वे बहुत परतदार पात्र होते हैं। फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहन ने कहा कि अपनी सीमाओं से आगे आकर इस पात्र को निभाओ, इसलिए लगता है कि इस साल की बेस्ट चीज रहा ये पात्र।

नवाजुद्दीन : मेरे लिए यह फिल्म खास है। फिल्म करने के बाद से ही इसकी रिलीज का इंतजार था। इसकी कहानी मूल कहानी से अलग है।

● पात्र को जीने का आपका तरीका क्या रहा?

चित्रांगदा : एक अभिनेता के अंदर एक आदत बन जाती है कि कैसे रोना है, कैसे हंसना है, लेकिन हनी ने मुझे सिखाया कि जब आप किसी इमोशन या शाट को बार-बार करते बोर हो जाते हैं, तो उसके आगे भी फोकस कैसे बनाए रखना है वर्ना मानसिक ब्लाक आ जाता है। उससे आगे जाकर परफार्म करना मैंने हनी से सीखा।

● नवाजजुद्दीन से- एक ही पात्र को बार-बार निभाना आसान होता है...

नहीं, यह थोड़ा जोखिम भरा होता है। अगर आपने सोचा कि यह तो मैं कर ही लूंगा, तो वही किरदार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हर बार आपको शून्य से शुरुआत करनी होती है। आधार जरूर होता है, लेकिन नए पात्रों से आपका रिश्ता, उनकी प्रतिक्रिया सब कुछ बदल जाता है। उसी हिसाब से आपकी परफार्मेंस भी बदलती है।

● आप दोनों तो पहले भी साथ काम करने वाले थे, लेकिन विवाद हो गए और फिल्म नहीं की...

चित्रांगदा : मैं हमेशा से नवाज के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं हो पाया। हमारी इक्वेशन कभी खराब नहीं रही। कई बार फिल्में किसी वजह से पूरी नहीं हो पातीं, लेकिन लोगों के लिए यह कह देना आसान है कि दो कलाकारों के बीच समस्या थी। मैंने हनी से भी यही कहा था कि मैं उनके साथ काम करना चाहती हूं। मैं कई सीन में अटकी थी, तो नवाज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।

● शाट में अटकने पर वापस बार-बार परफार्म करना कठिन होता होगा ?

नवाजुद्दीन : एकाध शाट में हर एक कलाकार अटकता है, लेकिन फाइनल शाट जो आता है वो बहुत ही मजेदार होता है।

● जटिल यादव पुलिस में है और मीरा बंसल मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े परिवार से, पावर के मायने आपके लिए क्या हैं ?

चित्रांगदा : मुझे ऐसा लगता है पावर यह है कि आप वो काम कर सकें, जो आप करना चाहते हैं। काम करने का मन है तो करो, नहीं है तो मत करो, जैसे चाहो वैसी जिंदगी जियो। यही असली ताकत है वर्ना ताकत की कोई सीमा नहीं है कि आप किससे क्या करवा सकते हो वो अलग चीजें हैं।

नवाजुद्दीन : यह बेहतरीन जवाब है। हमारे लिए पावर यही है कि हम अपने मन का काम कर सकें वर्ना ताकतवर लोग अक्सर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं।

● इस साल सितारों की लंबी चौड़ी टीम, आठ घंटे की शिफ्ट और फिल्मों में हिंसा के मुद्दे छाए रहे। आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर ?

नवाजुद्दीन : ये सब चीजें आपसी समझ पर निर्भर करती हैं। अगर हिंसा सिर्फ सनसनी के लिए दिखाई जाए, तो गलत है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट की मांग है, तो उसे समझना होगा।

चित्रांगदा : मेरा मानना है कि जहां ऐसा लगता है कि कलाकारों से बहुत काम कराया जा रहा है, तो वहां पर फिल्मकारों के साथ बातचीत होनी चाहिए। अगर फिल्मकारों को लगता है कलाकारों की टीम लंबी चौड़ी है तो कलाकारों को समझना होगा। सिनेमा में सहयोग से काम बेहतर हो पाता है। यह एकतरफा हो ही नहीं सकता। आप किसी एक पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। अच्छा काम तभी निकलता है जब सब मिलकर कर काम करें।

बाक्स आफिस रिपोर्ट

विवादों से बेअसर धुरंधर

धुरंधर फिल्म घरेलू बाक्स आफिस पर 450 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी है। इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताए जाने को लेकर विवाद भी हुए, पर दर्शकों का आकर्षण नहीं थमा। सिनेमाघरों में फिल्म की कमाई जारी है। फिल्म की सफलता की वजहों को टटोलने का प्रयास किया प्रियंका सिंह ने...

इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहरण करके कंधार ले जाए जाने और यात्रियों की सुरक्षा के बदले भारतीय जेलों में बंद कुख्यात आतंकवादियों की रिहाई की सौदेबाजी के बाद शुरू होता है आपरेशन धुरंधर। पाकिस्तान के कराची के ल्यारी इलाके में राजनीतिक सरपरस्ती में फलते-फूलते बाबू डकैत और रहमान डकैत के गैंगवार, बेहिसाब हिंसा, भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के इरादे से जाली नोट भेजने, संसद पर हमला और मुंबई पर आतंकी हमलों के लिए अजमल कसाब को भारत भेजे जाने के षड्यंत्रों की परतें धीरे-धीरे खुलती हैं। रणवीर सिंह का दमदार अभिनय और एक्शन, रहमान डकैत के पात्र में अक्षय खन्ना हों या फिर आपस में ही लड़ मरने वाले पाकिस्तानी पुलिस, माफिया और राजनेता, आदित्य धर की काल्पनिक कहानी का असर ऐसा कि फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों की तालियां मिलीं तो कुछ लोगों ने वीभत्स हिंसा, वास्तविक घटनाक्रम को काल्पनिक कहानी में मनमाने अंदाज में पेश किए जाने को लेकर सवाल भी खड़े किए। फिल्म को पाकिस्तान विरोधी कहा गया। जवाब में पाकिस्तान ने गैंगवार के लिए कुख्यात कराची के ल्यारी इलाके की छवि सुधारने के उद्देश्य से 'मेरा ल्यारी' नामक फिल्म बनाने की घोषणा कर दी। सवाल यह है कि विवादों के बावजूद धुरंधर रिकार्ड क्यों बना रही है?

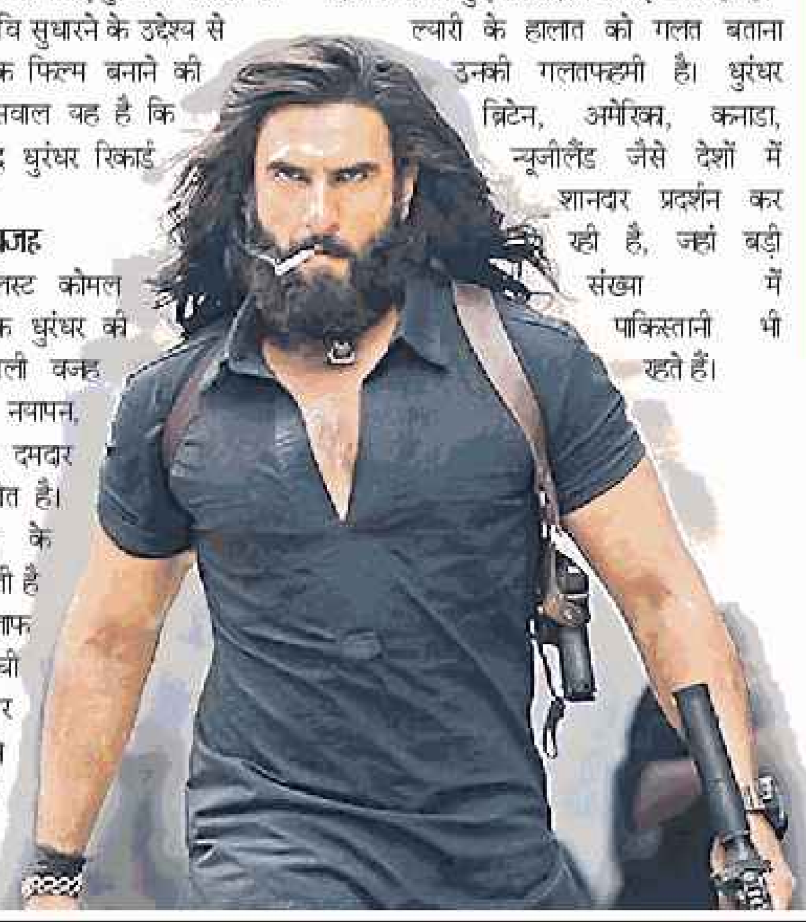

कहानी है असली वजह

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा कहते हैं कि धुरंधर की सफलता की असली वजह कहानी का नयापन, प्रभावशाली प्रस्तुति, दमदार अभिनय और संगीत है। धुरंधर पाकिस्तान के एंगल से यह दिखाती है कि भारत के खिलाफ साजिशें कैसे रची जाती हैं। कई बार विवादों की वजह से दर्शक भी फिल्म देखने पहुंच जाते हैं।

पाकिस्तान क्यों बेचैन

फिल्म समीक्षक और बिजनेस एनालिस्ट तरण आदर्श का कहना है कि पाकिस्तान की बेचैनी की वजह यह है कि धुरंधर उनके सिस्टम का पर्दाफाश करते हुए जबरदस्त कमाई कर रही है। ल्यारी के हालात को गलत बताना उनकी गलतफहमी है। धुरंधर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों में शानदार प्रदर्शन कर रही है, जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भी रहते हैं।

विवादों की फेहरिस्त

- बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, कतर और सऊदी अरब सहित छह खाड़ी देशों ने फिल्म को पाकिस्तान विरोधी कंटेंट बताते हुए रिलीज की अनुमति नहीं दी।
- पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने कराची की अदालत में याचिका दायर कर पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों और पार्टी के झंडे के उपयोग पर आपत्ति की।
- बलूच समुदाय ने रहमान डकैत और ल्यारी इलाके को गैंगवार और अपराध के प्रतीक के रूप में दिखाने पर नाराजगी जाहिर की।

पाकिस्तान द्वारा घोषित 'मेरा ल्यारी' फिल्म को लेकर कोमल नाहटा कहते हैं कि उसे देखेगा कौन? उनके देश में भी हमारी फिल्में पायरेसी पर देखी जाती हैं। वहां पर जब फिल्म रिलीज हुई, तो कई लोगों ने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन वहीं से शानदार कलेक्शन आया। वहीं तरण का मानना है कि धुरंधर 2 पर विवादों का असर नहीं पड़ेगा। फिल्म अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगी और निर्देशक आदित्य धर की रणनीति बिल्कुल सटीक है कि तवा गरम हो, तो रोटी जल्दी सिंकती है।

इनसे मिलिए

लक्ष्य को डायरी में लिखती हैं अलीशा

कई बार अगर किसी से अपनी बातें न कहनी हों, तो उसे डायरी में लिखना अच्छा होता है। यह मानना है अभिनेत्री अलीशा पंवार का। टीवी से अब अलीशा डिजिटल प्लेटफार्म की ओर बढ़ चली हैं। अपनी नई वेब सीरीज बिन्नी की किताब में वह अपनी इच्छाओं को एक डायरी में लिखती हैं। क्या कभी वास्तविक जीवन में उन्होंने डायरी लिखी है? इस पर अलीशा हंसते हुए कहती हैं कि हां, कालेज के दिनों में लिखा था कि सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए। खैर, अब तो कभी कभार समय मिलता है, तो यह लिखती हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है। टीवी से डिजिटल प्लेटफार्म की ओर बढ़ने को लेकर अलीशा कहती हैं कि मैं हमेशा टीवी गर्ल रहूंगी। मैं अभिनय इसलिए नहीं कर रही हूं कि पैसा चाहिए। मुझे अपने काम से प्यार है। वेब सीरीज मुझे पहले भी कई बार आफर हुआ है, लेकिन बोल्ड कांसेप्ट की वजह से नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उसमें सहज नहीं हूं। बिन्नी की किताब की कहानी बोल्ड है, लेकिन यह महिलाओं को स्वयं को लेकर नया दृष्टिकोण देगी।

प्रियंका सिंह

आज का भविष्यफल- 19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : पौष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या।
आज का राहुकाल : प्रात : 09 : 00 से 10 :30 बजे तक।
आज का दिशाशूल : पश्चिम
आज का पर्व एवं त्योहार : स्नानदान की अमावस्या।
विशेष : अमावस्या तिथि वृद्धि

कल 20 दिसंबर, 2025 का पंचांग

कल का दिशाशूल : पश्चिम
कल का पर्व एवं त्योहार : स्नानदान की अमावस्या।
विशेष : शुक्र धनु राशि में, अमावस्या तिथि वृद्धि।
विक्रम संवत 2082 शके 1947 दक्षिणायण, दक्षिणगोल, हेमंत ऋतु पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या 07 घंटे 13 मिनट तक, तत्पश्चात मूल नक्षत्र 25 घंटे 22 मिनट तक, तत्पश्चात पूर्वाआषाढ़ा नक्षत्र गण्ड योग 16 घंटे 17 तक, तत्पश्चात वृद्धि योग धनु में चंद्रमा।

मेष : शुक्र का परिवर्तन सुखद होगा। ससुराल पक्ष का सहयोग रहेगा। जीवन सुखमय होगा।

वृष : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे।

मिथुन : दांपत्य सुखमय होगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

कर्क : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवनसाथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा।

सिंह : प्रयास फलीभूत होंगे। व्यावसायिक योजना सार्थक होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

कन्या : निर्माण कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी। रिश्तों में निकटता आएगी।

तुला : जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। धन, कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन, कीर्ति में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

धनु : बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। योजना फलीभूत होगी।

मकर : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संतान के कारण चिंतित रहेंगे। आर्थिक मामलों में सचेत रहें।

कुंभ : महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन की वृद्धि होगी।

मीन : शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। कार्य संपन्न होगा।

वर्ग पहेली- 3194

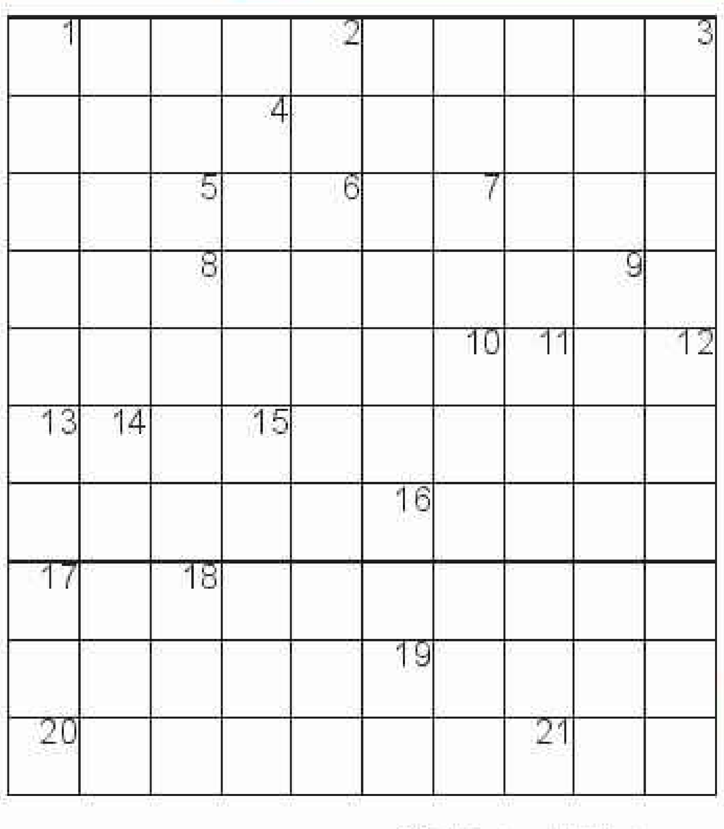

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं

1. नजदीक, पास (3)।
2. नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कृति है- बाबा .... (6)।
4. जेल, बंदीगृह (2)।
6. व्यर्थ की बात (4)।
8. काम-धंधा, नौकरी- ... (3)।
10. कवच-कुंडल दान कर कर्ण सबसे बड़ा ... बना (4)।
13. टीस उठना (4)।
16. 'मैं दुनिया भुला दूंगा, तेरी चाहत में...' - इस फिल्म का गाना है (4)।
18. बोलने में अटकना (4)। 19. समय, मौत (2)।
20. नरेंद्र बेदी द्वारा निर्देशित 1972 में बनी एक फिल्म (3,3)।
21. तरक्की (3)।

ऊपर से नीचे

1. कसमसाने का भाव (6)।
2. समानता का भाव (4)।
3. शिथिल होना, धीमा पड़ना (3)।
5. एकाएक, हठात (4)।
7. वादा (3)। 9. न्यूजीलैंड का नहीं उड़ सकने वाला पक्षी (2)। 11. नमक के स्वाद का (4)। 12. इंग्लैंड की क्रांति को ...भी कहा गया (2,2,2)। 14. नाड़ी, रग (2)।
15. व्यर्थ, बिना मतलब का (3)।
16. टालमटोल (4)।
17. पंकज, जलज (3)।

कल का हल

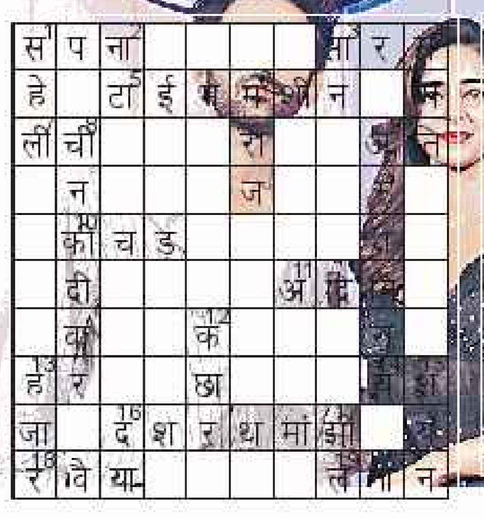

सुडोकू- 3194

कल का हल

4	5	6	9	8	1	2	7	3
8	3	1	2	7	4	6	5	9
2	9	7	3	6	5	8	4	1
7	8	3	4	2	6	9	1	5
1	4	9	5	3	8	7	6	2
5	6	2	7	1	9	3	8	4
9	7	5	6	4	3	1	2	8
3	2	8	1	5	7	4	9	6
6	1	4	8	9	2	5	3	7

राष्ट्रीय फलक

दक्षिणा पर प्रहार की बारी, इसीलिए हटाए थे बांकेबिहारी मंदिर से भंडारी

जागरण संवाददाता, वृंदावन

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने वाले भोग भंडारी के प्रवेश पर रोक को लेकर हुआ हंगामा आम नहीं है। इसके पीछे खास वजह है। इस आदेश से उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने भंडारियों की गलत प्रवृत्ति पर चोट की थी। भंडारी श्रद्धालु से प्रसाद के साथ दी जाने वाली दक्षिणा को दानपात्र में न डालकर अपने पास रख लेते हैं। हंगामे के दबाव में अभी इस व्यवस्था को वापस ले लिया गया है, मगर मंदिर में रेलिंग व्यवस्था शुरू होने के बाद माला प्रसाद अर्पित करने की वैकल्पिक व्यवस्था लागू होना निश्चित माना जा रहा है।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से स्थिति बिगड़ रही है। बुधवार को समिति ने व्यवस्था बनाने के लिए सेवायतों की सहायता के लिए तैनात भोग भंडारी हटा दिए। ये भोग भंडारी श्रद्धालुओं से प्रसाद लेकर ठाकुरजी को अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं से जो दक्षिणा आती है, उसे अपने पास रख लेते हैं। प्रबंधन समिति ने इसी व्यवस्था को लेकर भोग भंडारी हटा दिए थे। श्रद्धालु फूल-माला अर्पित नहीं कर पाए, लेकिन दक्षिणा भोग भंडारी न होने पर मंदिर के दानपात्र में डालते रहे। सेवायतों ने भंडारी हटाने पर हंगामा किया और करीब तीन घंटे बाद फिर से भंडारी को तैनात किया गया।

मथुरा : वृंदावन स्थित ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन करते श्रद्धालु। जागरण

बैनर प्रदर्शित करने के मामले टीटीडी करेगा कानूनी कार्रवाई

तिरुपति, प्रेट्र : तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने गुरुवार को कहा कि वेंकटेश्वर मंदिर के पास बैनर प्रदर्शित करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के कुछ लोगों ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के पास अन्नाद्रमुक नेताओं की तस्वीरों वाले बैनर प्रदर्शित किए हैं, जो मंदिर के नियमों का उल्लंघन है।

यह कार्रवाई इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद की जा रही है। इस वीडियो में दो युवक एक बैनर के साथ दिख रहे हैं। बैनर में दावा किया गया है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के आशीर्वाद से अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी पलानीसामी 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में आएंगे। बैनर में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता सहित अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें हैं। बैनर प्रदर्शित करने के अलावा संबंधित व्यक्तियों ने रील भी रिकार्ड की और उन्हें इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट किया।

****

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मेवाड़ राजपरिवार का संपत्ति विवाद

जासं, उदयपुर

उदयपुर के पूर्व राजपरिवार में दशकों से चला आ रहा संपत्ति विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को चुनौती देते हुए दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। यह विवाद अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और पुत्री पद्मजा कुमारी परमार के बीच सिटी पैलेस, एचआरएच होटल्स ग्रुप सहित अन्य बहुमूल्य संपत्तियों के अधिकार को लेकर है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले से जुड़े सभी मुकदमों को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 11 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ वर्तमान में मेवाड़ राजपरिवार के उत्तराधिकारी और एचआरएच ग्रुप आफ होटल्स के प्रमुख हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मुंबई हाई कोर्ट में लंबित मामलों को राजस्थान हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की याचिका दायर की थी, जबकि पद्मजा कुमारी परमार ने जोधपुर बेंच राजस्थान हाई कोर्ट से मामलों को बाम्बे हाई कोर्ट भेजने की मांग की थी।

पुराना व जटिल है विवाद

मेवाड़ के पूर्व महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ के तीन संतानें थीं- महेंद्र सिंह मेवाड़, अरविंद सिंह मेवाड़ और योगेश्वरी कुमारी। वर्ष 1983 में भगवत सिंह मेवाड़ ने पारिवारिक संपत्तियों को बेचने और लीज पर देने का निर्णय लिया, जिसका बड़े पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ ने विरोध किया और अदालत का रुख किया। इसके बाद भगवत सिंह मेवाड़ ने संपत्ति और ट्रस्ट से जुड़े निर्णयों की जिम्मेदारी छोटे पुत्र अरविंद सिंह मेवाड़ को सौंप दी।

महाकाल लोक परिसर भूमि अधिग्रहण मामले में याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उज्जैन में महाकाल लोक परिसर के पार्किंग क्षेत्र की जगह बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 11 जनवरी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। सात नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उज्जैन में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए निर्देश देने का आग्रह करने वाली याचिका निरस्त कर दी गई थी। यह मस्जिद भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद हटा दी गई थी। लगभग 200 साल पहले स्थापित तकिया मस्जिद को जनवरी में उस भूमि के अधिग्रहण के बाद हटा दिया गया था, जिस पर यह बनी थी।

सेना ने गोवा, दमन व दीव को पुर्तगाल से मुक्त कराया

1961 में आज ही आपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा, दमन व दीव को पुर्तगाल से मुक्त कराया था। पुर्तगाल ने वर्ष 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। शुरुआत में केंद्रशासित प्रदेश रहने के बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।

बलिदान हुए बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां व रोशन सिंह

1927 में आज ही महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजों ने अलग-अलग जेलों में फांसी दे दी थी। तीनों क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

झारखंड की लेडी टार्जन कही जाती हैं जमुना टुडू

जमुना टुडू का जन्म 1980 में आज ही ओडिशा में हुआ था। 1998 में शादी के बाद झारखंड के मुतुरखाम गांव गईं और वहां वन माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ काटने की स्थिति देखी। इस दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया। परिवार के विरोध के बावजूद, उन्होंने गांव की महिलाओं को एकजुट कर वन सुरक्षा समिति का गठन किया। इस समिति ने अवैध कटाई के खिलाफ संघर्ष किया, जिसमें उन्हें कई बार जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा। फिर भी, जमुना ने हार नहीं मानी और उन्होंने 50 हेक्टेयर जंगल को विनाश से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

छोटी आंत से माइक्रोबियल सैंपल लेने को डिवाइस तैयार

आइआइटी-एम्स की उपलब्धि ▶ छोटी आंत से सीधे ले सकेगी बैक्टीरिया के नमूने, समय और लागत में बचत

आंतों, मेटाबालिज्म और पोषण से जुड़ी बीमारियों की पहचान में होगी मददगार

अनूप कुमार सिंह ● जागरण

नई दिल्ली : आइआइटी व एम्स दिल्ली के विज्ञानियों ने एक ऐसी निगलने योग्य कैप्सूल आकार की माइक्रोडिवाइस तैयार की है, जो सीधे मानव शरीर की छोटी आंत से बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों के नमूने एकत्र करने में सक्षम है। इसे मानव माइक्रोबायोम को समझने और आंतों से जुड़ी बीमारियों के शुरुआती निदान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस माइक्रोडिवाइस को मरीज आसानी से निगल सकता है। छोटी आंत में पहुंचने पर यह सक्रिय होकर वहां मौजूद बैक्टीरिया व जैविक तत्वों का नमूना अपने भीतर संग्रहित कर लेती है। इसके बाद यह खुद को सील कर लेती है, ताकि आंत के अलग-अलग हिस्सों के सूक्ष्मजीव आपस में न मिलें। विशेषज्ञों के अनुसार यह डिवाइस आंतों, मेटाबालिज्म और पोषण से जुड़ी बीमारियों की पहचान में मददगार होगी।

आइआइटी दिल्ली की मेडिकल माइक्रोडिवाइस एंड मेडिसिन प्रयोगशाला के प्रधान विज्ञानी प्रोफेसर सर्वेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मानव शरीर के भीतर सूक्ष्मजीवों की एक विशाल दुनिया है, जो पाचन, प्रतिरक्षा और कई बीमारियों में अहम भूमिका निभाते हैं। अब तक छोटी आंत के माइक्रोबायोम का अध्ययन करना कठिन था, क्योंकि इसके लिए एंडोस्कोपी जैसी जटिल प्रक्रियाओं या फिर मल के नमूनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो सटीक जानकारी नहीं देते थे। नई माइक्रोडिवाइस इस कमी को दूर करेगी।

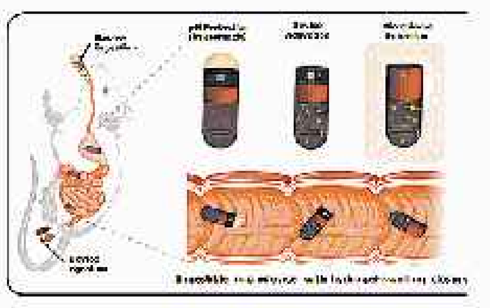

डिवाइस की छोटी आंत से बैक्टीरिया के नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया व चूहे पर इसके व्यवहार को दर्शाता रेखाचित्र: सौजन्य- आइआइटी

एम्स नई दिल्ली के गैस्ट्रोएंटरोलाजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन यूनिट के को-सीनियर विज्ञानी डा. समग्र अग्रवाल ने बताया कि छोटी आंत स्वास्थ्य और बीमारी दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस डिवाइस के आ जाने से छोटी आंत में मौजूद माइक्रोब्स और रासायनिक तत्वों की सही जानकारी मिल सकेगी, जिससे बीमारियों का जल्दी पता लगाना, पुरानी बीमारियों की निगरानी करना व अधिक असरदार उपचार विकसित करना संभव होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने इस शोध को वित्तपोषित किया है। यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल स्माल में 'ए स्माल पिल-लाइक इन्जेस्टिबल माइक्रोडिवाइस फार साइट-स्पेसिफिक माइक्रोबायोम सैंपलिंग इन द अपर जीआइ ट्रैक्ट' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अब नियामक मंजूरियों के बाद इसे क्लिनिकल उपयोग में लाने की तैयारी है, जिससे आने वाले समय में मरीजों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

कैसे आती है बाहर : छोटी आंत में पाचन के दौरान भोजन आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक लहरनुमा गति 'पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट' इसे धीरे-धीरे आगे की ओर धकेलता है। जिससे यह छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचती है। पाचन तंत्र के सामान्य मार्ग से आगे यह डिवाइस मल त्याग से बिना दर्द या अतिरिक्त बल के शरीर से बाहर आ जाती है। इसे ऐसे तैयार किया गया है कि इसे बाहर आने के बाद आसानी से पहचाना व निकाला जा सके।

नियंत्रित रिकवरी : मरीज को पहले से बताया जाता है कि 24-72 घंटे के भीतर मल त्याग के दौरान यह निकलेगी। इसके बाद मल को विशेष स्टूल-कलेक्शन किट में एकत्र किया जाता है। इसकी सतह चिकनी और अलग रंग की होती है जो कि पहचानी जा सकती है।

कोहरे में अठखेलियां करते प्रवासी पक्षी...

नई दिल्ली के यमुना बाजार के घाट पर घने कोहरे और ठंड में अठखेलियां करते प्रवासी पक्षी तथा यमुना में नौका विहार का आनंद लेते पक्षियों को दाना खिलाते पर्यटक। हर साल ये हजारों प्रवासी पक्षी हजारों मील की यात्रा करके राजधानी की गुलाबी ठंड का आनंद लेने यमुना किनारे आते है। ध्रुव कुमार

इधर-उधर

द्वीप की तटरेखा हो गई खून की तरह लाल

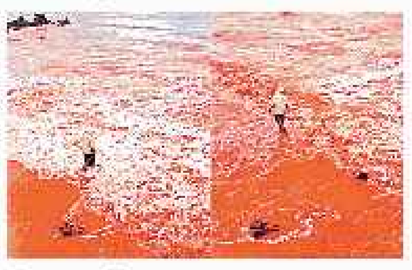

द्वीप पर भारी बारिश के बाद दिखा अद्भुत नजारा। इंटरनेट मीडिया

तेहरान, एजेंसी: ईरान के होर्मुज द्वीप की तटरेखा रातोंरात खून जैसे लाल रंग में बदल गई। भारी बारिश के बाद हुई इस अद्भुत प्राकृतिक घटना ने हलचल मचा दी। इस घटना के पीछे का वैज्ञानिक कारण द्वीप की अनूठी भूविज्ञान संरचना है। होर्मुज द्वीप आयरन आक्साइड, विशेष रूप से हेमेटाइट से समृद्ध है, जो मिट्टी व चट्टानों को गहरा लाल रंग देता है। जब बारिश का पानी द्वीप से रिसता है, तो यह आयरन आक्साइड के कणों को घोलकर तट तक ले जाता है।

सीएफएस में वैस्कुलर व इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी का पता चला

नई दिल्ली, प्रेट्र : क्रानिक थकान सिंड्रोम (सीएफएस) से पीड़ित लोगों के रक्त प्रोटीनों के विश्लेषण ने रक्त वाहिकाओं (वैस्कुलर) और प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) की संतुलित स्थिति में व्यवधान के प्रमाण दिखाए हैं। शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा और रक्त प्रवाह नहीं मिल पाता है। शोध बताते हैं कि टी-कोशिकाओं और रक्त प्रवाह नियंत्रण में दिक्कत, माइटोकान्ड्रियल ऊर्जा उत्पादन में कमी और इम्यून सिस्टम के मेटाबोलिज्म में गड़बड़ी इस जटिल बीमारी के मुख्य कारण हैं, जो शरीर के कई प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। जर्नल सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित निष्कर्ष कई जैविक प्रणालियों में असामान्यताओं की ओर इशारा करते हैं जो क्रानिक थकान सिंड्रोम (सीएफएस) वाले लोगों में एक साथ मौजूद होती हैं, जिससे पता चलता है कि यह स्थिति जैविक रूप से कितनी जटिल है।

- ▶ **शोध टीम ने निदान मानदंडों को पूरा करने वाले 61 लोगों के रक्त के नमूनों की तुलना स्वस्थ प्रतिभागियों से की**
- ▶ **क्रानिक थकान सिंड्रोम एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिससे पूरे शरीर में ज्यादा थकान होती है जो आराम करने से भी ठीक नहीं होती**

प्रतीकात्मक

61 लोगों के रक्त नमूनों की जांच : आस्ट्रेलिया के मैक्वेरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में की गई इस अध्ययन में यह भी देखा गया कि सफेद रक्त कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन में कमी आई है। टीम ने सीएफएस के निदान मानदंडों को पूरा करने वाले 61 लोगों के रक्त के नमूनों की तुलना स्वस्थ प्रतिभागियों के नमूनों से की। मायल्जिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस (एमई/सीएफएस) के नाम से भी जानी जाने वाली क्रानिक थकान सिंड्रोम एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिससे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा थकान होती है जो आराम करने से भी ठीक नहीं होती, जिसके कारण नींद, मूड और ध्यान लगाने में दिक्कत होती है। मैक्वेरी मेडिकल स्कूल में शोध साथी और प्रमुख लेखक बेंजामिन हेंग ने कहा कि हमें पता है कि क्रानिक थकान सिंड्रोम में एक विषम रोग है जिसमें कई विभिन्न जैविक प्रणालियों में असामान्यताएं होती हैं, लेकिन इन गड़बड़ियों का एक ही मरीज में एक साथ शायद ही कभी अध्ययन किया गया है।

'ऊर्जा तनाव' का संकेत : हेंग ने कहा कि इन असामान्य प्रणालियों के बीच संभावित अंतःक्रियाएं यह निर्धारित करने में योगदान कर सकती हैं कि रोग कैसे क्लिनिकली प्रकट होता है। क्रानिक थकान सिंड्रोम के रोगियों की सफेद रक्त कोशिकाओं में 'ऊर्जा तनाव' का संकेत मिला। एडेनोसिन मोनोफास्फेट (एएमपी) और एडेनोसिन डाइफास्फेट (एडीपी) के उच्च स्तर, जो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट (एटीपी) के उत्पादन में कमी को दर्शाते हैं, जो कोशिकाओं के भीतर एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। एएमपी और एडीपी ऊर्जा रिलीज के उत्पाद हैं और कम ऊर्जा का संकेत देते हैं। इन्हें एटीपी में रीसाइकिल किया जाता है, जो कोशिकीय गतिविधियों को शक्ति प्रदान करता है और मांसपेशियों के संकुचन व जटिल अणुओं जैसे डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक है। शोधकर्ताओं ने सीएफएस से पीड़ित लोगों में कम परिपक्व टी-लिम्फोसाइट्स, डेंड्रिटिक कोशिकाएं और नेचुरल किलर सेल्स की प्रवृत्ति पाई। एंडोथेलियम रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत से संबंधित प्रोटीनों के स्तर उच्च थे, जबकि परिसंचारी इम्युनोग्लोबुलिन संबंधित प्रोटीनों के स्तर कम थे। इसके परिणाम एमई/सीएफएस में रक्त वाहिकाओं और प्रतिरक्षा संतुलन में व्यवधान को उजागर करते हैं।

मस्तिष्क के हिप्पोकैंपस में कोशिकाएं दूरी मापने में करती हैं मदद

अनुसंधान

चूहों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि मस्तिष्क के हिप्पोकैंपस में मौजूद कोशिकाएं किसी व्यक्ति को तय की गई दूरी का पता लगाने में कैसे मदद करती हैं। ये कोशिकाएं, स्मृति और दिशा-निर्देश दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष अल्जाइमर रोग के शुरुआती चरणों को समझने में सहायक हो सकते हैं, जहां रोगियों को दूरी और समय का अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। अमेरिका के मैक्स प्लैंक फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट फार न्यूरोसाइंस के शोधकर्ताओं ने चूहों को एक निश्चित दूरी तक दौड़ने का प्रशिक्षण दिया, जहां कोई दृश्य चिह्न नहीं थे। चूंकि वातावरण में बाहरी संकेतों की कमी थी, इसलिए चूहों के लिए अपनी गतिविधियों पर नजर रखना ही यह अनुमान लगाने का एकमात्र तरीका था कि उन्होंने कितनी दूरी तय की है। टीम ने इस दौरान हिप्पोकैंपस में न्यूरान्स की विद्युत गतिविधि का अवलोकन किया। नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक और शोध समूह के प्रमुख यिंगक्सू वांग ने कहा, "इस अध्ययन में हमने अंधेरे में चलने जैसी स्थितियों की नकल करने के लिए यथासंभव संवेदी संकेतों को हटा दिया। इन परिस्थितियों में हमने पाया कि केवल कुछ ही हिप्पोकैंपस कोशिकाओं ने एक विशिष्ट स्थान या एक विशिष्ट समय का संकेत दिया।" इस अवलोकन ने टीम को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाकी न्यूरान्स क्या कर रहे थे। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

सैफ व सादिया हटे, तो सनी को मिला शालिनी का साथ

फिल्म महाराज में शालिनी ने पाई थी खूब सराहना। @shalzp)

अक्सर देखा जाता है कि फिल्म बनकर पूरी होने तक उसके कलाकारों में अनिश्चितता बरकरार रहती हैं। निर्माता रमेश तौरानी की बेटी स्नेहा तौरानी ने साल 2020 में प्रदर्शित तथा सनी कौशल अभिनीत फिल्म भंगड़ा पा ले से निर्देशन में कदम रखा था। उसके बाद अब वह अपनी दूसरी फिल्म सनी के साथ ही बना रही हैं।

सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म में सनी के साथ फिल्म द डिप्लोमेट की अभिनेत्री सादिया खतीब तथा अभिनेता सैफ अली खान को भी अहम भूमिकाओं में कास्ट किया गया था। हालांकि, फिर डेट्स की समस्याओं के कारण सैफ और सादिया दोनों ने ही यह फिल्म छोड़ दी। जिससे शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले ही फिल्म का काम रोकना पड़ा।

हालांकि, स्नेहा ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस अनाम फिल्म की कास्टिंग पर काम दोबारा शुरू किया। जिसमें उन्हें जयेशभाई जोरदार तथा महाराज फिल्मों की अभिनेत्री शालिनी पांडे का साथ मिला। यानी अब इस फिल्म में सनी के साथ शालिनी अहम भूमिका में होंगी। सैफ की जगह किस कलाकार को कास्ट किया गया है, अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू करने की योजना है, फिलहाल इसके चरित्र कलाकारों की कास्टिंग का काम चल रहा है।

जो चीज फिल्म पर बोझ बने, उसे ठीक करना जरूरी : विक्की कौशल

पिछले काफी समय से सितारों के संग चलने वाली उनकी लंबी-चौड़ी टीम का भार निर्माताओं पर पड़ने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अब इस पर छावा फिल्म अभिनेता विक्की कौशल ने भी अपनी राय दी है। एक साक्षात्कार में विक्की ने कहा कि कोई भी चीज जो फिल्म पर खर्च का अतिरिक्त बोझ डाले, उसे ठीक करना जरूरी है। कलाकारों के लिए कई बार सेट पर जिम की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसका कारण यह होता है कि अगर वह एक्शन फिल्म है और सुबह सात बजे से लेकर शाम के सात बजे तक की शूटिंग करनी है, तो मुझे जिम जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। सुबह पांच बजे उठकर जिम करना होता है। अगर मेरा जिम, शूटिंग लोकेशन से अलग दिशा में है, तो फिर वहां जाना संभव नहीं होता है, ऐसे में जिम का सेटअप लगाने में निर्माताओं को भी दिक्कत नहीं होती है। वह इन बातों को समझते हैं। हालांकि अगर निर्माता को लग रहा है कि कलाकार के साथ इन बातों को लेकर कोई दिक्कत हो रही है, तो उन्हें इसकी चर्चा उन्हीं से सीधे तौर पर करनी चाहिए। विक्की की अगली फिल्म संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही फिल्म लव एंड वार होगी।

लव एंड वार होगी विक्की की अगली फिल्म। फाइल

फिर छोटे पर्दे पर रियलटी शो की मेजबानी करते नजर आएंगे अक्षय

हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन तथा फिल्मकार रोहित शेट्टी की तरह अब खिलाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार भी एक बार फिर छोटे पर्दे पर रियलिटी शो की मेजबानी करते नजर आएंगे। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, वह सोनी चैनल के लिए बन रहे अमेरिकी गेम शो व्हील आफ फार्च्यून के भारतीय संस्करण की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले अक्षय टीवी पर सेवन डेडली आर्ट्स विद अक्षय कुमार, फीयर फैक्टर : खतरों के खिलाड़ी, मास्टरशेफ इंडिया तथा डेयर 2 डांस जैसे रियलिटी शो की मेजबानी कर चुके हैं। गेम शो व्हील आफ फार्च्यून की शुरुआत साल 1975 में अमेरिका में हुई थी। जिसके बाद इसे कई अन्य देशों में एडाप्ट किया गया। इस शो में एक बड़े पहिए को घुमाया जाता है और उसके हिसाब से आई पहेली को सुलझाने वाले प्रतिभागियों को ईनाम दिया जाता है। गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) की सफलता के बाद सोनी चैनल ने इस शो का भारतीय संस्करण बनाने का अधिकार ले लिया है। इस शो के भारतीय संस्करण में प्रतिभागियों के तौर पर आम लोगों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां भी बतौर मेहमान शामिल होंगी।

इससे पहले कई रियलिटी शो की मेजबानी कर चुके हैं अक्षय। फाइल

पहले होगी फिल्म की शूटिंग, बाद में होंगी छुट्टियां

कहा जाता है कि अगर एक बार काम की लय बनी हुई है, तो उसे बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। शायद कुछ ऐसा ही सोचकर एनिमल और कबीर सिंह फिल्मों के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने फिलहाल अपनी और अपनी टीम की छुट्टियां रद करने का निर्णय लिया है। दरअसल, संदीप फिलहाल बाहुबली फेम अभिनेता प्रभास के साथ फिल्म स्पिरिट की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास के साथ अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और अभिनेता विवेक ओबेराय भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की शूटिंग 27 नवंबर को हैदराबाद में शुरू हुई थी। कुछ दिनों की शूटिंग के बाद संदीप की योजना थी कि क्रिसमस और नए साल शूटिंग रोककर छुट्टियों पर जाएंगे। हालांकि, अब उन्होंने शूटिंग को प्राथमिकता देते हुए छुट्टियों की योजना रद कर दी है। यानी फिल्म की टीम दिसंबर के अंत और जनवरी के शुरुआती कुछ दिनों तक फिल्म की शूटिंग करेगी। उसके बाद टीम थोड़ा ब्रेक लेगी। स्पिरिट को साल 2027 के मध्य में प्रदर्शित किए जाने की योजना है, ऐसे में संदीप इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि शूटिंग तय टाइमलाइन में पूरी हो जाए। चूंकि संदीप, इस फिल्म को वैश्विक स्तर का बनाना चाहते हैं, ऐसे में इसके पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स में भी समय लगेगा।

प्रभास के साथ फिल्म स्पिरिट की शूटिंग कर रहे हैं संदीप। फाइल

अभिनेता और अभिनेत्रियों की फीस में अब भी असमानता है

सात सवाल

कंटेंट वाले सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना चुकी अभिनेत्री राधिका आप्टे पिछले साल मां बनी हैं। उन्होंने फिलहाल सीमित प्रोजेक्ट्स पर काम करने का फैसला किया है। राधिका हाल ही में जी5 पर रिलीज फिल्म साली मुहब्बत में नजर आईं, जहां उन्होंने एक साधारण, लेकिन मजबूत महिला किरदार को पर्दे पर उतारा है। फिल्म वाह! लाइफ हो तो ऐसी! से अभिनय की शुरुआत करने वाली राधिका 23 दिसंबर को फिल्म इंडस्ट्री में अपने 20 साल भी पूरे करेंगी। उनसे हुई बातचीत के अंश।

● **जल्द ही इंडस्ट्री में आपको काम करते हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे। क्या बदलाव आए हैं?**

मैं आभारी हूं कि मुझे अच्छा काम और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं जो करना चाह रही थी, वह कर पा रही हूं। अब अभिनेत्रियों के लिए अलग-अलग पात्र लिखे जा रहे हैं। अभिनय से इतर वह अलग क्षेत्रों में भी अपना परचम लहरा रही हैं। निर्देशन और निर्माण से लेकर सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग में भी अभिनेत्रियां काम कर रही हैं। खैर, अब भी कई चीजों में बदलाव की जरूरत है। जैसे बराबरी का हक। अभिनेता और अभिनेत्रियों की फीस में अब भी असमानता है। कार्य के माहौल में अभी सुधार की जरूरत है।

● **साली मुहब्बत में आपके पात्र को सराहना मिली है, क्या प्रक्रिया रही रोल में उतरने की?**

-मैं मध्यमवर्गीय परिवार में पली बढ़ी हूं, इसलिए मैं पात्र से आसानी से रिलेट कर पाई। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यही है कि यह अलग तरह की थ्रिलर है। वरना आम थ्रिलर तेज गति से बढ़ते हैं, उसमें एक्शन होता है। इसमें ठहराव है, चीजों के बारे में धीरे-धीरे पता चल रहा है। मुझे इस तरह की फिल्में पसंद आती हैं।

● **आपका पात्र प्रकृति से बहुत प्रेम करता है। आप कितनी प्रकृति प्रेमी हैं?**

-मुझे प्रकृति के बीच रहना पसंद है। मुझे डाइविंग पसंद है। इस फिल्म को करने के दौरान मुझे खास तरह के पौधों और उनकी खूबियों के बारे में पता चला। यह नया अनुभव था।

● **इस साल आपके लिए सबसे खास क्या रहा ?**

-मेरा यह पूरा साल अपने बच्चे का ध्यान रखने में गया है। एक नया अनुभव है। इस साल मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। बाकी, मां बनने के कई चीजों को लेकर मेरा नजरिया अब बदल गया है।

● **मां बनने के बाद प्राथमिकताओं में भी बदलाव आया है?**

-नहीं, काम के मामले में मुझे ऐसा नहीं लगता है। हां, मेरी बेटी प्राथमिकता बन गई है, लेकिन मैं काम व परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हूं। मैं जानती हूं कि मैं जब काम शुरू करूंगी, तब उसे बेहतर तरीके से संभाल पाऊंगी। फिलहाल, मैं काम नहीं कर रही हूं।

● **ना जाता है कि हिंदी सिनेमा में सितारे पावर दिखाने के लिए अपने साथ लंबी-चौड़ी टीम लेकर चलते हैं। आपका क्या मानना है?**

-मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि सितारों के साथ अनावश्यक रूप से कई लोग होते हैं। मुझे सितारों की टीम पर खर्च होने वाला पैसा दे दो, इंडिपेंडेंट फिल्म बना दूंगी। हालांकि, कुछ कलाकारों को वाकई टीम और सुरक्षा की जरूरत होती है। उनका अकेले चलना संभव नहीं है। यहां पर संतुलन की जरूरत है। बाकी काम के घंटों पर भी विचार होना चाहिए। सिर्फ काम में ही पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता।

● **कलाकार फ्रेंचाइज सीरीज का हिस्सा बनना जरूरी मानते हैं। आप क्या सोचती हैं? आपकी अक्का वेब सीरीज भी आने वाली है...**

- हर प्रोजेक्ट की एक लाइफ होती है, उसे अनावश्यक खींचने का कोई मतलब नहीं होता है। वहीं कुछ कहानियां ऐसी हैं, जिसे सिर्फ एक फिल्म में समाहित नहीं किया जा सकता है। मुझे फ्रेंचाइज पसंद है। आप देखते है कि ज्यादातर दूसरा पार्ट ठीक होता है, तीसरा उससे कमतर। बहुत कम फ्रेंचाइज अपना प्रभाव छोड़ पाती हैं। ऐसे में जिस विषय पर फ्रेंचाइज बन रही है, उसमें कितनी क्षमता है, वह जानना बहुत जरूरी है।

(स्मिता श्रीवास्तव)

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' कार्तिक संग नए दोस्ताना की शुरुआत है : करण

फिल्म दोस्ताना 2 से अभिनेता कार्तिक आर्यन के अलग होने के बाद उनके और फिल्मकार करण जौहर के बीच मनमुटाव की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि, उसके बाद कार्तिक और करण एक बार फिर साथ आए और दो फिल्मों की डील साइन की। इसमें से पहली फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर गुरुवार को मुंबई में जारी किया गया। इस मौके पर पहुंचे करण काफी मजाकिया अंदाज में दिखे और कार्तिक के साथ वह दोस्ताना 2 के घटनाक्रमों पर भी चुटकी लेने से नहीं चूके। उन्होंने कहा, 'यह नए दोस्ताना की शुरुआत है। हम लोग बहुत खुश हैं कि यह फिल्म पूरी हो पाई और रिलीज हो रही है। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है।' उसके बाद कार्तिक ने भी उसी अंदाज में कहा, 'हम दोनों ने यह फिल्म पूरी कर ली और अब अंतत: यह रिलीज हो रही है। हमने सच में बाहर इस बात पर चर्चा भी की थी कि ये वाली तो अब नहीं (ठंडे बस्ते में) जाएगी। इसका नाम भी हम दोस्ताना 2 रख सकते थे, अगर फिल्म का टाइटल लंबा लग रहा है तो। मैं इस (रोमांटिक कामेडी) जानर में वापसी करके बहुत खुश हूं।'

मुंबई में फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के ट्रेलर लांच के दौरान कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे व करण जौहर। प्रेट्र

****